# चौथी दुनिया

www.chauthiduniya.com

हिंदी का पहला साप्ताहिक अख़बार

1986 से प्रकाशित | 03 जुलाई– 09 जुलाई 2017 | नई दिल्ली | हर शुक्रवार को प्रकाशित | Postal Regn. No. DL (ND)-11/6139/2015-17, RNI No. DELHIN/2009/30467


## लालू को महंगा पड़ा मोदी विरोध, आयकर ने पिटारा ही खोल दिया

# राजनीति का लालू पर हमला

लालू को मोदी विरोध महंगा पड़ा. लोकसभा चुनाव के बाद से शुरू हुआ मोदी विरोध बिहार विधानसभा के चुनाव के बाद जितना तल्ख होता गया लालू के खिलाफ कानून का घेरा उतना ही तंग होता गया. लालू के मुखर विरोध का मोदी ने मौन जवाब दिया. मोदी के जाल में लालू ऐसे फंसे कि उनका पूरा परिवार ही चपेटे में आ गया.

सरोज सिंह

बिहार के सबसे दबंग और प्रभावशाली लालू परिवार के राजनीतिक भविष्य पर कानूनी संकट खड़ा हो गया है. लालू परिवार अरबों रुपए की बेनामी सम्पत्ति मामले में फंस गया है. आयकर विभाग ने लालू परिवार की कई बेनामी सम्पत्तियां जब्त कर ली हैं और लालू की बेटी मीसा यादव समेत परिवार के अन्य सदस्यों से आयकर विभाग सघन पूछताछ कर रहा है. पूछताछ की अगली बारी पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, उनके बेटे व बिहार के स्वास्थ्य मंत्री तेजप्रताप और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की आने वाली है. मामला राजनीतिक नहीं है, कानूनी है. राजनीतिक मुद्दा रहता तो लालू उसे अपनी स्टाइल में निपट लेते, लेकिन मामला आर्थिक अपराध का है इसलिए चाहकर भी लालू कुछ करने की स्थिति में नहीं हैं. आयकर विभाग की ताबड़तोड़ कार्रवाई बता रही है कि मामला अंजाम तक पहुंचेगा. लालू और उनका परिवार बार-बार सफाई दे रहा है कि सम्पत्ति के लेन-देन में कोई अनियमितता नहीं बरती गई है. सारा लेन-देन पारदर्शी है और छानबीन में संबंधित विभाग को पूरी जानकारी दे दी जाएगी. लेकिन लालू परिवार की बेचैनी बताती है कि लेन-देन उतना भी पारदर्शी नहीं है. आयकर विभाग के अधिकारी कहते हैं कि मामला जटिल है, जो प्रमाण जुटाए गए हैं उन्हें झुठलाना लालू प्रसाद और उनके परिवार के लिए आसान नहीं होगा. आयकर विभाग की पूछताछ में मीसा भारती संतोषजनक जवाब नहीं दे पाईं. यह बात भी लालू को परेशान कर रही है.

लालू प्रसाद बार-बार दोहरा रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विरोध का स्वर सुनना नहीं चाहते, इसलिए उन्हें फंसाने की साजिश रची जा रही है. लालू कहते हैं, 'मैं ही नहीं, जो कोई भी नरेंद्र मोदी के खिलाफ बोल रहा है वह केंद्रीय एजेंसियों का शिकार हो रहा है, चाहे वह ममता बनर्जी हों या फिर पी चिंदबरम. हमलोगों को मिलकर फासीवादी ताकतों को जवाब देना होगा.' लालू प्रसाद का यह बयान कुछ हद तक राजनीतिक है और कुछ हद तक तात्विक. लालू इस समय विपक्षी एकता के अभियान में काफी सक्रिय हैं. वे इस सिलसिले में ममता बनर्जी से बात कर रहे हैं और अखिलेश यादव से भी संवाद में हैं. यूपी में अखिलेश और मायावती को एक करने के लिए भी लालू काफी पसीना बहा रहे हैं. सोनिया गांधी से लेकर शरद पवार तक से लालू के अच्छे रिश्ते हैं. 2019 की लड़ाई के लिए खासकर यूपी और बिहार में लालू प्रसाद अभी से राजनीतिक बिसात बिछाने में लगे हैं. मामला नोटबंदी का हो या फिर राष्ट्रपति के चुनाव का, लालू प्रसाद विपक्ष की आवाज बनकर उभरे हैं. लालू प्रसाद का सक्रिय विरोध भाजपाइयों को सोहा नहीं रहा है. इसलिए हर कोशिश हो रही है कि लालू प्रसाद को कानून के फंदे में ऐसे कस दिया जाए कि राजनीतिक सक्रियता का वक्त ही न मिले. लालू के खास समर्थक शिवानंद तिवारी कहते हैं, 'लालू यादव को खलनायक साबित करने का अभियान चल रहा है. कुछ अखबार भी जाने-अनजाने इस अभियान का हिस्सा बन रहे हैं. लालू परिवार पर एक हजार करोड़ रुपए की बेनामी सम्पत्ति और टैक्स चोरी की खबर प्रमुखता से छापी गई. एक हजार करोड़ रुपए की बेनामी सम्पत्ति की खबर के बीच में इनकम टैक्स विभाग के हवाले से यह लिखा गया है कि दिल्ली-एनसीआर और पटना में लालू परिवार की कई अचल सम्पत्ति जब्त की गई है. इनमें जमीन, प्लॉट और इमारतें शामिल हैं. लालू परिवार ने इन सम्पत्तियों की कीमत 9 करोड़ 32 लाख रुपए बताई है. लेकिन इनकम टैक्स विभाग के मुताबिक इन सम्पत्तियों का मौजूदा बाजार मूल्य 170 से 180 करोड़ रुपए है. दरअसल विवाद का मूल यही है. इनकम टैक्स विभाग आज का बाजार मूल्य बता रहा है. लेकिन जिस समय इन सम्पत्तियों को खरीदा गया तब इनका बाजार मूल्य 9 करोड़ 32 लाख रुपए था. यही बात लालू परिवार को साबित करनी है. देशभर में ऐसे हजारों विवाद इनकम टैक्स विभाग में चलते रहते हैं. लालू परिवार पर एक हजार करोड़ रुपए की बेनामी सम्पत्ति और कर चोरी का आरोप बेबुनियाद, आधारहीन और पूर्वाग्रह से ग्रसित है.' इसके बरक्स सुशील मोदी कहते हैं, 'कानून अपना काम कर रहा है और जिन्होंने भी गलत किया है उन्हें सजा मिलनी चाहिए. कहा जा रहा था कि भाजपा नेता केवल प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं. अब केंद्रीय एजेंसियां कार्रवाई कर रही हैं तो नीतीश कुमार खामोश क्यों हैं. आखिर तेजप्रताप और तेजस्वी यादव को मंत्रिमंडल से बाहर क्यों नहीं किया जा रहा है? भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीतीश कुमार की नीति को अब क्या हो गया? नीतीश कुमार का सत्ता मोह उन्हें तेजप्रताप और तेजस्वी के खिलाफ कार्रवाई से रोक रहा है.' बहरहाल, सूबे में अभी दोनों ही खेमों की ओर से आरोप और प्रत्यारोप का दौर जारी है.

आरोप प्रत्यारोप और कहने सुनने वाली बातों को छोड़ कर हम लालू परिवार पर आयकर शिकंजे के पीछे की गुत्थियों को समझने के लिए बिहार की राजनीति के फ्लैशबैक में चलते हैं. नीतीश कुमार द्वारा भाजपा का साथ छोड़ने और लोकसभा चुनाव में उम्मीद के मुताबिक सफलता हासिल न होने के बाद जदयू के सामने दो रास्ते बच गए थे. उस समय जदयू दो विकल्पों को लेकर दो खेमों में बंटा था. पहले खेमे के लिए पहला और आसान विकल्प यह था कि पुरानी दोस्ती एक बार फिर कायम कर ली जाए. सबसे बड़ा आधार बिहार का विकास और सूबे को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने वाली मुहिम थी. नरेंद्र मोदी और इनकी सरकार को उस समय इसमें कोई दिक्कत भी नहीं थी और बात कुछ आगे भी बढ़ गई. लेकिन नरेंद्र मोदी की प्रचंड जीत ने नीतीश कुमार को संशकित कर दिया. उस समय जदयू के एक खेमे ने उन्हें यह राय दी कि अभी नरेंद्र मोदी से अपनी शर्तों पर हाथ मिलाना संभव नहीं है.

(शेष पृष्ठ 2 पर)

## लालू परिवार की ज़ब्त सम्पत्तियां

1. फार्म हाइस नंबर 26, पालम फार्म्स, बिजवासन, दिल्ली
   कागजों पर नाम : मिशेल पैकर्स एंड प्रिंटर्स प्रा. लिमिटेड
   असल मालिक : मीसा और शैलेश
   बजार मूल्य : करीब 40 करोड़

2. बंगला नंबर : 1088, न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी, दिल्ली
   कागजों में नाम : एबी एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
   असल मालिक : तेजस्वी यादव, चन्दा यादव और राजिनी यादव
   बाजार मूल्य : 40 करोड़

3. नौ प्लॉट : जालापुर, थाना-दानापुर
   कागजों के नाम : डिलाइट मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड
   असल मालिक : राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव
   बाजार मूल्य : 65 करोड़

4. तीन प्लॉट : जालापुर, थाना-दानापुर
   कागजों के नाम : ए.के. इन्फोसिस्टम
   असल मालिक : राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव
   बाजार मूल्य : 20 करोड़

# राजनीति का लालू पर हमला

पृष्ठ 1 का शेष

देश का मिजाज अभी मोदीमय है. इसलिए जल्दबाजी में कोई फैसला लेना ठीक नहीं होगा. दूसरा, यह संदेश भी जाएगा कि जदयू मौकापरस्ती की राजनीति कर रही है. इन दो तर्कों के आधार पर उस समय नीतीश कुमार ने यह तय किया कि अभी रुका जाए और राजनीति की दशा-दिशा कुछ आगे बढ़ने दी जाए. इसके बाद ही जदयू का दूसरा खेमा सक्रिय हुआ और उसने नीतीश कुमार पर लालू प्रसाद से हाथ मिलाने के लिए दबाव बनाना शुरू कर दिया. विधानसभा चुनाव का समय नजदीक आ रहा था और जदयू में लालू समर्थक खेमा लगातार यह दबाव बना रहा था कि महागठबंधन बनाकर नरेंद्र मोदी को करारा जवाब दिया जा सकता है. नरेंद्र मोदी से खार खाए प्रशांत किशोर की भी उसी समय सत्ता के गलियारे में इंट्री हुई और उन्होंने भी नीतीश कुमार को यह गणित समझाया कि लालू प्रसाद और कांग्रेस के वोटों को जदयू के वोटों में मिला दिया जाए, तो फिर नरेंद्र मोदी का जादू बेअसर किया जा सकता है. दूसरी तरफ, भाजपा को भी लगने लगा कि वह अपने बलबूते बिहार की सत्ता पर काबिज हो सकती है. पार्टी को नरेंद्र मोदी के जादू पर भरोसा इस कदर था कि उसने अपनी सहयोगी पार्टियों को भी बहुत तवज्जो नहीं दी. ऐसे हालात में जदयू के अंदर जो भाजपा से हाथ मिलाकर राजनीति करने का पैरोकार खेमा था वह सुस्त पड़ गया. लालू समर्थक खेमा इतना प्रभावी हो गया कि उसने महागठबंधन का निर्माण करा दिया.

चुनाव हुआ, नतीजे आए और सब कुछ महागठबंधन के पक्ष में रहा. लेकिन राजनीति के जानकारों ने उस समय कहा था कि लालू के साथ मिलकर चुनाव लड़ना एक बात है और लालू के साथ मिलकर सरकार चलाना दूसरी बात है. नीतीश सरकार जैसे-जैसे आगे बढ़ती गई यह आशंका सच साबित होती गई. तेजस्वी यादव के विभाग के विज्ञापनों में नीतीश कुमार की तस्वीर का न लगना यह बताने लगा कि परदे के पीछे सब कुछ ठीक-ठाक नहीं है. इस बीच नोटबंदी के मुद्दे पर बिल्कुल अलग स्टैंड लेकर नीतीश कुमार ने लालू प्रसाद को चौंका दिया. लाख दबाव के बावजूद नीतीश कुमार ने अपनी राय नहीं बदली और कहते रहे कि यह एक अच्छा कदम है. लालू प्रसाद को उसी दिन स्पष्ट हो गया कि नीतीश कुमार अपनी मर्जी की ही करेंगे, इसलिए बेहतर होगा कि महागठबंधन की रस्सी को जरूरत से ज्यादा न खींचा जाए नहीं तो यह टूट भी सकती है. इसका असर यह हुआ कि सरकार चलने लगी, लेकिन परदे के पीछे दो ऐसी चीजें अटकी रहीं, जो महागठबंधन की गाड़ी दौड़ने नहीं दे रही थीं. इसी की काट लालू प्रसाद और नीतीश कुमार दोनों अब भी खोज रहे हैं. पहला रोड़ा था बड़े प्रशासनिक तबादले का और दूसरा रोड़ा बोर्ड व निगमों का नए सिरे से गठन का था. ये ऐसे मामले हैं जिन पर कई प्रयासों के बावजूद तीनों दलों में आमसहमति नहीं बन पाई. डीएम और एसपी के तबादले के मुद्दे पर लालू प्रसाद ने एक बार नीतीश कुमार के कुछ करीबी नेताओं को ऐसी फटकार लगाई कि वे हक्का-बक्का रह गए. इस माहौल में जदयू के उस खेमे को फिर से बल मिला जो पहले से चाह रहा था कि भाजपा के साथ पुरानी दोस्ती फिर से बहाल हो. लालू के व्यवहार से अपमानित वह खेमा उसी दिन से अभियान में लग गया कि कैसे लालू और उनके परिवार को लपेटे में लिया जाए.

महागठबंधन में रहते हुए लालू प्रसाद के खिलाफ जदयू द्वारा सीधा हमला संभव नहीं था, इसलिए लालू विरोधी नेताओं ने रणनीति में बदलाव कर दूसरे तरीके से हमला कराना शुरू कर दिया. सभी जानते हैं कि लालू प्रसाद को नीतीश कुमार के खिलाफ कुछ बोलना होता है, तो वे कभी रघुवंश बाबू तो कभी सांसद बूलो मंडल का इस्तेमाल करते हैं. लेकिन जदयू के लालू विरोधी नेताओं के लिए इस रणनीति को अपनाना संभव नहीं था. इसलिए प्लान बदला गया और ऐसे नेता की तलाश हुई, जिसकी बातों को मीडिया वजनदार माने और देश दुनिया में यह बात फैले कि लालू और उनका सारा परिवार बेनामी सम्पत्ति का बेताज बादशाह है. संयोग से सुशील मोदी इस समय पाटी में हाशिए पर थे और उन्हें भी अपनी इमेज चमकाने के लिए कुछ खास मुद्दे की तलाश थी. यह तय हुआ कि सुशील मोदी को आगे करके लालू प्रसाद पर ताबड़तोड़ हमले किए जाएं ताकि नीतीश कुमार पर लगातार बन रहा दबाव कम हो सके. नोटबंदी के बाद नीतीश कुमार बार-बार कह रहे थे कि नरेंद्र मोदी को अब बेनामी सम्पत्ति वालों पर भी शिकंजा कसना चाहिए. जदयू का लालू विरोधी खेमा इस इशारे को समझ गया, इसलिए उसने सबसे पहले बेनामी सम्पत्ति के मामले में लालू और उनके परिवार को घेरने की रणनीति बनाई. जदयू का लालू विरोधी खेमा सुशील मोदी को आगे करके अपनी गोटी लाल करने में लग गया. नरेंद्र मोदी सरकार के कुछ मंत्री भी धीरे-धीरे इसमें दिलचस्पी दिखाने लगे और लालू के खिलाफ आरोपों की झड़ी लगाने वाले दस्तावेज पटना और दिल्ली से एक साथ पहुंचने लगे. यह बात अब सभी कहने लगे हैं कि बिना सरकारी मशीनरी के इतने अहम दस्तावेज सुशील मोदी के हाथ लगना असंभव है.

खैर, तेजस्वी यादव के पटना में बन रहे सबसे बड़े मॉल से बात शुरू हुई और धीरे-धीरे इसमें लालू का पूरा परिवार आ गया. लालू विरोधी खेमे का तीर निशाने पर लगा और आरोपों की जो झड़ी सुशील मोदी ने लगाई उसकी गूंज पूरे देश में सुनाई देने लगी. नीतीश कुमार ने इस मामले में बहुत ही ठंडा रवैया अपनाया और यह कहकर अपना पल्ला झाड़ लिया कि अगर किसी के पास कोई सबूत है, तो वह उचित जगह पर उसे रखे. केवल मीडिया में बात करने से कुछ नहीं होगा. लालू खेमा चाहता था कि नीतीश कुमार इस मामले में खुलकर इनका साथ दें, लेकिन ऐसा नहीं हुआ. लालू खेमे को आभास हो गया कि यह लड़ाई उसे अपनी ही ताकत पर लड़नी है. इसलिए जवाबी कार्रवाई की रणनीति अपनाई गई. राजद प्रवक्ता मनोज झा ने आरोप लगाया कि सुशील मोदी के भाई की कई फर्जी कंपनियां हैं, जो काले धन को सफेद करती हैं. सुशील मोदी को इस मामले में जवाब देना चाहिए. राजद के प्रदेश प्रवक्ता प्रगति मेहता का आरोप है कि एनडीए के कई नेता अरबों रुपए के बेनामी सम्पति के मालिक हैं, लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है. लालू प्रसाद चूंकि विपक्षी एकता की धुरी बन गए हैं, इसलिए नरेंद्र मोदी की सरकार फर्जी मामले में लालू परिवार को फंसा कर बदनाम कर रही है. हालांकि राजद सुप्रीमो लालू यादव के ठिकानों पर छापेमारी के बाद पार्टी में विरोध की आवाज उठने से लालू के समक्ष अंदरूनी मुश्किलें भी खड़ी हुई हैं. राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश उपाध्यक्ष डॉ. हरेंद्र कुमार ने इसी मुद्दे पर पार्टी से इस्तीफा दे दिया और कहा कि लालू यादव पहले से चारा घोटाले में फंसे हुए थे. अब उन्होंने घोटाले में अपने पूरे परिवार को समेट लिया है. ऐसे माहौल में राजद में रहकर काम करना मुश्किल है.

बहरहाल, लगभग तीन महीने से चल रहे इस आरोप-प्रत्यारोप की कहानी के राजनीतिक प्रभाव की समीक्षा करें, तो पाते हैं कि लालू खेमा अभी बैकफुट पर है. लालू कहीं न कहीं अपने ऊपर लगे आरोपों का आक्रामक जवाब देने की स्थिति में नहीं हैं. राजद के अन्य नेता भी प्रतिरोध में ढीले ही साबित हो रहे हैं. राजद और उसके नेता यह बात ठीक से नहीं उठा पा रहे कि दर्जनों नेताओं के पास अकूत बेनामी सम्पत्ति है. उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही. केवल लालू प्रसाद ही निशाने पर क्यों हैं? भाजपा आलाकमान भी यह समझ चुका है कि लालू और उनका परिवार भ्रष्टाचार के मामले में जितना ही उलझेगा, नीतीश कुमार के साथ सरकार की गाड़ी खींचना उतना ही आसान होगा. लालू जितना ही कानून के फंदे में उलझेंगे नरेंद्र मोदी और अमित शाह के लिए 2019 की लड़ाई बिहार में उतनी ही आसान होती जाएगी. यही वजह है कि लालू प्रसाद बार-बार प्रयास कर रहे हैं कि यूपी में अखिलेश यादव और मायावती एक मंच पर आ जाएं. मायावती से उनकी लगातार बात हो रही है और चर्चा है कि एक बार तो उन्होंने मायावती को बिहार से राज्यसभा भेजने का प्रस्ताव भी दिया था. लालू चाह रहे हैं कि बिहार की तरह यूपी में भी भाजपा कमजोर हो. जदयू की भाजपा के साथ दोस्ती अगर एक बार फिर परवान चढ़ती है, तो नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की जोड़ी बिहार में कमाल कर सकती है. जाहिर है, 2019 की राजनीतिक बिसात के लिए सभी दल अपनी-अपनी गोटियां बिछाने में लग गए हैं. शह और मात के इस खेल में देखना दिलचस्प होगा कि कौन सी चाल पर किस खेमे को मात मिलती है और कौन सा खेमा बादशाहत बरकरार रख पाता है. ■

feedback@chauthiduniya.com

## फंसते हैं तब भी और उबरते हैं तब भी, चर्चा में रहते हैं लालू

बिहार के सबसे बड़ा मॉल का मसला हो, चिड़ियाखाना में मिट्टी बेचने की बात हो या अकूत बेनामी सम्पत्ति जमा करने के आरोप हों, लालू यादव इन आरोपों पर लगातार बल्लेबाजी कर रहे हैं. लालू की फितरत है कि वे फंसकर भी चर्चित होते हैं और उबरकर भी चर्चा में रहते हैं. निर्माणाधीन मॉल की मिट्टी चिड़ियाघर को बेचने के आरोप पर जब लालू आक्रामक हुए, तो लगा था कि लालू आरोपों से पार पा जाएंगे. लेकिन ऐसा नहीं हुआ. लालू लगातार यह कहते रहे कि सारे आरोप बेबुनियाद हैं और सच्चाई सामने आने पर सबकी बोलती बंद हो जाएगी. लेकिन आरोपों की तादाद बढ़ती ही गई. लालू ने मीडिया के समक्ष कहा था कि उनकी सम्पत्ति की सच्चाई नौ साल पहले 2008 में ही सामने आ चुकी थी. आय से अधिक सम्पत्ति के मामले में उन्हें सुप्रीम कोर्ट तक से क्लीनचिट मिल चुकी है. उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव और स्वास्थ्य मंत्री तेजप्रताप यादव ने अपनी सम्पत्ति का ब्यौरा सार्वजनिक किया हुआ है. मुख्यमंत्री को भी उसका ब्यौरा दिया गया है और चुनाव आयोग को भी. विभिन्न कंपनियों में शेयर के बारे में भी चुनाव आयोग को दिए गए हलफनामे में पहले ही उल्लेख किया जा चुका है. लालू ने कहा कि उनके बच्चों और पत्नी को बदनाम किया जा रहा है. लालू ने बाद में माना कि मॉल की जमीन उन्हीं की है, जहां मेरिडियन कंपनी पार्टनरशिप में मॉल बना रही है. डिलाइट मार्केटिंग ने सिलिंग एक्ट के तहत अनुमति लेकर जमीन खरीदी थी. सर्किल रेट और जमीन की कीमत का भुगतान चेक से किया गया था. बूम आया तो रीयल स्टेट की कीमत बेतहाशा बढ़ी. उस जमीन की कीमत भी बढ़ी. उसी जमीन पर मेरिडीयन कंस्ट्रक्शन ने मॉल बनाना शुरू किया. 2014 में पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने डिलाइट मार्केटिंग के शेयर खरीदे थे. लालू ने दावा किया था कि उनकी बेटी चन्दा और रागिनी के शेयर होल्डर होने की बात गलत है. हालांकि आयकर विभाग के रडार पर ये दोनों भी हैं. इनके अलावा लालू की पांचवीं बेटी हेमा यादव के पास भी बेनामी सम्पत्ति का आरोप है. हेमा के पास 62 लाख रुपए की बेनामी जमीन होने का मामला सामने आया है. ललन चौधरी नामक व्यक्ति ने हेमा यादव को तोहफे में जमीन दी. ललन चौधरी लालू के मवेशियों की देखभाल करता था और उसका नाम बीपीएल सूची में दर्ज है. सीवान जिले के बड़हरिया थानान्तर्गत सियाडीह गांव निवासी ललन चौधरी ने केवल राबड़ी देवी को ही 30 लाख 80 हजार रुपए के मकान सहित 2.5 डिसमिल जमीन 'दान' में नहीं दी, बल्कि लालू परिवार के कुछ अन्य लोग भी हैं, जिन्हें ललन ने तोहफे में जमीनें दी हैं. आरोप है कि राबड़ी को जमीन दिए जाने के 18 दिन बाद ही 62 लाख की 7.75 डिसमिल जमीन लालू प्रसाद की पांचवीं बेटी हेमा यादव को तोहफे में दे दी. पिछले 16 मई को आयकर विभाग ने दिल्ली और गुड़गांव में लालू यादव और उनके परिवार के 22 ठिकानों पर जब ताबड़तोड़ छापेमारी की तब आरोप-प्रत्यारोप का सच लोगों की समझ में आया. इसके काफी पहले मीसा यादव के चार्टर्ड अकाउंटेंट राजेश अग्रवाल की गिरफ्तारी हो चुकी थी. राजेश पर बेनामी कम्पनियों के 8 हजार करोड़ रुपए के लेन-देन को कानूनी बनाने की कोशिश करने के आरोप हैं. आयकर छापे की जद में राजद सांसद प्रेमचंद गुप्ता के ठिकाने भी आए. ■

## लालू का हमलावर तेवर बरकरार

आरोपों और छापों के बावजूद लालू यादव का हमलावर तेवर बरकरार है. आयकर विभाग की छापेमारियों पर सवाल उठाते हुए लालू ने मीडिया की भूमिका पर भी गंभीर सवाल उठाए. लालू ने पूछा कि वे 22 ठिकाने कौन हैं, जहां छापेमारी हुई? यह भी सवाल सामने आया कि अगर आठ घंटे तक छापेमारी चलती रही तो न्यूज चैनल उन ठिकानों को क्यों नहीं दिखा पाए? लालू परिवार ने यह भी आरोप लगाया कि खबरों में आयकर का आधिकारिक पक्ष भी नहीं दिखाया गया. ऐसी खबरों पर लालू प्रसाद ने भाजपा पर हमला बोला और कहा कि भाजपा की गीदड़ भभकी से वे डरने वाले नहीं है और वे भाजपा और संघ की ईंट से ईंट बजा देंगे. लालू यह साबित करने में लगे हैं कि उन पर हो रही कार्रवाई कानूनी नहीं बल्कि राजनीतिक साजिश है.

उल्लेखनीय है कि कुछ महीने पहले राजद ने राजगीर में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई थी. तीन दिनों की इस बैठक में संघ और भाजपा पर जोरदार हमला बोला गया था. भाजपा को उखाड़ फेंकने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर महागठबंधन बना कर 2019 का चुनाव लड़ने का ऐलान किया गया था. उसी समय 27 अगस्त को भाजपा भगाओ देश बचाओ रैली करने का भी ऐलान किया गया था. इस रैली में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी जैसी पार्टियां एक मंच पर जुटने वाली हैं. पश्चिम बंगाल की तृणमूल कांग्रेस और मार्क्सवादी पार्टी भी इस रैली में एक मंच पर शामिल होने वाली हैं. राजद के विधायक और प्रवक्ता अख्तरुल इस्लाम शाहीन कहते हैं कि लालू प्रसाद की इस कोशिश से भाजपा डर गई है और इसीलिए वह उनका मनोबल तोड़ने पर लगी है. ■

## लालू पर चारा घोटाले का केस चलता रहेगा

बेनामी सम्पत्तियों के आरोप में फंसा लालू परिवार सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले से पहले से चिंता में था कि लालू प्रसाद पर चारा घोटाले का केस भी चलता रहेगा. सुप्रीम कोर्ट ने लालू प्रसाद यादव के खिलाफ चारा घोटाला मामले में अलग से ट्रायल चलाने की अनुमति दे रखी है. सुप्रीम कोर्ट ने लालू के साथ-साथ बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा और पूर्व नौकरशाह सजल चक्रवर्ती के खिलाफ भी आपराधिक साजिश का केस चलाने का आदेश दे रखा है. पिछले महीने सुप्रीम कोर्ट ने साफ-साफ कहा कि झारखंड हाईकोर्ट ने कानून का उल्लंघन करते हुए लालू को राहत दी थी. सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को आदेश दिया कि वह लालू और अन्य आरोपियों के खिलाफ देवघर कोषागार से धन निकासी के मामले की सुनवाई तेजी से करे और ट्रायल नौ महीने में पूरा करे. ट्रायल कोर्ट ने लालू को पांच साल की सजा सुनाई थी. रांची हाईकोर्ट ने लालू यादव के खिलाफ साजिश के आरोपों को हटा दिया था. झारखंड के चाईबासा में ट्रेजरी से अवैध निकासी के मामले में ट्रायल कोर्ट लालू को दोषी ठहरा चुकी है. सीबीआई ने रांची हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर की थी. सीबीआई ने कहा था कि हाईकोर्ट ने आरोपियों के खिलाफ आपराधिक साजिश की धाराएं हटाकर गलती की. हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि एक ही अपराध के लिए किसी व्यक्ति के खिलाफ दो बार ट्रायल नहीं चलाया जा सकता. लालू की तरफ से सीबीआई की देर से दाखिल हुई याचिका के औचित्य पर सवाल उठाया गया था. नियमतः नब्बे दिन के अंदर याचिका दायर करनी होती है, लेकिन सीबीआई ने 157 दिनों के बाद याचिका दाखिल की थी. सीबीआई ने देरी की जो वजह बताई वह भी सही नहीं थी. लालू ने यह भी कहा था कि एक ही साजिश के आरोप बार-बार नहीं लगाए जा सकते. ■

चौथी दुनिया
हिंदी का पहला साप्ताहिक अखबार

वर्ष 09 अंक 18
03 जुलाई- 09 जुलाई 2017

RNI-DELHIN/2009/30467

संपादक
संतोष भारतीय

एडिटर (इंवेस्टिगेशन)
प्रभात रंजन दीन

सहायक संपादक
सरोज कुमार सिंह (बिहार-झारखंड)
सरयू भवन, वेस्ट बोरिंग केनाल रोड,
हरीलाल स्वीट्स के निकट, पटना-800001
फोनः 0612 3211869, 09431421901

मैसर्स अंकुश पब्लिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड के लिए मुद्रक व प्रकाशक रामपाल सिंह भदौरिया द्वारा जागरण प्रकाशन लिमिटेड डी 210-211 सेक्टर 63 नोएडा उत्तर प्रदेश से मुद्रित एवं के- 2, गैनन, चौधरी बिल्डिंग, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली 110001 से प्रकाशित

संपादकीय कार्यालय
के-2, गैनन, चौधरी बिल्डिंग कनॉट प्लेस, नई दिल्ली 110001
कैंप कार्यालय एफ-2, सेक्टर -11, नोएडा, गौतमबुद्ध नगर उत्तर प्रदेश-201301

फोन न.
संपादकीय 0120-6451999
6450888
विज्ञापन व प्रसार 022-65500786
+91-8451050786
+91-9266627379
फैक्स न. 0120-2544378

पृष्ठ-16++ (बिहार-झारखंड, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड)

चौथी दुनिया में छपे सभी लेख अथवा सामग्री पर चौथी दुनिया का कॉपीराइट है. बिना अनुमति के किसी लेख अथवा सामग्री के पुनः प्रकाशन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

समस्त कानूनी विवादों का क्षेत्राधिकार दिल्ली न्यायालयों के अधीन होगा.

## राजग प्रत्याशी रामनाथ कोविंद के मुक़ाबले विपक्ष ने मीरा कुमार को उतारा

# राम मीरा

### संख्या की कसौटी पर जीत रहे कोविंद

### व्यक्तित्व की कसौटी पर जीत चुकीं मीरा

### तिकड़म के आगे हार गए अनुभवी आडवाणी

प्रभात रंजन दीन

थोड़ी देर से ही सही, लेकिन विपक्ष ने राष्ट्रपति प्रत्याशी के लिए जोरदार नाम चुनकर एकबारगी सत्ता पक्ष को सकते में ला खड़ा किया. केंद्र सरकार ने दलित प्रत्याशी रामनाथ कोविंद को राष्ट्रपति पद का प्रत्याशी बना कर विपक्ष को झटका दिया था, लेकिन विपक्ष ने मीरा कुमार जैसी दमदार दलित प्रत्याशी को मैदान में उतार कर राष्ट्रपति चुनाव को रोचक-रोमांचक बना दिया है. रामनाथ कोविंद पढ़े-लिखे व्यक्ति हैं. लेकिन मीरा कुमार की शिक्षा-दीक्षा कोविंद की तुलना में काफी ऊपर है. वे देश की पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष थीं और राजनीति में आने से पहले वे भारतीय विदेश सेवा की अधिकारी थीं. लिहाजा, मीरा कुमार की उम्मीदवारी रामनाथ कोविंद पर भारी है. यह अलग बात है कि अंकगणितीय समीकरणों से सत्ता का प्रत्याशी चुनाव जीत जाए और विपक्ष का उम्मीदवार हार जाए, लेकिन व्यक्तित्व के चयन में सत्ता पक्ष पर विपक्ष की जीत दर्ज हो चुकी है.

राष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए आम सहमति बनाने के तमाम प्रहसन खेले गए. कभी विपक्ष का भोज तो कभी पक्ष का भोज. कभी विपक्ष की कमेटी तो कभी पक्ष की कमेटी, कभी इधर की मुलाकातें तो कभी उधर की, लेकिन यह सब जानी-समझी हुई नौटंकी थी. भाजपा ने खुद ही पहले संघ प्रमुख का नाम उड़वाया. शिव सेना से मोहन भागवत का नाम उछलवाया, फिर उसे असरदार करने के लिए भागवत की प्रणब मुखर्जी से मुलाकात करवाई और नियोजित भ्रम फैलाकर अचानक रामनाथ कोविंद का नाम प्रस्तावित कर दिया. भाजपा ने राष्ट्रपति पद के लिए दलित नाम चुना, जिसके नाम पर विपक्ष कोई चूं-चां नहीं कर पाए. लेकिन विपक्ष ने भाजपा के दलित-दांव पर भारी पड़वा रख दिया. मीरा कुमार की उम्मीदवारी से अब विपक्ष के उन नेताओं के समक्ष धर्मसंकट की स्थिति खड़ी हो गई है, जिन्होंने दलित होने के कारण रामनाथ कोविंद का पक्ष लेने का बयान दिया था. बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि उनकी पार्टी (जदयू) कोविंद के पक्ष में वोट डालेगी. राष्ट्रपति पद के लिए रामनाथ कोविंद की उम्मीदवारी का समर्थन करने वाले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कोविंद के राज्यपाल बनाए जाने पर विरोध किया था. नीतीश का कहना था उनसे सलाह लिए बगैर राज्यपाल की नियुक्ति की गई. रामनाथ कोविंद को समर्थन देने के नीतीश के फैसले से विपक्ष मुश्किल में है. बिहार में महागठबंधन में शामिल राजद के नेता लालू यादव ने इस मसले पर नीतीश से पुनर्विचार करने की अपील की है. नीतीश का फैसला विपक्षी दलों के लिए अप्रत्याशित इसलिए भी रहा क्योंकि नीतीश ने ही शुरुआत में विपक्षी दलों की तरफ से सर्वसम्मति के आधार पर राष्ट्रपति उम्मीदवार उतारने की बात कही थी. उन्होंने इस सिलसिले में कुछ विपक्षी नेताओं से बात भी की थी और 20 अप्रैल को कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मिले भी थे. लेकिन कोविंद के नाम की घोषणा के कुछ अर्सा पहले से नीतीश कुमार विपक्षी दलों से अलग-थलग रह रहे थे. राष्ट्रपति चुनाव के मसले पर 26 मई को सोनिया गांधी की अध्यक्षता में बुलाई गई भोज-बैठक में नीतीश शामिल नहीं हुए, जबकि अगले ही दिन नरेंद्र मोदी की तरफ से दिए गए भोज में वे शामिल हुए. इसे लेकर विपक्ष काफी परेशान है. कोविंद की उम्मीदवारी घोषित होने पर उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने भी कहा था कि अगर विपक्ष ने कोई दलित उम्मीदवार नहीं उतारा, तो बसपा कोविंद के पक्ष में वोट देगी, लेकिन वे मीरा कुमार के मैदान में उतरने के बाद पलट गईं. इसी तरह मुलायम सिंह यादव भी कोविंद के प्रति समर्थन जता चुके थे. लेकिन सपा के आधिकारिक अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मीरा कुमार के प्रति समर्थन जताया है. मीरा कुमार के मैदान में आ जाने से भाजपा को इन पार्टियों का वोट नहीं मिलने के आसार बढ़ गए हैं. कोविंद के नाम पर डंवाडोल में पड़ी कई अन्य पार्टियां भी अब मीरा कुमार के समर्थन में आ सकती हैं. अब तक 17 पार्टियों ने आधिकारिक तौर पर मीरा कुमार को समर्थन देने की घोषणा की है.

वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषकों का भी कहना है कि विपक्ष ने मीरा कुमार का नाम पहले ही घोषित कर दिया होता, तो राष्ट्रपति चुनाव को लेकर परिदृश्य कुछ और ही होता. लिहाजा, संप्रग अध्यक्ष सोनिया गांधी एक बड़ा राजनीतिक अवसर चूक गईं, या दांव लगाने में पिछड़ गईं, ऐसा कहा जा सकता है. त्रिसदस्यीय भाजपाई कमेटी ने सोनिया गांधी से भावी प्रत्याशी का नाम पूछा, तो उन्होंने भाजपा को पहले पत्ते खोलने को कहा. विश्लेषक यह भी कहते हैं कि अगर सोनिया ने उस समय लालकृष्ण आडवाणी को राष्ट्रपति बनाए जाने की इच्छा जता दी होती, तो भाजपा चारो खाने चित हो गई होती. लेकिन सोनिया ऐसा कुछ भी नहीं कर पाईं. दरअसल मीरा कुमार का नाम तो विपक्ष के ध्यान में कोविंद के चयन के बाद आया, लेकिन आडवाणी पर दांव खेलना भाजपा के लिए भारी पड़ जाता और विपक्ष की राजनीति भाजपा के अंदरूनी समीकरणों की गिल्लियां बिखेर कर रख देती. विपक्ष की इस चाल से राजग में दरारें पड़ जातीं, पार्टी व्हिप की ऐसी-तैसी हो जाती और भाजपा को जमीन दिख जाती.

लालकृष्ण आडवाणी को लेकर भाजपा सांसद शत्रुघ्न सिन्हा का ट्वीट पहले ही सुर्खियां और समर्थन दोनों बटोर चुका था. शत्रुघ्न सिन्हा ने अपने ट्वीट में लिखा था कि पूर्व उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी ही राष्ट्रपति पद के लिए बेहतर उम्मीदवार हैं. भाजपा को उन्हें उम्मीदवार बनाना चाहिए. लालकृष्ण आडवाणी को पितामह कहने वाले बिहारी बाबू ने लिखा कि कुछ गंभीर चिंतन करने वाले नागरिकों की प्रतिक्रियाओं से मैं काफी प्रभावित हूं. यह देश सत्ता के शीर्ष पर काबिज किसी एक व्यक्ति या एक छोटे प्रभावशाली समूह की मर्जी से नहीं चल सकता. यह देश किसी एक व्यक्ति का या किसी एक समूह का नहीं वरन सवा सौ करोड़ देशवासियों का है. राष्ट्रपति जैसे महत्वपूर्ण पद पर किसी की योग्यता और अनुभव को पूरी तरह नजरअंदाज कर अपनी मर्जी नहीं थोपी जा सकती. मेरे विचार से आडवाणी ही किसी भी पार्टी के जरूरी मापदंडों से ऊपर हैं, जो किसी से प्रभावित नहीं होते. आखिर राष्ट्रपति के नॉमिनेशन को लेकर अजीब सी चुप्पी क्यों हैं? किसी पार्टी या किसी व्यक्ति को आडवाणी की योग्यता, उनके लंबे संसदीय अनुभव और उनके सार्वजनिक जीवन के अनुभवों में क्या कोई कमी दिखाई देती है? शत्रुघ्न के इस ट्वीट पर चर्चा भी खूब हुई और उन्हें समर्थन भी खूब मिला. लेकिन विपक्ष के नेता सियासी थर्मामीटर के इस तापमान को पढ़ नहीं पाए.

**रोचक रोमांचक राष्ट्रपति चुनाव**

### लालू प्रसाद यादव ने भरा राष्ट्रपति का पर्चा!

17 जुलाई को होने वाले राष्ट्रपति चुनाव के लिए लालू प्रसाद यादव ने नामांकन दाखिल किया है. लालू प्रसाद यादव ने बुधवार 23 जून को नामांकन दाखिल किया. लोकसभा सचिवालय ने आधिकारिक तौर पर बताया कि लालू प्रसाद यादव ने नामांकन पत्र दाखिल करते हुए मतदाता के तौर पर पंजीकृत संसदीय क्षेत्र की मतदाता सूची में दर्ज अपने नाम की कॉपी और 15 हजार रुपए जमानत राशि के रूप में जमा किए हैं. 23 जून को दो लोगों ने राष्ट्रपति पद के लिए नामांकन भरा, जिसमें लालू प्रसाद यादव के अलावा तमिलनाडु के धरमपुरी जिले के अग्नि श्रीरामचंद्रन शामिल हैं. अब तक दो दर्जन से अधिक लोग नामांकन दाखिल कर चुके हैं. राष्ट्रपति चुनावों के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू होने के पहले दिन छह लोगों ने नामांकन दायर किया था, जिसमें मुम्बई के पटेल दम्पति सायरा बानो मोहम्मद पटेल और मोहम्मद पटेल अब्दुल हामिद शामिल हैं. इनके अलावा तमिलनाडु के के.पद्मराजन, मध्यप्रदेश के आनंद सिंह कुशवाहा, तेलंगाना के ए.बालाा राज और पुणे के कोंडेकर विजयप्रकाश ने भी राष्ट्रपति चुनाव के लिए अपना नामांकन-पत्र दाखिल किया है.

लालू प्रसाद यादव को लेकर किसी भ्रम में न रहें, ये लालू यो लालू नहीं हैं. यानि, ये लालू राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष नहीं हैं. संयोग यह है कि दोनों का नाम और गृह जिला समान है. राष्ट्रपति पद के लिए नामांकन भरने वाले लालू प्रसाद यादव भी बिहार के सारण जिले के हैं और राजद अध्यक्ष लालू यादव भी सारण के रहने वाले हैं. ■

### कौन-कौन हुए राष्ट्रपति, कैसे बनते हैं राष्ट्रपति

भारत का राष्ट्रपति देश का सबसे सर्वोच्च पद और तीनों भारतीय सेनाओं का प्रमुख होता है. राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होता है. संसद और राज्य के विधानमंडल के चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा देश के राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है.

भारत की आजादी से अब तक देश के 14 राष्ट्रपति चुनाव हुए, जिनमें 13 व्यक्ति भारत के राष्ट्रपति चुने गए. डॉ. राजेंद्र प्रसाद अकेले ऐसे राष्ट्रपति हुए, जो दो कार्यकाल में राष्ट्रपति रहे. छोटे अंतराल के लिए तीन कार्यकारी राष्ट्रपति हुए. भारतीय संविधान के भाग 5 के अनुच्छेद 56 के द्वारा भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल पांच साल का होता है. राष्ट्रपति की बर्खास्तगी और अनुपस्थिति में ही उपराष्ट्रपति कार्यभार संभालता है. ये हैं भारत के अबतक के राष्ट्रपतिः-

1. डॉ. राजेन्द्र प्रसाद. जन्म-1884, मृत्यु-1963, कार्यकाल-26 जनवरी 1950 से 13 मई 1962.

2. डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन. जन्म-1888, मृत्यु-1975. कार्यकाल-13 मई 1962 से 13 मई 1967.

4. डॉ. जाकिर हुसैन. जन्म-1897, मृत्यु-1969, कार्यकाल-13 मई 1967 से 3 मई 1969.

5. वराहगिरी वेंकट गिरि. जन्म-1894, मृत्यु-1980, कार्यकाल- 24 अगस्त 1969 से 24 अगस्त 1974.

6. फखरुद्दीन अली अहमद. जन्म- 1912, मृत्यु- 2002, कार्यकाल- 24 अगस्त 1974 से 24 अगस्त 1977.

7. नीलम संजीव रेड्डी. जन्म-1913, मृत्यु-1996, कार्यकाल-25 जुलाई 1977 से 25 जुलाई 1982.

8. ज्ञानी जैल सिंह. जन्म-1916, मृत्यु-1994, कार्यकाल-25 जुलाई 1982 से 25 जुलाई 1987.

9. आर वेंकटरमण. जन्म-1910, मृत्यु-2009, कार्यकाल-25 जुलाई 1987 से 25 जुलाई 1992.

11. के. आर. नारायणन. जन्म-1920, मृत्यु-2005, कार्यकाल-25 जुलाई 1997 से 25 जुलाई 2002.

12. डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम. जन्म-1931,मृत्यु-2015, कार्यकाल-25 जुलाई 2002 से 25 जुलाई 2007.

13. प्रतिभा देवी पाटिल. जन्मः 1934, कार्यकाल-25 जुलाई 2007 से 25 जुलाई 2012

14. प्रणब मुखर्जी. जन्म-1935, कार्यकाल-25 जुलाई 2012 से अबतक.

राष्ट्रीय राजनीति के मैदान के नए लेकिन खुर्राट नेता नरेंद्र मोदी ने उम्र के आधार पर लालकृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी जैसे वरिष्ठ नेताओं को किनारे लगा दिया. मोदी ने इन नेताओं की आयु पूरी होने के पहले ही इनकी राजनीतिक हत्या कर दी. उम्र अगर आधार हो तो 60 साल से ऊपर के किसी भी व्यक्ति को किसी भी पद पर नहीं होना चाहिए. जब सरकारी अधिकारी या कर्मचारी का 58 और 60 साल में रिटायर हो जाना नियम है तो नेताओं में कौन सा सुर्खाब का पर लगा है कि वे 60 से ऊपर के हों तो प्रधानमंत्री बन जाएं, लेकिन आडवाणी 75 साल के हो जाएं तो उनकी हत्या कर दी जाए! उम्र की इसी नैतिकता के आधार पर मोदी को इस्तीफा देकर योगी जैसे युवा को देश का प्रधानमंत्री बना देना चाहिए था और कोविंद की जगह किसी दूसरे युवा दलित को राष्ट्रपति पद का प्रत्याशी घोषित करना चाहिए था. आम लोगों के ये सवाल नैतिक मूल्यों से जुड़े हैं, नेताओं पर ये लागू नहीं होते. नरेंद्र मोदी और अमित शाह की तिकड़म के आगे आखिरकार हार ही गए अनुभवी आडवाणी.

बहरहाल, उत्तर प्रदेश के लोगों को इसी में गौरव-बोध है कि देश का प्रधानमंत्री वाराणसी का सांसद है और होने वाला राष्ट्रपति कानपुर का रहने वाला है. रामनाथ कोविंद भी 70 साल के हो चुके हैं. लिहाजा, रिटायरमेंट के पहले की उनकी आखिरी पोस्टिंग है. इसके पहले देश को यूपी से कोई पूर्णकालिक राष्ट्रपति नहीं मिला. मोहम्मद हिदायतुल्ला एक बार 24 दिन के लिए और दूसरी बार 25 दिन के लिए देश के कार्यकारी राष्ट्रपति बने थे. रामनाथ कोविंद बिहार के राज्यपाल थे. बिहारवासियों को भी कोविंद के राष्ट्रपति उम्मीदवार बनाए जाने पर इसलिए खुशी मिली, क्योंकि वे बिहार के राज्यपाल थे. बिहार के लोगों को यह खुशी 1962 में भी मिल चुकी है, जब बिहार के राज्यपाल डॉ. जाकिर हुसैन भारत के राष्ट्रपति बने थे. डॉ. जाकिर हुसैन आजादी के बाद बिहार के चौथे राज्यपाल थे और वे देश के भी चौथे ही राष्ट्रपति बने. डॉ. जाकिर हुसैन छह जुलाई 1957 से 11 मई 1962 तक बिहार के राज्यपाल रहे.

रामनाथ कोविंद का जन्म कानपुर देहात की डेरापुर तहसील के गांव परौख में 1945 में हुआ था. उनकी प्रारंभिक शिक्षा संदलपुर ब्लॉक के ग्राम खानपुर परिषदीय प्राथमिक व पूर्व माध्यमिक विद्यालय हुई. कानपुर नगर के बीएनएसडी से इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद डीएवी कॉलेज से बी. कॉम और डीएवी लॉ कालेज से एलएलबी की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद दिल्ली में रहकर तीसरे प्रयास में सिविल सेवा की परीक्षा पास की, लेकिन एलाइड सर्विसेज़ मिलने के कारण नौकरी ठुकरा दी और वकालत करने लगे. 1977 में जनता पार्टी की सरकार के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के वे निजी सचिव बने. इसके बाद वे भाजपा में आए. कोविंद को भाजपा ने 1990 में घाटमपुर लोकसभा सीट से टिकट दिया लेकिन वे चुनाव हार गए. वर्ष 1993 और 1999 में पार्टी ने उन्हें प्रदेश से दो बार राज्यसभा भेजा. पार्टी के लिए दलित चेहरा बने कोविंद अनुसूचित जाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रवक्ता भी रहे. वर्ष 2007 में पार्टी ने रामनाथ कोविंद को भोगनीपुर सीट से चुनाव लड़ाया, लेकिन वे फिर चुनाव हार गए. अगस्त 2015 में उन्हें बिहार का राज्यपाल बनाया गया था. कोविंद नरेंद्र मोदी के काफी करीबी हैं. भाजपा रामनाथ कोविंद को मायावती के खिलाफ एक दलित चेहरे के तौर पर आजमाना चाहती थी, लेकिन उनके लगातार चुनाव हारने के कारण ऐसा संभव नहीं हो पाया.

विपक्ष ने 23 जून को पूर्व लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार को विपक्ष की तरफ से राष्ट्रपति पद का प्रत्याशी बनाए जाने का ऐलान किया. अब राष्ट्रपति का चुनाव 'दलित बनाम दलित' हो गया है. कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा, 'हमने मीरा कुमार को राष्ट्रपति चुनाव में उतारने का फैसला किया है. हमें उम्मीद है कि अन्य दल भी हमारे साथ आएंगे.' 17 राजनीतिक दलों ने संसद भवन में हुई विपक्ष की बैठक में हिस्सा लिया और मीरा कुमार के नाम पर मुहर लगा दी. 'दलित बनाम दलित' का चुनाव काफी रोचक हो गया है. रामनाथ कोविंद राजग के साफ छवि वाले नेता हैं, तो दूसरी तरफ मीरा कुमार का प्रशासनिक करियर और राजनीतिक जीवन भी स्वच्छ रहा है. उच्च शिक्षित मीरा कुमार विनम्र, मृदुभाषी और हमेशा मुस्कुराने वाली भद्र महिला मानी जाती हैं. मीरा कुमार पूर्व उप प्रधानमंत्री जगजीवन राम की बेटी हैं. वे वर्ष 1973 में भारतीय विदेश सेवा में शामिल हुईं. कई देशों में नियुक्त रहीं और बेहतर राजनयिक साबित हुईं. तीन जून 2009 को मीरा कुमार पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष निर्विरोध चुनी गई थीं. 1975 में वे पहली बार बिजनौर से संसद में चुनकर आई थीं. 1990 में वे कांग्रेस पार्टी कार्यकारिणी समिति की सदस्य और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की महासचिव भी चुनी गईं. 1996 में मीरा कुमार दूसरी बार सांसद बनीं और तीसरी बार 1998 और 2004 में बिहार के सासाराम से लोकसभा सीट पर चुनाव जीतकर संसद पहुंची. ■

## वेलस्पन के ख़िलाफ़ किसान

# किसान के ख़िलाफ़ मध्य प्रदेश सरकार

चौथी दुनिया ब्यूरो

**दरअसल, 2010 में वेलस्पन एनर्जी नामक औद्योगिक कंपनी ने मध्यप्रदेश के विजयराघवगढ़ एवं बरही तहसीलों के ग्राम बुजबुजा व डोकरिया के क्षेत्रीय किसानों की कृषि भूमि का उनकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ अधिग्रहण किया था. अधिग्रहण के बाद जब किसानों ने इसका विरोध किया, तो उन्हें मुआवजे और नौकरी का लालच दिया गया. साथ ही प्रशासन का भी डर दिखाया गया था. मुआवजे और नौकरी की बात तो थोथी ही साबित हुई, प्रशासन भी कंपनी का पक्षकार बनकर रह गया. किसानों ने ज़िला कलेक्टर को इस कार्यवाही के विरुद्ध सामूहिक रूप से आपत्ति व्यक्त करते हुए ज्ञापन सौंपा था. लेकिन कुछ नहीं हुआ. उल्टे कंपनी का विरोध करने वाले इन किसानों को असामाजिक तत्व बताया गया और इनके ख़िलाफ़ प्रशासनिक कार्रवाई का डर भी दिखाया गया.**

क्या मध्य प्रदेश की सरकार पूंजीपतियों और कंपनियों के इशारे पर चल रही सरकार है? ये सरकार क्यों किसानों के न्यायपूर्ण अधिकार को नजरअंदाज़ कर रही है? ये कहना है उन किसानों का जिनकी जमीनें 7 साल पहले वेलस्पन कंपनी द्वारा अधिग्रहित की गई थीं. तब से अब तक ये किसान अपनी जमीनें वापस पाने के लिए संघर्षरत हैं, लेकिन कंपनी तो दूर सरकार की तरफ से भी इन्हें कोई सहायता नहीं मिल पाई है. भूमि अधिग्रहण कानून के अनुसार, पांच वर्ष के भीतर यदि अधिग्रहित भूमि का प्रोजेक्ट के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता है, तो उसे किसानों को वापस किया जाना कानूनी बाध्यता है. लेकिन ना तो कंपनी देश के कानून का सम्मान कर रही है और ना ही राज्य सरकार द्वारा किसानों के पक्ष में कंपनी को भूमि वापस करने के निर्देश दिए जा रहे हैं. देश में अब तक ऐसी कई परियोजनाओं के इलाके में जमीनें उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय द्वारा भूमि अधिग्रहण कानून के तहत वापस कराई जा चुकी हैं. लेकिन बुजबुजा और डोकरिया के किसान हर तरफ से प्रयास कर के हार चुके हैं.

दरअसल, 2010 में वेलस्पन एनर्जी नामक औद्योगिक कंपनी ने मध्यप्रदेश के विजयराघवगढ़ एवं बरही तहसीलों के ग्राम बुजबुजा व डोकरिया के क्षेत्रीय किसानों की कृषि भूमि का उनकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ अधिग्रहण किया था. अधिग्रहण के बाद जब किसानों ने इसका विरोध किया, तो उन्हें मुआवजे और नौकरी का लालच दिया गया. साथ ही प्रशासन की भी डर दिखाया गया था. मुआवजे और नौकरी की बात तो थोथी ही साबित हुई, प्रशासन भी कंपनी का पक्षकार बनकर रह गया. किसानों ने ज़िला कलेक्टर को इस कार्यवाही के विरुद्ध सामूहिक रूप से आपत्ति व्यक्त करते हुए ज्ञापन सौंपा था. लेकिन कुछ नहीं हुआ. उल्टे कंपनी का विरोध करने वाले इन किसानों को असामाजिक तत्व बताया गया और इनके ख़िलाफ़ प्रशासनिक कार्रवाई का डर भी दिखाया गया. जमीन अधिग्रहण का विरोध करने वाले लोगों को विकास का दुश्मन कहा गया. लेकिन बुजबुजा एवं डोकरिया ग्रामों के बहुसंख्यक ग्रामीण इस उद्योग के लिए किसी भी क़ीमत पर अपनी ज़मीनें देने के लिए तैयार नहीं हैं. उनकी आपत्तियों तथा विरोध को पर्याप्त महत्व न दिए जाने और उसकी पूरी तरह अनदेखी करते हुए ज़मीनें हथियाने की प्रक्रिया पर अभी भी रोक न लगने से नाराज़ ग्रामीणों ने आंदोलन का रास्ता अपनाया. गौरतलब है कि अधिग्रहित जमीनों पर अब तक प्रोजेक्ट स्थापित नहीं किया जा चुका है, लेकिन कंपनी ने उन 800 एकड़ जमीन पर गड्ढे खोद रखे हैं. इसके कारण किसान 2010 से ही उन जमीनों पर खेती नहीं कर पा रहे हैं. कंपनी का ये कृत्य गैर-कानूनी भी है. लेकिन न तो स्थानीय प्रशासन और न ही राज्य सरकार कंपनी के खिलाफ कार्रवाई कर रही है और न ही किसानों को उनका हक दिलवा पा रही है.

अब तो इन किसानों के शांतिपूर्ण आंदोलन को पुलिसिया कार्रवाई के जरिए दबाने की कोशिश भी की जाने लगी है. बुजबुजा और डोकरिया के किसान बीते 13 जून को अपनी जमीनों को वापस पाने के लिए अहिंसक व शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे थे. अपनी जमीन की वापसी के मांग को लेकर लगभग 40-50 किसान कटनी कलेक्टर कार्यालय के समीप शांतिपूर्वक धरने बैठे थे. तभी पुलिस ने जबरदस्ती उन्हें वहां से हटाने की कोशिश की और एसडीएम के आदेश पर धारा 151 के तहत उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया. गिरफ्तार किसानों को कटनी जेल भेज दिया गया. गिरफ्तारी के दौरान किसानों से मारपीट भी की गई. इस गिरफ्तारी के बाद पूरे क्षेत्र में पुलिस प्रशासन के खिलाफ गुस्से का माहौल फैल गया. लोगों ने इस कार्रवाई को अलोकतांत्रिक एवं अवैधानिक बताया. इनका कहना है कि पुलिस प्रशासन की ये कार्रवाई वेलस्पन कंपनी को सरकार द्वारा मिले अवैध संरक्षण को दिखाती है. इस कार्रवाई से किसानों के प्रति सरकार का घिनौना चेहरा सामने आ गया है.

जन आंदोलनों के राष्ट्रीय समन्वय, एनएपीएम ने वेलस्पन कंपनी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों के साथ मारपीट और उन्हें गिरफ्तार कर कटनी जेल भेजे जाने की कार्रवाई की निंदा की है और किसानों को जल्द रिहा किए जाने की मांग की है. जन आंदोलनों के राष्ट्रीय समन्वय की नेत्री मेधा पाटेकर ने किसानों के खिलाफ इस पुलिसिया कार्रवाई को किसानों के संवैधानिक अधिकारों का हनन बताया है. उन्होंने राज्य सरकार ने मांग की है कि किसानों को जल्द से जल्द रिहा किया जाय. साथ ही सरकार वेलस्पन कंपनी पर कार्रवाई करते हुए किसानों की अधिग्रहित जमीनों को उन्हें वापस करे. इसी कड़ी में किसान संघर्ष समिति के प्रदेश उपाध्यक्ष एवं जिला पंचायत सदस्य डॉ ए. के. खान, डॉ सुनीलम व कई अन्य लोगों ने इस कार्रवाई का विरोध किया है. ये सभी लोग बुजबुजा और डोकरिया गांव के किसानों के समर्थन में खड़े हैं. किसानों के आंदोलन को भी शुरू से ही इनका साथ मिलता रहा है. इनका कहना है किसानों के साथ पुलिस द्वारा मारपीट और उनकी गिरफ्तारी प्रशासनिक कायरता को दिखाती है. हम मुख्यमंत्री से मांग करते हैं कि किसानों को बिना शर्त रिहा किया जाय और जबरन अधिग्रहित उनकी जमीनों को वापस किया जाय. ■

feedback@chauthiduniya.com

# कोविंद के बहाने नीतीश ने चलाए सियासी तीर

## सियासत में मौक़े की नज़ाकत को जो नेता सबसे पहले समझ ले वही मैदान मार ले जाता है

चौथी दुनिया ब्यूरो

राष्ट्रपति चुनाव के लिए प्रत्याशी चयन को लेकर पिछले महीने भर से जो रहस्य बना हुआ था, उसकी गहराई को नापने में लगता है नीतीश कुमार बाजी मार ले गए. नीतीश कुमार का बार-बार ये कहना सबको याद है कि केंद्र सरकार को इस मामले में सब लोगों से विचार कर एक राय बनानी चाहिए. इस मामले में सोनिया गांधी और लालू प्रसाद से उनकी कई दौर की बातचीत भी हुई. यह कहा जाने लगा कि नीतीश कुमार विपक्षी एकता की धुरी बन रहे हैं. लेकिन जैसे ही अमित शाह ने बिहार के राज्यपाल रामनाथ कोविंद को एनडीए का प्रत्याशी घोषित किया, पूरा खेल ही बदल गया. जानकार बताते हैं कि इस खेल की पटकथा पहले ही लिखी जा चुकी थी और नीतीश कुमार को कुछ-कुछ इसका आभास भी था. जैसे ही संघ की पृष्ठभूमि वाला एक दलित चेहरा सामने आया, नीतीश कुमार ने बिना समय गंवाए कोविंद से मुलाकात की और उन्हें बधाई दी. नीतीश कुमार ने उस दिन कहा कि बिहार में राज्यपाल के तौर पर कोविंद जी काम बेहतरीन रहा है और मुझे व्यक्तिगत तौर पर उनके नाम की घोषणा होने से खुशी है. आगे विपक्षी दलों की बैठक में जो तय होगा उस पर जदयू अपना मत स्पष्ट करेगा. लेकिन 22 तारीख की बैठक का इंतजार किए बिना नीतीश कुमार ने आनन-फानन में अपने विधायकों और कोर ग्रुप की बैठक 21 तारीख को ही बुलाकर यह ऐलान कर दिया कि जदयू रामनाथ कोविंद को समर्थन देगा. हालांकि कोविंद के नाम की घोषणा के साथ ही जिस गर्मजोशी से नीतीश कुमार उनसे मिले थे, उसी समय लगने लगा था कि जदयू कोविंद के साथ ही जाएगा. लेकिन विपक्षी दलों की बैठक के ठीक पहले अपने विधायकों को बुलाकर नीतीश कुमार ने साफ संदेश दे दिया कि महागठबंधन अपनी जगह पर है, लेकिन जब बात राष्ट्रीय मुद्दे की आएगी, तो जदयू किसी भी तरह का फैसला लेने के लिए स्वतंत्र है. नीतीश कुमार की इस साफगोई ने लालू प्रसाद और सोनिया गांधी को भौंचक कर दिया. सबको उम्मीद थी कि नीतीश कुमार कम से कम 22 तारीख वाली दिल्ली में होने वाली बैठक तक चुप रहेंगे. लेकिन लालू प्रसाद का यह अंदाजा भी गलत निकला और 21 तारीख को ही अपने विधायकों को बुलाकर नीतीश कुमार ने कोविंद को समर्थन देने की घोषणा करवा दी. जानकार बताते हैं कि नीतीश कुमार का अंदेशा था कि अगर विपक्ष की बैठक में किसी दलित प्रत्याशी के नाम पर सहमति बन गई, तो ऐसे में दुविधा वाली स्थिति पैदा हो जाएगी. इसलिए बेहतर होगा कि उस बैठक के पहले ही जदयू के स्टैंड को साफ कर दिया जाए. नीतीश कुमार ने ऐसा ही किया और कोविंद को समर्थन कर दिया. जानकार बताते हैं कि नीतीश कुमार के इस फैसले का असर बिहार और दिल्ली की राजनीति पर पड़ना तय है. हालांकि ऐसा पहली बार नहीं है कि नीतीश कुमार ने किसी मामले में अपना अलग स्टैंड लिया हो. पहले नोटबंदी और बाद में सर्जिकल स्ट्राइक के मुद्दे पर भी वे केंद्र की भाजपा सरकार के साथ दिखे थे. लेकिन चूंकि इस बार मुद्दा राजनीतिक है इसलिए ज्यादा बवाल मचा हुआ है. राजद विधायक भाई विरेंद्र कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ने महागठबंधन को धोखा दिया है. रघुवंश बाबू का आरोप है कि नीतीश कुमार महागठबंधन को कमजोर कर रहे हैं. सूत्र बताते हैं कि इस बार लालू प्रसाद ने भी महसूस किया कि नीतीश कुमार के इस फैसले को हल्के में न लिया जाए. आगे सतर्क रहने की जरूरत है. दरअसल, नीतीश कुमार सारे विकल्प खुले रखना चाहते हैं. उन्होंने जिस समय कोविंद को समर्थन किया, ठीक उसी समय योग दिवस को लेकर कहा कि इसे बस प्रचार का दिन बनाकर रख दिया गया है. कहा जाए तो नीतीश अपने को किसी पाले में बैठा हुआ नहीं दिखना चाहते हैं. राष्ट्रपति चुनाव के बहाने विपक्षी एकता की जो कवायद चल रही थी, उसे तो नीतीश कुमार ने भंडोल कर ही दिया साथ ही साथ इतनी गुंजाइश भी नहीं छोड़ी कि इस चुनाव में कोई रोमांच बना रहे. जदयू के समर्थन के बाद अब कोविंद का आसानी से राष्ट्रपति बन जाना तय हो गया है. नीतीश कुमार के करीबी बताते हैं कि कोविंद की जीत तय कर नीतीश कुमार अपने दलित वोट बैंक को और भी मजबूत करने में सफल होंगे. कोविंद को समर्थन कर नीतीश ने भाजपा नेताओं का भी दिल जीत लिया है. सुशील मोदी ने उन्हें इसके लिए धन्यवाद भी कहा. कहा जाए तो नीतीश कुमार ने अपनी चाल चल दी और उसका उन्हें फायदा होता भी दिख रहा है, लेकिन इस चाल का असर महागठबंधन और 2019 के चुनाव पर क्या होगा इसका आकलन करने में अभी वक्त लगेगा. लेकिन इतना तय है कि सूबे और देश की राजनीति पर नीतीश के इस बोल्ड फैसले का असर होगा और इसके आसार दिखने भी लगे हैं. ■

**हालांकि ऐसा पहली बार नहीं है कि नीतीश कुमार ने किसी मामले में अपना अलग स्टैंड लिया हो. पहले नोटबंदी और बाद में सर्जिकल स्ट्राइक के मुद्दे पर भी वे केंद्र की भाजपा सरकार के साथ दिखे थे. चूंकि इस बार मुद्दा राजनीतिक है इसलिए ज्यादा बवाल मचा हुआ है. राजद विधायक भाई विरेंद्र कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ने महागठबंधन को धोखा दिया है. रघुवंश बाबू का आरोप है कि नीतीश कुमार महागठबंधन को कमजोर कर रहे हैं.**

feedback@chauthiduniya.com

# छग में किसके सिर बंधेगा जीत का सेहरा

सुषमा गुप्ता

छत्तीसगढ़ में आज से ठीक डेढ़ साल बाद जनता अगली सरकार चुनेगी. अब तक जनता के पास दो ही विकल्प होते थे, कांग्रेस और भाजपा. इस बार तीन विकल्प हैं. इन दोनों पार्टियों के अलावा जनता छग जनता कांग्रेस को चुन सकती है. कांग्रेस से अलग होकर पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी ने छग जनता कांग्रेस बनाई है.

अब तीनों ही पार्टियां मैदान में ताल ठोक रही हैं. रोज़ नए-नए दावे कर रही हैं. पिछले दो चुनावों में महज़ एक फीसदी से भी कम वोटों से चुनावी जीत हासिल करने वाली भाजपा इस बार 65 सीटों की जीत का दावा कर रही है. अजीत जोगी भी अपनी ताजपोशी का दावा कर रहे हैं, वहीं कांग्रेस हर किसी को अपने जीत का गणित समझा रही है. राज्य में 65 सीट जीतने का दावा अगर किसी और नेता ने किया होता तो इसे उतनी तवज्जो नहीं मिलती. लेकिन ये बात भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने तीन दिन राज्य में बिताने के बाद कही है, इसलिए कोई भी विरोधी दल इसे हल्के में नहीं ले रहा है. अमित शाह ने यूपी चुनाव के जो नतीजे तमाम अटकलों को गलत साबित कर दिलाए थे, उसके बाद उन्हें कुशल चुनावी प्रबंधक माना जा रहा है. अमित शाह के दौरे के बाद राज्य में राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ गई हैं. तीनों मुख्य पार्टियां चुनावी प्रबंधन को मज़बूती देने में जुट गई हैं. जनता कांग्रेस ने अजीत जोगी के दौरे के लिए तत्काल हेलिकॉप्टर मंगा लिया. वहीं कांग्रेस महासचिव बीके हरिप्रसाद ने दो दिन तक रायपुर में डेरा डाले रखा और चुनावी तैयारियों का जायज़ा लेना शुरू कर दिया.

अहम बात यह है कि साढ़े तीन साल में किस पार्टी ने कितनी तैयारी की है. तैयारियों में जो जितना आगे रहेगा कठिन मुकाबले में फायदा उसे ही सबसे ज़्यादा होगा. इस मसले पर प्रदेश के एक वरिष्ठ पत्रकार से मैंने पूछा कि आज की तारीख में कौन सी पार्टी कहां खड़ी है. उन्होंने इसका जवाब बड़े दिलचस्प तरीके से दिया. वे उठ खड़े हुए, फिर दौड़े और बोले ये है सरकार की तैयारी. इसके बाद वे पैदल आगे गए और बोले ये जोगी कांग्रेस की तैयारी है. फिर वे अपनी जगह पर खड़े होकर बिना आगे बढ़े ताल ठोंकने लगे. कहा, और ये है कांग्रेस की तैयारी. जहां वो दो साल पहले थी, अब भी वहीं है, लेकिन ताल ऐसे ठोंक रही है जैसे बाज़ी उसी के हाथ में है.

अगर मैदान में देखें, तो वाकई भाजपा की तैयारी काफी आगे दिख रही है. जोगी कांग्रेस केवल एक साल पुरानी पार्टी है, लेकिन जोर-आजमाइश के बावजूद वह तैयारियों में भाजपा से पीछे है. वहीं, कांग्रेस तीन साल से प्रेस कॉन्फ्रेंस और बयानबाजी के दौर से आगे नहीं निकल पाई है.

तीन बार सत्ता में रहने के बाद भाजपा चौथी बार सत्ता में आने की मुश्किलों से बखूबी वाकिफ है. इसलिए सरकार और संगठन के स्तर पर उसके कार्यकर्ता और नेता लगातार सक्रिय हैं. प्रदेश के मुखिया रमन सिंह हर साल सुराज अभियान के तहत पूरे प्रदेश में जाते हैं. लोगों से मिलकर उनकी समस्याएं सुनते हैं. संगठन के स्तर पर भी पार्टी के मुखिया धरमलाल कौशिक पूरा प्रदेश नाप चुके हैं. तैयारियों को लेकर भाजपा कितनी गंभीर है, इसका अंदाज़ा इसी बात से लगा सकते हैं कि देश की सबसे बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह खुद तीन दिनों तक रायपुर में रुके रहे और तैयारियों का जायज़ा लिया.

पार्टी का फोकस बूथ पर है. पार्टी दीनदयाल उपाध्याय जन्म शताब्दी वर्ष के अवसर पर उसके कार्यकर्ता हर बूथ पर जा रहे हैं. पार्टी के राष्ट्रीय नेता और राज्य स्तर के बड़े पदाधिकारी प्रदेश के हर हिस्से में लगातार बैठकें कर सरकार के काम को जनता के बीच पहुंचा रहे हैं और संगठन के काम को मज़बूती प्रदान कर रहे हैं. आरएसएस के अनुषांगिक संगठन लगातार काम कर रहे हैं. वे अलग-अलग कार्यक्रमों के जरिए लगातार पूरे प्रदेश में सक्रिय हैं.

दूसरी तरफ अजीत जोगी की पार्टी है. जबसे पार्टी बनी है तब से अजीत जोगी लगातार दौरे कर रहे हैं. वे महज़ एक साल में तीन सौ से ज्यादा सभाओं को संबोधित कर चुके हैं. पार्टी ने अपना घोषणा पत्र शपथ पत्र के माध्यम से डेढ़ साल पहले ही जारी कर दिया. चाहे किसानों का मुद्दा हो या आउटसोर्सिंग का. मुद्दों को किस तरह से आगे बढ़ाना है, ये खूबी उनके पास है. संगठन के स्तर पर जनता कांग्रेस भाजपा के स्टाइल में काम कर रही है. भाजपा की तरह वे कार्यकर्ताओं की फौज तैयार कर रहे हैं. पार्टी का दावा है कि उसने एक साल में ही दस लाख सदस्य बना लिए हैं, जो कांग्रेस के सदस्यों की संख्या से ज़्यादा हैं. सोशल मीडिया पर पार्टी बेहद सक्रिय है. पार्टी इसी महीने से 'जन-जन जोगी' कार्यक्रम के तहत अपने शपथ पत्र को घर-घर लेकर जाएगी.

कांग्रेस की बात करें तो पार्टी कई समस्याओं और सवालों के साथ खड़ी दिख रही है. पार्टी में गुटबाज़ी इतनी जबरदस्त है कि भूपेश बघेल को कुर्सी से हटाने के लिए कई बड़े नेता लगे हैं. फिलहाल वे काम करने से ज्यादा कुर्सी बचाने की जद्दोजहद में जुटे हैं. अभी तक ये भी साफ नहीं है कि चुनाव के दौरान प्रदेश का प्रभारी महासचिव कौन होगा? वर्तमान प्रभारी बीके हरिप्रसाद इस्तीफा दे चुके हैं. हालांकि उनका इस्तीफा नामंजूर हो चुका है. संगठन स्तर पर चल रही उथल-पुथल और अनिश्चितता का असर संगठन के काम-काज पर पड़ रहा है. अजीत जोगी ने कांग्रेस को पीसीसी दफ्तर में रहने वाली पार्टी करार दिया है.

पार्टी में संगठन चुनाव होने हैं, जो लगातार टल रहे हैं. पार्टी के बड़े नेता इंतज़ार कर रहे हैं कि संगठन चुनाव हो जाए, तब फिर मैदान में उतरा जाए. पार्टी प्रवक्ताओं के पास केवल यही दलील है कि कांग्रेस के काम-काज का यही तरीका है, लेकिन सवाल ये है कि क्या इन तरीकों को आजमाकर आज चुनाव जीता सकता है? हालांकि संगठन के स्तर पर कांग्रेस ने कुछ काम करना शुरू किया है. हर विधानसभा को सेक्टर में बांटकर कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग दी जा रही है. उन्हें एक्सपर्ट के जरिए सोशल मीडिया के गुर सिखाए जा रहे हैं. पार्टी ने अब तक सात विधानसभा के कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग दे दी है. लेकिन संगठन स्तर पर बैठकों के जरिए जो रणनीति तय होनी चाहिए, उस पर अब तक कोई काम शुरू नहीं हुआ है.

पिछली बार जब विधानसभा चुनाव के नतीजे आए थे, तब उसके कई कारण गिनाए गए. उस दौरान एक कांग्रेस नेता का अपने भाजपा के दोस्त को भेजा गया बधाई संदेश काफी चर्चा में रहा था. उसने कहा कि आपकी पार्टी इसलिए जीत गई क्योंकि आपकी पार्टी ने चुनाव को लड़ा और हम केवल देखते रह गए. इस बार के चुनाव में जीतेगी एक पार्टी और देखेगी दो पार्टी. ■

feedback@chauthiduniya.com

# किसानों की मौत पर सियासत

रूपेश गुप्ता

आज की तारीख़ में छत्तीसगढ़ की राजनीति के केंद्र में किसान हैं. किसान आंदोलन के बाद से दो किसानों की आत्महत्या की खबर आई है. मृतक किसानों के परिजनों का कहना है कि किसानों ने आत्महत्या कर्ज़ की वजह से की है, लेकिन प्रशासन का कहना है कि मौत की वजह पारिवारिक कलह थी. इस घटना के बाद ही कांग्रेस अध्यक्ष भूपेश बघेल मृतक किसान के घर मिलने के लिए रवाना हो गए थे. इस पर तंज कसते हुए प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष धरमलाल कौशिक ने कहा कि किसान आंदोलन राजनीति से प्रेरित है और विपक्ष इसे भड़काने की कोशिश कर रहा है. इस बीच प्रशासन ने राजनांदगांव के किसान भूषण गायकवाड़ की मौत की वजह पारिवारिक कलह बताया. इसका कारण बताया गया कि भूषण ने सुसाइड नोट में अपनी प्रॉपर्टी में पत्नी को हिस्सा नहीं देने की बात कही है. इस मामले की जांच कर रहे अशोक साहू से जब चौथी दुनिया ने बात की तो उन्होंने बताया कि यह मामला पूरी तरह से पति-पत्नी के विवाद का है. सुसाइड नोट में कहीं भी आर्थिक कारण का ज़िक्र नहीं किया गया है. न ही किसी परिजन ने अपने बयान में ऐसी कोई बात कही है.

इस मामले में जब भूषण गायकवाड़ के भाई जीवराखन गायकवाड़ से बात की गई, तो उन्होंने बताया कि उनके भाई पर 8-10 लाख रुपए कर्ज था, जिसमें उसके ट्रैक्टर की किस्त और बाज़ार का कर्ज़ भी शामिल है. इसके अलावा केसीसी लोन भी है. कुछ दिन पहले उसकी पिकअप दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी, जिसे बनाने में काफी खर्च आया था. हालांकि पुलिस का कहना है कि भूषण के पिकअप का केवल टायर फटा था. जीवराखन बताते हैं कि उसकी 10 एकड़ में लगी करेले की फसल खराब हो गई थी, जिसके कारण वो काफी निराश था. हालांकि वे मानते हैं कि भूषण का अपनी पत्नी से अक्सर विवाद रहता था. इसके बावजूद उनका कहना है कि अगर सिर्फ पारिवारिक दबाव का मामला होता, तो भूषण इतना बड़ा कदम नहीं उठाता. आर्थिक कारणों ने उसे अंदर-ही-अंदर तोड़ दिया था. उस पर काफी कर्ज चढ़ गया था. सवाल है कि जो बात किसान के परिजन बता रहे हैं, उसे पुलिस जान-बूझकर झूठ क्यों साबित करना चाहती है?

छत्तीसगढ़ किसान मजदूर महासंघ के प्रतिनिधि राजकुमार गुप्ता भी मौत की यही वजह बता रहे हैं, जो भूषण के भाई जीवराखन गायकवाड़ ने कही है. राजकुमार गुप्ता रविवार को भूषण के घर गए थे. उनका कहना है कि उसके खेतों में चार बोर लगे थे, जिसमें से 2 खराब हो गए थे. गुप्ता का कहना है कि मामला मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के क्षेत्र का होने के कारण स्थानीय प्रशासन लीपापोती में लगा है. गुप्ता का आरोप है कि राज्य में किसानों की आत्महत्या को पुलिस और प्रशासन तथ्यहीन रिपोर्ट पेश कर दबाना चाहती है. दुर्ग के किसान कुलेश्वर देवांगन ने 12 जून को खुदकुशी कर ली थी. राजकुमार गुप्ता ने बताया कि प्रशासन ने कुलेश्वर को मानसिक रूप से कमज़ोर बता दिया, जो संविधान के आर्टिकल 21 का खुल्लमखुल्ला उल्लंघन है. उन्होंने कहा कि बिना किसी मेडिकल जांच के प्रशासन ने कुलेश्वर को मानसिक कमज़ोर कैसे बता दिया? उन्होंने कहा कि इस मामले को वे जल्द मानवाधिकार आयोग लेकर जाएंगे. राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों के अनुसार, देश में खुदकुशी करने वाले किसानों के साथ आर्थिक परेशानियों के अलावा अन्य वजहें भी जुड़ी रहती हैं. करीब 11.7 प्रतिशत खुदकुशी करने वाले किसान पारिवारिक परेशानियों और 2 प्रतिशत शादी की समस्या से जूझ रहे होते हैं. लेकिन

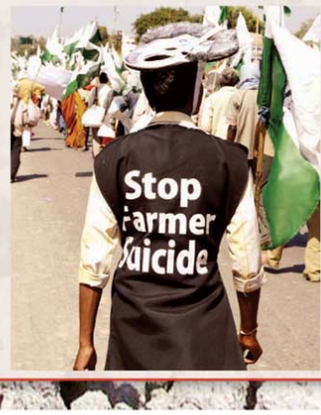

छत्तीसगढ़ में शासन को जब आत्महत्या करने की दूसरी वजह मिल जाती है, तो पहली ठोस वजह खारिज़ कर दी जाती है.

अगर राजकुमार गुप्ता के आरोप सही हैं, तो फिर सवाल है कि आखिर क्यों पुलिस और प्रशासन किसी भी किसान की खुदकुशी पर पर्दा डालने में जुट जाती है? दरअसल, पूरे देश में किसान आंदोलन को लेकर माहौल गर्म है. मध्यप्रदेश में हालात काफी गंभीर हैं और उसकी आंच छत्तीसगढ़ तक भी पहुंच रही है. कांग्रेस और जेसीसी दोनों ही विरोधी पार्टियों ने इस मुद्दे को मजबूती से पकड़ रखा है. सरकार पहले ही 2100 रुपए धान का समर्थन मूल्य और 300 रुपए बोनस देने का अपना चुनावी वादा नहीं निभा पाई है. लिहाज़ा किसानों की मौत की सच्चाई सरकार की मुश्किलें और बढ़ा सकती है. सरकार के लिए परेशानी की बात यह है कि किसान लगातार आत्महत्या कर रहे हैं. राजनांदगांव में ही एक और किसान ने खुदकुशी कर ली है. मुख्यमंत्री के गृहक्षेत्र कवर्धा में लोहारा ब्लॉक के 60 साल के किसान रामझूल साहू ने फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली है. हालांकि प्रशासन का कहना है कि उसके मौत की वजह का पता नहीं चला है. पुलिस को आशंका है कि उसने सांस की बीमारी से परेशान होकर खुदकुशी कर ली होगी. सरकार के लिए परेशानी का सबब यह है कि मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के उस बयान के बाद भी किसान आत्महत्या कर रहे हैं, जिसमें उन्होंने कहा था कि प्रदेश में किसानों की स्थिति बहुत अच्छी है. यहां किसान अपना सारा कर्ज वापस कर देते हैं, क्योंकि उन्हें ऋण पर कोई ब्याज़ नहीं लगता. आंकड़ों के मुताबिक ये करीब सालाना 3200 करोड़ रुपये का है. सवाल यह है कि आखिर इसके बाद भी किसान क्यों खुदकुशी कर रहे हैं? सच यही है कि सरकार की कई कल्याणकारी योजनाओं के बाद भी किसान आत्महत्या करने को मजबूर हैं.

दरअसल सरकार आंकड़ों की बाज़ीगरी कर अपनी छवि पेश कर रही है. सरकारी आंकड़ों के मुताबिक प्रदेश में 32 लाख किसान हैं. इनमें से इस ऋण की पात्रता प्रदेश के करीब 10 लाख 50 हज़ार उन किसानों तक है, जो नाबार्ड में पंजीकृत हैं. प्रदेश में 76 फीसदी सीमांत और लघु किसान हैं, जो इसके दायरे से बाहर हैं.

सरकार जिस ऋण को शून्य ब्याज़ दर पर देने की बात कहती है, वह केवल अल्पकालीन कृषि ऋण है जो खाद और बीज के लिए दिए जाते हैं. यानी जो इस ऋण के दायरे में हैं, उन्हें भी केवल खाद और बीज के लिए शून्य प्रतिशत दर पर कर्ज़ मिलता है. जबकि ट्रैक्टर समेत खेती के अन्य उपकरणों और महंगे कीटनाशकों के लिए बाजार दर पर ऋण लेना होता है. जिन लोगों को बैंक से लोन नहीं मिल पाता, वे लोग साहूकारों से कर्ज लेने को विवश हैं, जिसकी दर ज़्यादा होती है. बैंक हो या साहूकार ऋण वसूली को लेकर वे किसानों पर जबरदस्त दबाव डालते हैं. बैंक व साहूकार के आदमी किसानों के घर वसूली के लिए बार-बार पहुंच जाते हैं. एक ग्रामीण परिवेश में किसानों के लिए यह स्थिति बहुत ही अपमानजनक होती है.

राज्य का प्रशासनिक तंत्र किसी किसान की खुदकुशी को इस आधार पर खारिज करने की कोशिश करता है कि किसान साधन-संपन्न था. लेकिन संपन्न किसान के आत्महत्या करने की बड़ी वजह उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचना है. समस्या ये है कि सिर्फ छत्तीसगढ़ ही नहीं, बल्कि पूरे देश में किसानों के लिए ऐसी कोई लोककल्याणकारी योजना नहीं है, जो उन्हें बाज़ार के कर्ज़ जाल से बाहर निकाल सके. फिर सत्ता चाहे बीजेपी की हो या कांग्रेस की, इसलिए देश में किसानों की खुदकुशी रुक नहीं रही है. ■

feedback@chauthiduniya.com

# जीएसटी के लिए अभी तैयार नहीं देश

अगर 1 जुलाई, 2017 से माल और सेवा कर (जीएसटी) लागू होता है तो केवल एक राज्य में परिचालन के साथ एक लघु-स्तरीय विनिर्माण कंपनी को कम से कम 37 रिटर्न फाइल करनी होगी. हम बता दें कि मौजूदा समय में 13 रिटर्न फाइल करनी पड़ती है. इंडियास्पेंड द्वारा किए गए विश्लेषण के अनुसार, इससे उद्योग, एकाउंट और बैंकों के लिए काम बढ़ेगा.

जीएसटी के लिए एक महीने से भी कम की समय सीमा है और ऐसा लगता है कि वित्त पेशेवर, बैंक और उद्योग 'एक राष्ट्र-एक टैक्स' लागू करने की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार नहीं हैं. देश में 'एक राष्ट्र-एक टैक्स' लागू करने का विचार 13 वर्ष पहले शुरू किया गया था. 'इन्स्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया' के पूर्व अध्यक्ष के रघु ने इंडियास्पेंड से बात करते हुए बताया, जीएसटी को स्वीकार करने के लिए पूरे पारिस्थितिकी तंत्र को बदलना होगा. इसे लागू करने के लिए एक आदर्श तिथि 1 सितंबर होगी. 237 बैंकों का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था द इंडियन बैंक्स एसोसिएशन ने एक संसदीय पैनल को सूचित किया है कि उनके सदस्य नए अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था को लागू करने के लिए अभी तैयार नहीं हैं.

5 जून, 2017 को छपे इकोनॉमिक टाइम्स की इस रिपोर्ट के अनुसार, अब सब कुछ ऑनलाइन होगा और उन्हें नियमित रूप से अपडेट करने की आवश्यकता होगी. एक व्यवसाय को प्रति राज्य, सालाना 37 रिटर्न फाइल करना होगा यानि प्रति माह तीन रिटर्न और एक वार्षिक रिटर्न. अगर कोई कंपनी एक से अधिक राज्यों में अपने कार्यालयों से व्यवसाय करता है, तो रिटर्न की संख्या उसी अनुसार बढ़ेगी. यदि किसी व्यावसायिक कंपनी का तीन राज्यों में कार्यालय है, तो उसे प्रति वर्ष 111 रिटर्न फाइल करना होगा.

सरकार ने चार तरह के कर दर के लिए जीएसटी की घोषणा की है-5 फीसदी, 12 फीसदी, 18 फीसदी और 28 फीसदी. इसके साथ ही उद्योग को इसे अमल में लाने के लिए चुनौतियों का सामना करना होगा. इन चुनौतियों में सिस्टम अपग्रेड, मानवशक्ति प्रशिक्षण और नए करों को समझना शामिल है. बिक्री या खरीद, प्रत्येक लेन-देन का पहले भुगतान किए गए टैक्स से लाभ उठाने के लिए अब ऑनलाइन रिकॉर्ड करना होगा.

## केंद्रीय और राज्य जीएसटी और संघवाद की चुनौतियां

भारत केंद्र और राज्य के साथ आम कर आधार पर दोहरी जीएसटी लागू कर रहा है. अप्रत्यक्ष करों का केंद्रीय निकाय 'सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम्स' (सीबीईसी) द्वारा प्रकाशित अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों की इस सूची के अनुसार, केंद्र द्वारा वस्तुओं और सेवाओं की अंतराल आपूर्ति पर लगाए जाने वाले जीएसटी को केंद्रीय जीएसटी (सीजीएसटी) कहा जाएगा और राज्यों द्वारा लगाए जाने वाले राज्य जीएसटी (एसजीएसटी) कहा जाएगा.

**भारत केंद्र और राज्य के साथ आम कर आधार पर दोहरी जीएसटी लागू कर रहा है. अप्रत्यक्ष करों का केंद्रीय निकाय 'सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम्स' (सीबीईसी) द्वारा प्रकाशित अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों की इस सूची के अनुसार, केंद्र द्वारा वस्तुओं और सेवाओं की अंतराल आपूर्ति पर लगाए जाने वाले जीएसटी को केंद्रीय जीएसटी (सीजीएसटी) कहा जाएगा और राज्यों द्वारा लगाए जाने वाले राज्य जीएसटी (एसजीएसटी) कहा जाएगा.**

सीबीईसी एफएक्यू कहती है, इसी तरह, इंटीग्रेटेड जीएसटी (आईजीएसटी) माल और सेवाओं की हर अंतरराज्यीय आपूर्ति पर केंद्र द्वारा लगाया और प्रशासित किया जाएगा.

दोहरी जीएसटी राजकोषीय संघवाद की संवैधानिक आवश्यकता का पालन करता है, चूंकि केंद्र और राज्य दोनों के पास टैक्स लगाने और एकत्र करने की शक्तियां हैं.

सीबीईसी एफएक्यू के अनुसार, छूट वाले सामान और सेवाओं को छोड़कर, माल और सेवाओं की आपूर्ति के हर लेन-देन पर केंद्रीय जीएसटी और राज्य जीएसटी एक साथ लगाए जाएंगे. 24 राज्यों ने राज्य जीएसटी अधिनियम पारित किए हैं, लेकिन सात राज्यों ने अब तक नहीं किया है.

## जीएसटी की जटिलताओं को समझना आसान नहीं

जबकि देश के भीतर आपूर्तिकर्ता और ग्राहक का स्थान सीजीएसटी के प्रयोजन के लिए बेकार है, एसजीएसटी पर तब ही शुल्क लिया जाएगा, जब सप्लायर और ग्राहक राज्य के भीतर हों. सरकार द्वारा प्रकाशित एफएक्यू का एक उदाहरण देखें. मान लीजिए कि सीजीएसटी की दर 10 प्रतिशत और एसजीएसटी की दर 10 प्रतिशत है. जब उत्तर प्रदेश में स्टील का एक थोक व्यापारी एक निर्माण कंपनी को स्टील की सलाखों और छड़ों की आपूर्ति करता है, जो उसी राज्य के भीतर स्थित है; मान लें कि 100 रुपए में, डीलर 10 रुपए का सीजीएसटी और 10 रुपए का एसजीएसटी माल के मूल दाम में जोड़कर वसूल करेगा. उस सीजीएसटी की रकम केंद्र सरकार के खाते में जमा करनी है, जबकि एसजीएसटी के हिस्से की राशि संबंधित राज्य सरकार के खाते जमा करना आवश्यक होगा. जाहिर है, कि उसे वास्तव में 20 रुपए (1010 रुपए) नकद राशि में जमा करना आवश्यक नहीं होगा, क्योंकि वह इस दायित्व को अपनी खरीद पर भुगतान किए गए सीजीएसटी या एसजीएसटी के (इनपुट कहते हैं) के विरुद्ध समायोजित करने का हकदार होगा.

यह वह जगह है जहां इसे अमल में लाने में चुनौतियां उत्पन्न होती हैं, जैसा कि पूर्व आईसीएआई के अध्यक्ष के रघु कहते हैं. खरीदार और विक्रेताओं के हर चालान को जीएसटी सिस्टम में सही ढंग से दर्ज किया जाना चाहिए.

रघु कहते हैं, ज्यादातर छोटी इकाइयों में आज ऐसी प्रणाली है, जहां एकाउंटेंट महीने में एक बार आता है. वाउचर बनाता है और टैक्स के लिए जानकारी का विवरण देता है. अब यह संभव नहीं है, क्योंकि हम ऑनलाइन की ओर जा रहे हैं और समय के साथ चल रहे हैं. इसे करने में ज्यादा लोगों की जरूरत होगी.

रघु आगे कहते हैं, वित्त उद्योग अपने पेशेवरों को प्रशिक्षण देने के लिए तैयार है. रघु ने अगले 5-6 वर्षों में कई तरह के रोजगार के अवसरों की संभावना जताई है. लेकिन उनका मानना है कि इस सिस्टम को सुचारू रूप से चलने में कम से कम 12 से 18 महीने का समय लगेगा. वह कहते हैं, मैं आने वाले वर्षों में अप्रत्यक्ष करों के लिए प्रशिक्षित सीए और अन्य वित्त पेशेवरों के लिए अपार संभावनाएं देख रहा हूं.

## उद्योग और सेवा क्षेत्र अभी तैयार नहीं

भारत के उद्योग और उसके बैंकिंग सिस्टम को अपनी कार्य प्रणाली बदलनी होगी. कर्मियों को प्रशिक्षित करना होगा और नई कर प्रणाली के लिए अतिरिक्त कार्यभार को स्वीकार करना होगा. बैंकिंग सेक्टर ने स्पष्ट रूप से कहा है कि वह अभी तक तैयार नहीं है. उद्योग सेक्टर दुविधा में है. 'टैली सॉल्यूशंस' के प्रबंध निदेशक भारत गोयनका ने 5 जून, 2017 को 'द इकनॉमिक टाइम्स' में कहा है, लगभग 50 फीसदी भारतीय कारोबारी जीएसटी में आने वाले परिवर्तनों से अवगत नहीं हैं.

टैली अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर व्यापक रूप से भारतीय कंपनियों द्वारा उपयोग किया जाता है. द इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, कंपनी जीएसटी नियमों को अंतिम रूप देने के लिए इंतजार कर रही है, ताकि वह भारतीय कंपनियों के लिए अपने जीएसटी सॉफ्टवेयर निकाल सके.

फेडरेशन ऑफ द इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (एफआईसीसीआई) के एक वरिष्ठ अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि जीएसटी अब एक हकीकत है और उद्योग इसे अपनाने की कोशिश कर रहा है. उन्होंने कहा कि फिक्की उद्योगों के बीच जागरूकता सत्र आयोजित कर रहा है, ताकि वे नई संरचना को समझ सकें. औद्योगिक क्षेत्र विशेषकर सेवा क्षेत्र टैक्स दरों, प्रक्रियाओं और सिस्टम को व्यवस्थित करने के लिए समय सीमा पर अधिक स्पष्टता के लिए इंतजार कर रहे हैं.

गोवा में संचालित एक समुद्री सेवा प्रदाता ने नाम न छापने की शर्त पर इंडियास्पेंड से बताया कि, एक चीज जो हमें अब भी नहीं पता है वह यह कि हम किस कर स्लैब में आते हैं. हालांकि यह अच्छा है कि कर प्रणाली सुगम हो जाएगी और हमें एक्साइज, सर्विस टैक्स और वैल्यू एड कर जैसे कई कर भुगतानों से निपटना नहीं होगा, लेकिन हम अभी भी नहीं जानते हैं कि इसमें कितना वक्त लगेगा. ■

*(साभार इंडियास्पेंड)*

feedback@chauthiduniya.com

# हमारी संवेदनाएं दम तोड़ रही हैं

डॉ. सबा बुनुस

आइए, आज तफसील से बात करते हैं कानपुर शहर के बर्रा क्षेत्र स्थित न्यू जागृति अस्पताल की. एक महिला मरीज का आरोप है कि अस्पताल के वार्ड ब्वॉय ने उनके साथ दुष्कर्म किया.

अस्पताल का आईसीयू वार्ड एक ऐसी जगह है, जहां मरीजों को सबसे ज्यादा देखभाल की जरूरत होती है. यहां मरीजों के परिजनों का भी अनावश्यक रूप से जाने की मनाही होती है. इसका मकसद होता है कि मरीज़ ज्यादा से ज्यादा आराम कर सके और उचित मेडिकल प्रोसिजर से गुज़र कर सामान्य स्थिति में आ सके. वहां ऐसी घिनौनी हरकत? आईसीयू वार्ड में हमेशा मरीज की तीमारदारी के लिए अस्पताल का एक स्टाफ मौजूद होता है. वार्ड में भी एक नर्स मौजूद रहती है. फिर सवाल ये है कि वहां पुरुष स्टाफ की एंट्री कैसे हुई? यदि पीड़िता की जुबानी जानें, तो देखिए क्या हुआ था उस रोज़:-

वार्ड ब्वॉय मेरे कपड़े बदलने आया था. मैंने जब आपत्ति की और कहा कि किसी महिला स्टाफ को भेजो तो वो मुझसे बदतमीजी पर उतर आया और गन्दी गन्दी बातें बोलने लगा. फिर उसने मुझे बेहोशी का इंजेक्शन लगा कर मेरे साथ ग़लत काम किया.

अब सिर्फ और सिर्फ एक सवाल मन में उठता है-ये कैसा अस्पताल है, जहां महिला मरीज़ के कपड़े बदलवाने की ड्यूटी एक पुरुष स्टाफ को सौंप दी जाती है? एक अकेली महिला मरीज के कमरे में एक पुरुष स्टाफ की एंट्री कैसे दी गई? इस पूरे प्रकरण में जितना वार्ड ब्वॉय दोषी है, उतने ही दोषी अस्पताल के मैनेजमेंट से सम्बंधित लोग भी हैं. नियमों में शिथिलता होने पर ही जुर्म पनपता है. ऐसे में सवाल उठता है कि अस्पताल में मरीजों की सुरक्षा से

सम्बंधित नियमों पर प्रशासन ने ध्यान क्यों नहीं दिया?

लड़की के परिजनों ने बताया कि पुलिस ने एफआईआर लिखने से मना कर दिया. इतना ही नहीं, हॉस्पिटल मैनेजमेंट को बचाने के उद्देश्य से मामला ख़त्म करने के लिए भी दबाव बनाया गया.

अब सवाल ये उठता है कि जुर्म सहने के बाद इसके खिलाफ उठ खड़ा होना भी अपराध है क्या?

अगले दिन पब्लिक का गुस्सा फूटता है. भीड़ कई पुलिस कर्मियों के साथ मारपीट कर गंभीर रूप से घायल कर देती है. कह सकते हैं कि जब पुलिस अपना कर्तव्य नहीं निभा रही हो और उल्टा पीड़ित के परिजनों को ही सताने में लगी हो, तब आम जन के पास कोई उपाय बचता है? यहां भी पब्लिक ने कानून अपने हाथ ले लिया और पुलिस के साथ हाथापाई की. लेकिन इसमें एक गलत संदेश यह जाता है कि यदि सभी लोग कानून अपने हाथ में लेने लगेंगे और भीड़ अराजक बर्ताव करने लगी, तब यह देश और समाज के लिए खतरनाक संकेत है.

अब इस पूरे प्रकरण को समझते हुए जरूरत है गंभीर चिंतन की. चिंतन सामाजिक सुरक्षा और कानून व्यवस्था को लेकर. चिंतन नियमों की शिथिलता पर. चिंतन इंसान के गिरते नैतिक स्तर पर. साथ ही जरूरत है सरकार द्वारा अस्पतालों के लिए कड़े नियम लागू करने की. यदि कोई अस्पताल मरीज़ की सेहत और सुरक्षा से खिलवाड़ करे या अस्पताल नियमों का उल्लंघन करे तो तत्काल उसका लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाए. अस्पताल खोले जाने की मंजूरी तभी मिले, जब वे सभी मानकों व प्रावधानों को पूरा करें. हालांकि यह कोई पहला मामला नहीं है, लेकिन हुआ क्या-

वही हो-हल्ला, दो-चार दिन का बवाल और फिर वही पहले की तरह सब कुछ सामान्य. किसी अस्पताल का लाइसेंस रद्द नहीं हुआ, कोई कार्रवाई नहीं हुई, यदि कार्रवाई हुई भी तो कोई आरोप साबित नहीं हुआ. ऐसे मामलों में पीड़ा झेलने के लिए सिर्फ पीड़ित या उसका परिवार बचता है, जो थक-हारकर केस वापस लेने को मजबूर होता है.

हम बड़ी विचित्र और गंभीर सामाजिक व्यवस्था का हिस्सा बनते जा रहे हैं. हम तब तक किसी मुद्दे की गंभीरता को नहीं समझते जब तक वह हमसे जुड़ा नहीं हो. इंसान संवेदना खोता जा रहा है और धीरे-धीरे हिंसक भीड़ का हिस्सा बनता जा रहा है. यही वजह है कि समाज में अराजकता और अनैतिकता बढ़ रही है. हमें जरूरत है अपनी सुप्त पड़ी संवेदनाओं को जगाने की, ताकि हम दूसरों के दुःख तकलीफों को भी महसूस कर सकें.

न्यू जागृति अस्पताल की घटना भी मुश्किल से एक-दो दिन अखबारों की सुर्खियां बनी रहीं, लोगों ने आक्रोश दिखाया और फिर सब-कुछ ठंडे बस्ते में चला गया. किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा कि उस मरीज का क्या हुआ या इस मामले में पुलिस ने आगे क्या कार्रवाई की? हम बस तेज़ भागती हुई ज़िन्दगी का एक हिस्सा मात्र बनकर रह गए हैं. हमारी संवेदनाएं मर गई हैं. यदि हम चाहते हैं कि भविष्य में ये घटनाएं हमारे या हमारे परिवार के सदस्यों के साथ न घटे तो हमें सचेत होना पड़ेगा, हमको जागना पड़ेगा. उठिए, जागिए और झिंझोड़िए सरकार और कानून व्यवस्था को, ताकि इस तरह की घटनाएं दोबारा न हों. ■

*(लेखिका समाजशास्त्र की प्रोफेसर और सामाजिक कार्यकर्ता हैं)*

feedback@chauthiduniya.com

## झारखंड में किसान की पहली आत्महत्या से शासन पर उठे सवाल

# किसान आत्महत्या की शुरुआत

**वैसे दोनों किसानों की मौत की वजह चाहे जो रही हो, इससे कोई इंकार नहीं कर सकता कि झारखंड के छोटे किसान गंभीर आर्थिक संकट का सामना कर रहे हैं. यहां रोजगार का मुख्य साधन कृषि है, जो सिंचाई के अभाव में नाममात्र का लाभ देती है. प्रतिकूल मौसम रहने पर किसान भारी घाटे में आ जाते हैं. सूदखोर, बिचौलिए, दलाल सरकारी व्यवस्था पर भारी पड़ रहे हैं. किसी अधिकारी को इसके लिए जिम्मेदार भी नहीं ठहराया जाता है. यही कारण है कि किसान तंगहाली की ओर बढ़ रहे हैं, जबकि अफसर और दलाल मालामाल हो रहे हैं.**

प्रशान्त शरण

झारखंड में किसान द्वारा आत्महत्या की घटना भले ही पहली बार घटित हुई है, पर झारखंड में किसानों की हालत अत्यंत दयनीय है. लगभग 80 प्रतिशत अन्नदाता को दो जून की रोटी भी नसीब नहीं हो पाती है. अन्नदाता के परिजन अपने पेट में अन्न के लिए मजदूरी करने को विवश हैं. इधर नकली बीज और खाद ने किसानों की स्थिति ऐसी कर दी कि वे कर्ज में डूबते जा रहे हैं और अब आत्महत्या करने को मजबूर हैं. झारखंड की राजधानी रांची के पिठोरिया प्रखंड के दो किसानों ने आर्थिक तंगी से त्रस्त होकर अपनी जान दे दी. पिठोरिया के खेत काफी उर्वरा हैं और यहां के किसान कभी काफी सम्पन्न माने जाते थे, पर अब नकली बीज और खाद ने इनकी हालत काफी खस्ता कर दी है.

सबसे आश्चर्यजनक तथ्य तो यह है कि इन दोनों किसानों ने आत्महत्या तब की, जब मुख्यमंत्री रघुवर दास ने इस घटना के ठीक एक दिन पहले रांची में एक बड़े किसान सम्मेलन का उद्घाटन किया. इस दौरान उन्होंने किसानों के लिए दर्जनों कल्याणकारी योजनाओं की घोषणा की. उन्होंने किसानों से बड़े-बड़े वादे किए और किसानों को सबसे खुशहाल होने की बातें कही. आज किसानों के सामने जो यक्ष प्रश्न है, उस पर किसी का ध्यान नहीं जाता. किसानों के सामने आज सबसे बड़ी चुनौती खेती और पैदावार नहीं, बल्कि जिंदा रहने की जद्दोजहद है. सरकार की संवेदनहीनता की पराकाष्ठा यह है कि किसान आत्महत्या करने को मजबूर हैं, लेकिन इन परिस्थितियों के लिए किसी को जिम्मेवार नहीं ठहराया गया, केवल जांच कमेटी बनाकर औपचारिकता पूरी कर ली गई. हद तो तब हो गई, जब जिले के आलाधिकारियों ने दोनों किसानों की आत्महत्या पर ही सवाल खड़े कर दिए. एक किसान के बारे में तो यहां तक कहा गया कि वह नशे का आदी था और नशे में कुएं में गिर जाने से उसकी मौत हो गई, जबकि दूसरे किसान के बारे में भी कई तरह के सवाल खड़े कर उसकी आत्महत्या को संदिग्ध बताया गया. इस तरह के बयान से राज्य के किसानों में

**झारखंड में किसान पहली बार आत्महत्या करने को मजबूर हुए हैं. पिठोरिया के प्रगतिशील किसान कलेश्वर महतो ने फांसी लगाकर जान दे दी. कलेश्वर स्नातक था और उसने कई किसान प्रतियोगिताएं भी जीती थीं. परिवार वालों के अनुसार उसने बैंक से कर्ज लिया था और इस कर्ज के चुकता नहीं किए जाने से परेशान था. वैसे उसके पास 66 कट्ठा जमीन थी, पर इस बार उसकी फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई थी. उसने अपने सुसाइड नोट में अपनी मौत का कारण बैंक से लिए गए कर्ज और फसल का बर्बाद होना बताया है. उसके परिवार की आर्थिक स्थिति इतनी बदहाल थी कि उसकी मौत के बाद दाह संस्कार के लिए आसपास के लोगों से सहयोग लेना पड़ा.**

काफी आक्रोश है, जबकि किसान कर्ज के दबाव में आत्महत्या कर रहे हैं. यहां करोड़ों रुपए लोन लेने वाले ऐशो-आराम की जिंदगी जी रहे हैं, जबकि पचास हजार रुपए लोन लेने वाले किसान आत्महत्या करने को मजबूर हैं. मुख्यमंत्री रघुवर दास किसानों के प्रति कितने संवेदनशील हैं, यह इससे पता चलता है कि रांची से पन्द्रह किलोमीटर दूर पिठोरिया में पांच दिनों के भीतर दो किसानों ने आत्महत्या कर ली, पर मुख्यमंत्री ने पीड़ितों के परिजनों से मिलना भी जरूरी नहीं समझा. यहां तक कि उनके मंत्रिमंडल का भी कोई सदस्य वहां नहीं गया.

झारखंड में किसान पहली बार आत्महत्या करने को मजबूर हुए हैं. पिठोरिया के प्रगतिशील किसान कलेश्वर महतो ने फांसी लगाकर जान दे दी. कलेश्वर स्नातक था और उसने कई किसान प्रतियोगिताएं भी जीती थीं. परिवार वालों के अनुसार उसने बैंक से कर्ज लिया था और इस कर्ज के चुकता नहीं किए जाने से परेशान था. वैसे उसके पास 66 कट्ठा जमीन थी, पर इस बार उसकी फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई थी. उसने अपने सुसाइड नोट में अपनी मौत का कारण बैंक से लिए गए कर्ज और फसल का बर्बाद होना बताया है. उसके परिवार की आर्थिक स्थिति इतनी बदहाल थी कि उसकी मौत के बाद दाह संस्कार के लिए आसपास के लोगों से सहयोग लेना पड़ा. अभी इस घटना से राज्य के किसान एवं अन्य लोग उबर भी नहीं पाए थे कि ठीक पांच दिन बाद एक और किसान बालदेव महतो ने कर्ज से तंग आकर आत्महत्या कर ली. बलदेव का बड़ा भाई सत्यनारायण महतो भी दो बार आत्महत्या की कोशिश कर चुका है. बलदेव के पास 51 डिस्मिल जमीन थी. सिंचाई के लिए उसने दो बार कुआं खोदने की कोशिश की, पर सफल नहीं हो सका. बलदेव ने तो खेती के लिए लोन लिया ही था, उसकी पत्नी ने भी महिला समिति से 20 हजार रुपए का कर्ज ले रखा था. बलदेव के परिवार का आरोप है कि जितने पैसे खेती में लगते थे, उसका उत्पादन मूल्य भी नहीं मिल पाता था. इस बार दो-दो फसलें क्षतिग्रस्त हो गईं. अपने परिवार का पेट भरने के लिए बलदेव मजदूरी करने लगा, पर वह कर्ज के दबाव से परेशान था और आखिर में परेशान होकर उसने आत्महत्या कर ली. वैसे रांची के आला अधिकारी इस बात से इंकार करते हैं कि उसने आत्महत्या की है. अधिकारियों का मानना है कि नशे में कुएं में गिर जाने से उसकी मौत हो गई.

यहां के किसानों का कहना है कि सरकारी योजनाओं का लाभ उनलोगों को नहीं मिल पाता है. फसल क्षति के बाद भी बीमा का पैसा नहीं मिलता है. सिंचाई की कोई व्यवस्था नहीं होने के कारण किसानों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है. बिचौलिए किसानों पर हावी हैं और पूरा लाभ ले जाते हैं, पर सरकारी अमला इसपर ओर कोई कदम नहीं उठाता. किसानों की आत्महत्या की घटना को सरकार को गंभीरता से लेना होगा. एक तरफ तो राज्य सरकार किसानों की आय दोगुनी करने के लिए पूरे राज्य में कृषि जागृति अभियान चला रही है, इसके बावजूद किसान आत्महत्या कर रहे हैं. झारखंड के छोटे और सीमांत किसानों की जरूरतें बहुत छोटी हैं, लेकिन विडंबना यह है कि सरकारी तंत्र किसानों की इन जरूरतों को भी पूरी नहीं कर पाते हैं. किसानों के हितों के लिए दर्जनों योजनाएं चलाई जा रही हैं, पर ये योजनाएं उन तक पहुंच ही नहीं पाती हैं. स्पष्ट है कि राज्य सरकार का मौजूदा तंत्र इसके लिए पूरी तरह से जिम्मेवार है. किसानों को अपनी फसल का उचित मूल्य नहीं मिल पाता है. धान खरीद में भी घोटाले हुए थे, इस बात को स्वयं खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री सरयू राय ने स्वीकार किया था. नकली बीज एवं खाद से भी किसान परेशान हैं. रांची के अनुमंडल पदाधिकारी ने जब नकली खाद बीज का रैकेट पकड़ा, तब उस अधिकारी का आनन-फानन में स्थानांतरण कर दिया गया और कारोबारियों को भाजपा सरकार ने बचा लिया.

वैसे दोनों किसानों की मौत की वजह चाहे जो रही हो, इससे कोई इंकार नहीं कर सकता कि झारखंड के छोटे किसान गंभीर आर्थिक संकट का सामना कर रहे हैं. यहां रोजगार का मुख्य साधन कृषि है, जो सिंचाई के अभाव में नाममात्र का लाभ देती है. प्रतिकूल मौसम रहने पर किसान भारी घाटे में आ जाते हैं. सूदखोर, बिचौलिए, दलाल सरकारी व्यवस्था पर भारी पड़ रहे हैं. किसी अधिकारी को इसके लिए जिम्मेदार भी नहीं ठहराया जाता है. यही कारण है कि किसान तंगहाली की ओर बढ़ रहे हैं, जबकि अफसर और दलाल मालामाल हो रहे हैं.

इधर मुख्यमंत्री रघुवर दास ने किसानों की आत्महत्या को गंभीर बताते हुए कहा कि सरकार किसानों के विकास एवं उनकी आय में वृद्धि को लेकर कृतसंकल्प है. राज्य में किसानों के हित में दर्जनों योजनाएं चल रही हैं. फसल बीमा योजना का लाभ भी किसानों को दिया जा रहा है. किसानों द्वारा लिए गए ऋण पर ब्याज की दरों में भारी कमी की गई है, ताकि राज्य के किसान समृद्ध और प्रगतिशील हो सकें. किसानों को बिचौलियों से मुक्त करने के लिए भी योजना शुरू की गई है. इससे किसानों को अपनी फसल का सही दाम और बाजार मिल सकेगा.

नेता प्रतिपक्ष एवं राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि भाजपा सरकार को किसानों से कोई लेना-देना नहीं है. रघुवर दास किसानों की मौत पर केवल घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं. यहां सरकार पूंजीपतियों की है और किसानों की जमीन छीनकर औद्योगिक घरानों को देने की साजिश चल रही है. अगर मुख्यमंत्री किसानों के प्रति इतने संवेदनशील रहते तो नकली बीज और खाद रैकेट चलाने वाले गिरोह का पर्दाफाश करने वाले आईएएस अधिकारी का स्थानान्तरण नहीं होने देते. भाजपा सरकार ही इनलोगों को संरक्षण देने का काम कर रही है. जो भी हो किसानों की मौत पर लोगों या राजनीतिक दलों को राजनीति नहीं कर किसानों की हालत कैसे सुधरे, इस पर विचार करना चाहिए. ■

feedback@chauthiduniya.com

## किसानों को कम ब्याज पर मिलेगा ऋण : रघुवर दास

रांची के पिठोरिया में किसानों की आत्महत्या को गंभीरता से लेते हुए मुख्यमंत्री रघुवर दास ने इस पूरे मामले की जांच एसआईटी से कराने के आदेश दिए हैं. उन्होंने कहा कि किसान ने किस परिस्थिति में आत्महत्या की, यह देखना होगा. मुख्यमंत्री ने बताया कि किसानों की आर्थिक स्थिति को देखते हुए कृषि ऋण पर ब्याज में तीन फीसदी की छूट दी जाएगी. केन्द्र सरकार पहले ही तीन प्रतिशत की छूट दे रही है. किसानों को सात प्रतिशत ब्याज पर कृषि ऋण दिया जा रहा है. किसानों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के साथ ही खेती से संबंधित मशीनें भी अनुदान पर दी जा रही हैं. पूरे राज्य में दो लाख से अधिक डोभा, तालाब की खुदाई एवं कुओं का निर्माण कराया गया है. राज्य में किसानों की आर्थिक खुशहाली हेतु कई योजनाएं चलाई जा रही हैं, बीज एवं खाद अनुदानित दर पर मुहैया कराने के निर्देश अधिकारियों को दिए गए हैं. सोलर लाइट से भी किसानों को लाभ मिलेगा. उन्नत विधि से पैदावार करने की विधि भी किसानों को बताई जा रही है. इसके लिए किसान मेला, किसान प्रशिक्षण योजना एवं किसानों को दूसरे राज्यों की यात्रा कराई जा रही है, ताकि यहां के किसान उन्नत तरीके से उत्पादन की विधि सीख सकें. ■

## किसानों का क़र्ज़ माफ़ करे सरकार : हेमंत

झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष एवं राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने किसानों की दुर्दशा के लिए भाजपा सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि केवल बड़ी-बड़ी घोषणा की जाती है, पर उसे अमल में नहीं लाया जाता है. बड़े व्यवसायियों को बड़ी राशि कर्ज में दी जा रही है, पर किसानों को प्रताड़ित किया जा रहा है. उन्होंने सरकार से किसानों को दिए गए कर्ज माफ करने के साथ ही किसानों की खेती के लिए सिंचाई समेत अन्य वैकल्पिक सुविधाएं देने की भी मांग की है. उन्होंने कहा कि सरकार अगर किसानों के प्रति संवेदनशील नहीं हुई तो झामुमो पूरे राज्य में आंदोलन खड़ा करेगा. इस आंदोलन में अन्य दलों को भी शामिल किया जाएगा. उन्होंने कहा कि किसानों की संख्या धीरे-धीरे घट रही है, किसान अब मजदूर बनते जा रहे हैं. खेती के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं होने और कर्ज में डूबने की वजह से अब किसान आत्महत्या कर रहे हैं. राज्य सरकार को किसानों से कोई मतलब नहीं रह गया है. सरकार सिर्फ राजनीति कर रही है.

पूर्व मुख्यमंत्री सोरेन कहते हैं, भाजपा सरकार की यह मंशा है कि किसानों को इतना परेशान किया जाए कि वे खेती करना छोड़ दें और इस जमीन को भाजपा उद्योगपतियों के हाथों सौंप दें. इस साजिश के तहत ही सीएनटी एसपीटी एक्ट लाया गया और अब किसानों को जमीन से बेदखल करने का काम किया जा रहा है. अगर सरकार अब भी नहीं चेती तो सड़क से लेकर सदन तक उग्र आंदोलन चलाया जाएगा. ■

## रघुवर सरकार की नीयत साफ़ नहीं : सुखदेव

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सुखदेव भगत ने आरोप लगाया कि रघुवर सरकार की नीयत साफ नहीं है. रघुवर सरकार मामले को रफा-दफा करने में लगी हुई है. किसानों की समस्याओं से इस सरकार को कोई लेना-देना नहीं है. उन्होंने राज्य सरकार से दोनों किसानों के परिवारों को मुआवजा देने की मांग की. प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि राजधानी में दो-दो किसानों ने आत्महत्या कर ली, पर मुख्यमंत्री पीड़ित परिवारों की स्थिति जानने नहीं गए, अगर कॉरपोरेट घराने में यह घटना होती तो मुख्यमंत्री दौड़े चले जाते. सरकार को अपनी नीति और मंशा स्पष्ट करनी चाहिए. उन्होंने राज्य में किसानों के लिए सिंचाई सुविधा और अन्य बुनियादी सुविधाएं देने की मांग के साथ ही किसानों का कर्ज माफ करने की मांग राज्य सरकार से की है. ■

# प्रतिशोध की भावना देशहित में नहीं

www.kamalmorarka.com

कमल मोरारका

**मेरी राय में सरकार की पसंद बेहतर है. विपक्ष को एकमत से यह चुनाव होने देना चाहिए. इस आधार पर किसी व्यक्ति के विरोध करने का कोई मतलब नहीं है कि वे भाजपा और आरएसएस से जुड़े रहे हैं. स्वाभाविक रूप से यह उनकी सरकार है. कांग्रेस ने हमेशा ऐसे व्यक्ति का चयन किया है जो या तो कांग्रेस का हिस्सा रहे हों या फिर उसके करीब रहे हों. ऐसे में आप बीच में नियम को नहीं बदल सकते. मेरी राय में राष्ट्रपति का चुनाव कोई मुद्दा नहीं बनना चाहिए. प्रधानमंत्री और सत्तारूढ़ दल को उपराष्ट्रपति का चयन भी सावधानीपूर्वक करना चाहिए. ऐसे किसी गरिमापूर्ण व्यक्ति को ही उपराष्ट्रपति बनाया जाना चाहिए, जो राज्यसभा में अपनी विश्वसनीयता बहाल कर सके.**

सरकार ने राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के चयन को लेकर काफी देर से कदम उठाया है. प्रधानमंत्री को यह काम बहुत पहले कर लेना चाहिए था. परंपरागत रूप से राष्ट्रपति का पद सत्तारूढ़ दल द्वारा प्रायोजित किया जाता है. कुछेक बार चुनाव हुए हैं, कभी-कभी केवल औपचारिक चुनाव होते हैं. एक बार सिर्फ कांग्रेस के दो धड़ों द्वारा प्रायोजित दो उम्मीदवारों के बीच वास्तविक चुनाव हुआ था. यह वांछनीय है कि राष्ट्रपति एक ठीक-ठाक कद का व्यक्ति होना चाहिए और उन्हें अन्य सामाजिक-आर्थिक कारकों को पूरा करना चाहिए. इसे लेकर सरकार को पहले ही अपना रुख स्पष्ट करना चाहिए, ताकि इस पर आम सहमति बन सके. हमेशा की तरह, सरकार ने आखिरी पल में नाम घोषित किया और विपक्ष को सकते में डाल दिया. सरकार के रुख को भांपते हुए विपक्ष इस मुद्दे पर पहले से कोई तैयारी नहीं कर पाया. मेरी राय में सरकार की पसंद बेहतर है. विपक्ष को एकमत से यह चुनाव होने देना चाहिए. इस आधार पर किसी व्यक्ति के विरोध करने का कोई मतलब नहीं है कि वे भाजपा और आरएसएस से जुड़े रहे हैं. स्वाभाविक रूप से यह उनकी सरकार है. कांग्रेस ने हमेशा ऐसे व्यक्ति का चयन किया है जो या तो कांग्रेस का हिस्सा रहे हों या फिर उसके करीब रहे हों. ऐसे में आप बीच में नियम को नहीं बदल सकते. मेरी राय में राष्ट्रपति का चुनाव कोई मुद्दा नहीं बनना चाहिए. प्रधानमंत्री और सत्तारूढ़ दल को उपराष्ट्रपति का चयन भी सावधानीपूर्वक करना चाहिए. ऐसे किसी गरिमापूर्ण व्यक्ति को ही उपराष्ट्रपति बनाया जाना चाहिए, जो राज्यसभा में अपनी विश्वसनीयता बहाल कर सके.

अब एक गंभीर मसले पर आते हैं और वह है कृषि क्षेत्र. किसान आत्महत्याओं के बारे में सब जानते हैं, लेकिन अब यह एक संक्रामक बीमारी की तरह फैल चुका है. झारखंड के किसान आत्महत्या कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ में आत्महत्या हो रही है और मध्य प्रदेश में बड़ी संख्या में किसानों ने आत्महत्या की है. यह ठीक नहीं है. सरकार को यह समझना चाहिए कि 80 प्रतिशत भारतीय जनसंख्या कृषि पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्भर करती है. यदि किसान हिंसक या असंतुष्ट हो जाते हैं, तो कोई सरकारी अमला या कानून-व्यवस्था का रक्षक उस स्थिति को नियंत्रित नहीं कर सकता है. कानून और व्यवस्था की एक समस्या के रूप में कश्मीर या छत्तीसगढ़ को संभालना एक अलग बात है. अर्थव्यवस्था के लिए कृषि क्षेत्र कहीं अधिक महत्वपूर्ण है. जैसा मैंने पहले भी कहा था, सरकार को चाहिए कि वह विभिन्न हितधारकों के साथ बातचीत करे. सरकार एमएस स्वामीनाथन, वाईके अलघ जैसे विशेषज्ञों से विचार-विमर्श करे, ताकि वे लोग ये बता सकें कि इस स्थिति से कैसे बाहर निकला जाए. ये लोग सरकार को बेहतर विचार दे सकते हैं. मैं सरकार की स्थिति समझता हूं. सरकार को जितनी धनराशि की आवश्यकता है, उसके पास उतना पैसा है नहीं. ऐसे में चुनाव से पहले यह कहना मूर्खतापूर्ण है कि हम लागत पर अतिरिक्त 50 फीसदी पैसा देंगे या सरकार में आने के बाद हम किसानों की आय 6 साल में दोगुनी कर देंगे. ये लक्ष्य आसानी से प्राप्त नहीं किए जा सकते हैं. सरकार को और नुकसान उठाने को लेकर आगे सावधान रहना चाहिए. सरकार जितनी जल्दी स्थिति पर काबू पा ले, उतना ही हम सभी के लिए बेहतर होगा.

**यह सरकार फूहड़ता का प्रदर्शन कर रही है. सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय का हमेशा दुरुपयोग होता रहा है. इससे पहले इनका इस्तेमाल केवल व्यापारिक या उन लोगों के खिलाफ होता था, जो सरकार के विरोध में होते थे. अब लालू यादव और उनके परिवार पर हमले ने एक अलग मोड़ ले लिया है. ये बहुत ही छोटे मुद्दे हैं.**

यह सरकार फूहड़ता का प्रदर्शन कर रही है. सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय का हमेशा दुरुपयोग होता रहा है. इससे पहले इनका इस्तेमाल केवल व्यापारिक या उन लोगों के खिलाफ होता था, जो सरकार के विरोध में होते थे. अब लालू यादव और उनके परिवार पर हमले ने एक अलग मोड़ ले लिया है. ये बहुत ही छोटे मुद्दे हैं. बेनामी क्या होता है? भारत पूरी तरह से भावनाओं पर निर्भर एक देश है. 1988 में बेनामी अधिनियम पारित किया गया था. तब मैं संसद में था. मैंने संसद में कहा था कि यह नॉमिनी की तरह है, क्योंकि आप जो इस अधिनियम में कह रहे हैं, उसका मतलब यह है कि संपत्ति उस व्यक्ति की है, जिसके नाम से वह है और इस पर इसके वास्तविक मालिक का कोई अधिकार नहीं होगा. ठीक बात है. जिस व्यक्ति के नाम संपत्ति है, वह अदालत में शपथ लेकर बोल देगा कि यह उसकी संपत्ति है और उसने इसे इसके वास्तविक मालिक को दे दिया है. क्या आप भारत के भावनात्मक चरित्र को नियंत्रित कर सकते हैं? यह एक मूर्खतापूर्ण विचार है. अब, प्रवर्तन निदेशालय के पास प्रीवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है, जो बहुत बड़ा अधिकार देता है. इसके तहत ईडी लोगों को गिरफ्तार कर सकता है. ईडी लालू यादव और उनके परिवार को जेल भेजने का डर दिखा रहा है. कोई भी आम आदमी कहेगा कि यह एक समझदार रवैया नहीं है. लालू यादव का एक लंबा सियासी सफर रहा है. इसके बावजूद कि वे अदालत से एक मामले में दोषी साबित हो चुके हैं, फिर भी लोगों ने उन्हें बहुमत के साथ जिताया है. जनता इस तरह से राजनीतिक शिकार करने में विश्वास नहीं रखती है. ऐसे काम को सरकार जितनी जल्दी रोक ले, उतना बेहतर होगा.

सरकारी अधिकारी भी मुझसे मिलते रहते हैं. स्वाभाविक रूप से वे अपनी पहचान जाहिर नहीं करना चाहते हैं, लेकिन वे सभी मानते हैं कि यह सरकार प्रतिशोध की भावना से काम कर रही है. हालांकि, ऐसा हमेशा रहा है, कम या अधिक. लेकिन ये लोग बहुत कच्चे और अनाड़ी है. मुझे नहीं पता कि यह सोच कहां से आती है, लेकिन ऐसा लगता है कि यह सीधे पीएमओ से आ रही है. कोई सुधारात्मक कदम उठाए गए हों, इसमें मुझे सन्देह है. लेकिन, दीर्घावधि में देशहित में और अगर श्री नरेंद्र मोदी बार-बार चुनाव जीतने की महत्वाकांक्षा रखते हैं, तो उन्हें इस देश को सभ्य बनाना होगा न कि जैसे को तैसा वाला देश.■

feedback@chauthiduniya.com

# प्राइम टाइम का प्रोपेगेंडा

**काफी समय से कश्मीर इस प्रचारतंत्र (प्रोपेगेंडा) को झेल रहा है. ये प्रोपेगेंडा भारतीय मीडिया के एक बड़े हिस्से, विशेष रूप से टीवी चैनलों द्वारा फैलाया जा रहा है. इस प्रोपेगेंडे को सरकारी अधिकारियों और सत्ताधारी भाजपा के प्रवक्ताओं द्वारा प्रोत्साहित किया जा रहा है. दूसरे शब्दों में कहें, तो इस सोच को आधिकारिक स्वीकृति प्राप्त है. दिल्ली में भाजपा सरकार के कुछ मंत्री नियमित रूप से इस कश्मीर विरोधी आवरण का हिस्सा बनते हैं. इसका उद्देश्य होता है, कश्मीर के लोगों को नीचा दिखाना और समस्या के राजनीतिक समाधान के उनके आग्रह को खारिज करना. अशांति फ़ैलाने और मिलिटेंसी को बढ़ावा देकर गड़बड़ी पैदा करने के लिए पाकिस्तान को दोषी ठहराना कहानी का कोई नया अध्याय नहीं है. लेकिन इस प्रोपेगेंडे का जो नया हिस्सा है, वो है कश्मीरियों को बदनाम करना और वर्तमान संकट के लिए उन्हें या पाकिस्तान को दोषी करार देना. मीडिया के इस प्रहार को देख-सुन कर ये आभास होता है जैसे नई दिल्ली ने 1947 के बाद से कुछ गलत किया ही नहीं है.**

शुजात बुखारी

टीवी चैनेलों पर कश्मीर के बारे में कुछ पैनलिस्टों द्वारा की गई हालिया टिप्पणियों से कश्मीर के लोग नाराज़ भी हुए और आनंदित भी. गौरतलब है कि टीवी चैनलों ने अपने प्राइम टाइम का अधिकतर समय कश्मीर पर चर्चा के लिए समर्पित कर रखा है. भले ही वो चर्चा प्रासंगिक हों या न हो. टीवी चैनलों ने अपने आचरण से ये साबित कर दिया है कि कश्मीर के मामले को वे एक एजेंडे के तहत उछाल रहे हैं, ताकि यदि सरकार किसी कार्रवाई पर विचार करे, तो उसे न्यायोचित ठहराया जा सके. एक आम कश्मीरी शोर से भरपूर प्राइम टाइम स्टूडियो में अपने खिलाफ ज़हर देख कर चकित रह जाता है. जब यहां सामान्य स्थिति लौटती दिखाई दे रही होती है, तब भी प्राइम टाइम वार्तालाप में ये धारणा प्रस्तुत की जाती है कि घाटी जल रही है. हालिया दिनों में इन चैनलों ने शालीनता की सभी सीमाएं पार कर दी हैं. इन्होंने कई ऐसे लोगों (जो पत्रकारिता की कौन कहे, सभ्य आचरण के किसी ढांचे में भी फिट नहीं बैठते) को बहस में जगह देकर कश्मीर की बहस पर अपनी साख खो दी है.

काफी समय से कश्मीर इस प्रचारतंत्र (प्रोपेगेंडा) को झेल रहा है. ये प्रोपेगेंडा भारतीय मीडिया के एक बड़े हिस्से, विशेष रूप से टीवी चैनलों, द्वारा फैलाया जा रहा है. इस प्रोपेगेंडे को सरकारी अधिकारियों और सत्ताधारी भाजपा के प्रवक्ताओं द्वारा प्रोत्साहित किया जा रहा है. दूसरे शब्दों में कहें, तो इस सोच को आधिकारिक स्वीकृति प्राप्त है. दिल्ली में भाजपा सरकार के कुछ मंत्री नियमित रूप से इस कश्मीर विरोधी आवरण का हिस्सा बनते हैं. इसका उद्देश्य होता है, कश्मीर के लोगों को निचा दिखाना और समस्या के राजनीतिक समाधान के उनके आग्रह को खारिज करना. अशांति फ़ैलाने और मिलिटेंसी को बढ़ावा देकर गड़बड़ी पैदा करने के लिए पाकिस्तान को दोषी ठहराना कहानी का कोई नया अध्याय नहीं है. लेकिन इस प्रोपेगेंडे का जो नया हिस्सा है, वो है कश्मीरियों को बदनाम करना और वर्तमान संकट के लिए उन्हें या पाकिस्तान को दोषी करार देना. मीडिया के इस प्रहार को देख-सुन कर ये आभास होता है जैसे नई दिल्ली ने 1947 के बाद से कुछ गलत किया ही नहीं है.

हाल के दिनों में एक टीवी चैनल पर पैनलिस्ट्स द्वारा की गई दो टिप्पणियों ने लोगों को क्रोधित किया. लेकिन उनमें से एक टिप्पणी का लोगों ने खूब आनंद लिया और सोशल मीडिया पर मजाक भी उड़ाया. जिस टिप्पणी पर तीखी प्रतिक्रिया आई, वो थी आरएसएन सिंह की. आरएसएन सिंह एक सेवानिवृत्त कर्नल हैं, जो कुछ समय के लिए रिसर्च एंड एनालिसिस विंग (रॉ) के अधिकारी रहे हैं. अभी वे एक नए-नए लॉन्च हुए टीवी चैनल के सहयोगी के रूप में कार्यरत हैं. उन्होंने अपनी शर्मनाक टिप्पणी में ये संकेत दिया कि कश्मीरी युवा विदेशी मिलिटेंट्स की 'नाजायज औलाद' हैं और यही कारण है कि वे सरकारी अमले से इस तरह लोहा ले रहे हैं. आरएसएन सिंह जब ये असभ्य टिप्पणी कर रहे थे, तो ये स्पष्ट दिख रहा था कि एंकर को उसमें आनंद आ रहा है. इससे पता चलता है कि इस तरह की बहसें जो इन चैनलों की पहचान बन गई हैं, वो अब कितनी गहरी गर्त में चली गई हैं. उस पैनलिस्ट द्वारा कश्मीरियों को गाली दिए जाने पर किसी ने इस्तक्षेप नहीं किया और इसी तरह सरकार की प्रतिक्रिया भी आकार लेती है.

ऐसा व्यवहार न केवल शर्मनाक है, बल्कि इससे ये भी ज़ाहिर होता है कि सरकार ने कश्मीरियों को दबाने के लिए इन चैनलों को खुली छूट दे रखी है. इन चैनलों ने पत्रकारिता के पेशे को अपमानित किया है और ये स्पष्ट किया है कि कैसे सरकार भी इसमें एक पार्टी बन गई है. इन सबों ने बार-बार दुहराए जाने वाले इस सिद्धांत की कलई खोल दी है कि कश्मीरी हमारे अपने हैं और जम्मू-कश्मीर भारत का एक अभिन्न हिस्सा है.

दूसरी टिप्पणी सेना के पूर्व मेजर गौरव आर्य द्वारा की गई थी. उन्होंने मृत बुरहान वानी के नाम एक पत्र लिखा था, जिसकी वजह से टीवी चैनलों ने उन्हें प्रसिद्ध बनाया. ये ज्ञात नहीं है कि आर्य ने इतनी कम उम्र में सेना को क्यों छोड़ दिया. लेकिन अब वे एक ऐसे विशेषज्ञ बन गए हैं, जिन्हें उनकी सनसनीखेज टिप्पणियों के लिए हाथों हाथ लिया जा रहा है. आर्य ने एक कश्मीरी पैनलिस्ट से पूछा कि कश्मीरियों के गाल लाल क्यों होते हैं? कश्मीर में कुपोषण से कोई मृत्यु क्यों नहीं होती? और जब अशांति के दौरान सब कुछ बंद हो गया था, तो वे कैसे जीवित रहे? एक आम कश्मीरी ने ज़ाहिरी तौर पर इसे हल्के अंदाज़ में लेते हुए इस टिप्पणी का मजाक उड़ाया. लेकिन इसका अंतर्निहित असर काफी मजबूत था और इसमें भी उसी तरह के संकेत थे, जो आरएसएन सिंह के वक्तव्य में थे. कश्मीर और कश्मीरियों के मामले में आर्य जैसे लोग अनपढ़ की श्रेणी में आते हैं. ये एक ऐसी हकीकत है, जो कश्मीरियों को भी चकित कर देती है कि वे कैसे छह महीने तक चलने वाले बंद के दौरान जीवित रहे. हालांकि यहां की कृषि आधारित अर्थव्यवस्था काफी मज़बूत है, उसके लचीलेपन ने उन्हें मुश्किल समय में जीवित रहने में मदद किया. कश्मीरियों के लाल गाल से किसी को अचम्भा नहीं होना चाहिए, क्योंकि कश्मीरी अलग जेनेटिक पूल से सम्बंध रखते हैं. इस जेनेटिक पूल का अविभाजित भारत के किसी भी अन्य क्षेत्र से कोई सम्बंध नहीं है. हालांकि सरकार ने यहां की अर्थव्यवस्था को आश्रित अर्थव्यवस्था बनाया है, लेकिन यहां के लोग अपने दम पर संघर्ष करते हैं. 24,000 मेगावाट बिजली उत्पादन की क्षमता के बावजूद कश्मीर सर्दियों के महीनों में अंधेरे से जूझता रहता है. यहां की क्षमता से उत्पादित बिजली को भारत के बाकी हिस्सों में उजाला फ़ैलाने के लिए भेज दिया जाता है. यहां बिजली उत्पादन के जो संसाधन हैं वे नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन के अंतर्गत आते हैं. यहां तक कि उत्तरी ग्रिड के माध्यम से कश्मीरियों से बिजली की कीमत भी वसूली जाती है.

किराए के पैनलिस्ट्स द्वारा रोजाना जारी होनी वाली टिप्पणियां लोगों को झुकाने के लिए जारी मनोवैज्ञानिक जंग का हिस्सा हैं. मेजर गोगोई द्वारा एक कश्मीरी युवक को जीप के आगे बांधे जाने को उचित ठहराया जा रहा है. सरकार में शामिल कुछ लोगों ने तो इसे कश्मीरियों को सबक सिखाने के एक उपाय के रूप में बता दिया. वरिष्ठतम मंत्रियों में से एक, अरुण जेटली ने आधिकारिक रूप से घोषणा किए बिना कश्मीर में युद्ध जैसी स्थिति की बात कही और एक अन्य मंत्री एक टीवी शो पर दो कश्मीरी लोगों के साथ दुर्व्यवहार कर भीड़ पैनलिस्ट्स की सूची में शामिल हो गए. बाबुल सुप्रियो मोदी सरकार के एक मंत्री हैं. उन्होंने एक तरह से कश्मीर समस्या से निपटने की सरकार की नीति का खुलासा कर दिया. जब एक कश्मीरी पैनलिस्ट ने मानव शील्ड से सम्बंधित उनके जवाब पर मुस्कुरा कर अपनी प्रतिक्रिया दी, तो बाबुल ने गरज कर कहा था कि 'वे जिस तरह से मुस्कुरा रहे हैं, वो मुझे पसंद नहीं है. मैं उनकी गर्दन पड़कर उनसे कहलवाना चाहता हूं कि वे पहले भारतीय हैं... ये कहना कि हम शुरू से आखिरी तक कश्मीरी हैं, मैं समझता हूं कि ये हर उस कश्मीरी के लिए है जो टीवी पर बेशर्मी से मुस्कुराता है, एक मेजर गोगोई है, जो उन्हें जीप के आगे बांधेगा.' ये विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के एक मंत्री का व्यवहार है. यदि इस तरह की भाषा इस्तेमाल की जाएगी, तो कश्मीर की राजनीतिक समस्या के समाधान के लिए किसी राजनीतिक पहल और मेल मिलाप की उम्मीद कैसे की सकती है? इस तरह की चीज़ों की अनुमति देकर दिल्ली सरकार ने स्वयं को बेनकाब कर दिया है. जिस तरह से इन्होंने अपमानजनक प्रचार अभियान चलाने की अनुमति दी है, ये अब नैतिक आधार पर किसी भी जीत का दावा नहीं कर सकते. कश्मीर पर इनकी नीति स्पष्ट होती जा रही है, जो पिछली सरकारों के विपरीत है. शायद उनका भी यही दृष्टिकोण रहा हो, लेकिन कम से कम उन्होंने इसे पर्दे में रखा था.■

**-लेखक *राइजिंग कश्मीर* के संपादक हैं.**

feedback@chauthiduniya.com

संतोष भारतीय

# जब तोप मुक़ाबिल हो

# फ़ैसला राजनीतिज्ञों को लेना चाहिए, नौकरशाहों को नहीं

जब फैसले राजनीतिक नहीं होते, बल्कि ब्यूरोक्रेसी द्वारा लिए जाते हैं, तब देश को बड़ी परेशानियां झेलनी पड़ती हैं. इल्जाम हमेशा राजनीतिज्ञों पर आता है. नौकरशाही इससे दूर खड़ी दिखाई देती है. दरअसल फैसले तो सिस्टम लेता है, मतलब नौकरशाही लेता है. हम हाल के इतिहास में देखें तो संत जरनैल सिंह भिंडरावाले को सिस्टम ने पैदा किया. उन्हें मदद दी, बढ़ाया, नाम चारों तरफ फैलाया. फिर वही भिंडरावाले जब आगे बढ़ गए, तब सिस्टम ने कहा कि वे भारत के लिए खतरा बन गए हैं और भिंडरावाले को समाप्त करने के लिए स्वर्ण मंदिर में सेना भेज दी. दोष इंदिरा गांधी पर आया. किन नौकरशाहों ने ऐसा फैसला लिया, यह अभी तक सामने नहीं आया है. इसी वक्त दूसरा हादसा श्रीलंका में हुआ. लिट्टे और उसके नेता प्रभाकरण को हमारे सिस्टम ने पैदा किया. इल्जाम राजीव गांधी पर आया. किन नौकरशाहों ने लिट्टे और प्रभाकरण को बड़ा बनाने का फैसला लिया, ये अब तक सामने नहीं आया. पहली घटना के बाद इंदिरा गांधी और दूसरी घटना के बाद राजीव गांधी की हत्या हुई. इस वक्त, यही सिस्टम कश्मीर और नॉर्थ-ईस्ट को लेकर फैसला ले रहा है.

नॉर्थ-ईस्ट में जो हुआ, उसकी खबर भी मीडिया में नहीं आ रही है. नगाओं के साथ जो समझौता हुआ, उस समझौते में हमने सेना, करेंसी और ज्यूडिशियरी उनको सौंप दी. सिस्टम ने एक नए शब्द का अविष्कार किया, शेयरिंग सोवर्निटी यानि प्रभुसत्ता में साझेदारी. इस समझौते को संसद के सामने भी नहीं रखा गया. यह कह दिया गया कि ऐसा करना सुरक्षा के लिए खतरा बन सकता है. आज नगालैंड में नगाओं के पास अपनी 5 हजार की सेना है. जाहिर है, ये फैसला प्रधानमंत्री स्तर पर नहीं लिया गया होगा. इसका फैसला नौकरशाहों ने लिया होगा और गृह मंत्री के सामने लिया होगा. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को समझाया गया होगा कि नगालैंड में शांति के लिए ये समझौता सही होगा और इसे प्रधानमंत्री व गृहमंत्री ने मान लिया.

कश्मीर की स्थिति की जिम्मेदारी भी नौकरशाहों पर है. उन्होंने हमेशा नेताओं को भरमाया है. चाहे जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, वीपी सिंह, चंद्रशेखर, देवेगौड़ा, अटलबिहारी वाजपेयी या फिर मनमोहन सिंह रहे हों और अब नरेन्द्र मोदी, ये सभी लोग कश्मीर को लेकर वही भाषा बोलते रहे, जो भाषा नौकरशाहों ने उन्हें सिखाई. कश्मीर को देखने वाला एक सेल है, जिसमें विशेषज्ञ के रूप में बड़े नौकरशाह रहते हैं. यही लोग कश्मीर के मसले को उलझाते चले जा रहे हैं. इन दिनों कश्मीर का मसला उलझते-उलझते ऐसी जगह पहुंच गया है, जहां से भयानक विनाश की ओर एक रास्ता जा रहा है. दूसरा रास्ता अब भी है कि हम कश्मीर के लोगों को अपने साथ रख सकते हैं, लेकिन शायद जमीन अपने साथ रखने में हमारी ज्यादा रुचि है. लोगों को साथ रखने में हमारी रुचि नहीं है. नौकरशाह धीरे-धीरे कश्मीर को वहां पहुंचा रहे हैं, जहां प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष विदेशी हस्तक्षेप सामने नजर आ रहा है.

इसके अलावा देश के सामने बहुत सारी समस्याएं हैं. प्रधानमंत्री मोदी ने इन समस्याओं को हल करने के लिए कई सारे बिन्दु भी बताए हैं. लेकिन इन बिन्दुओं के ऊपर अमल करना या न करना वरिष्ठ नौकरशाहों के हाथ में है. जो वरिष्ठ नौकरशाह देश को चला रहे हैं, वो प्रधानमंत्री द्वारा किए गए वादों को या सुझाए गए रास्तों पर चलना अपना फर्ज नहीं समझते हैं.

**कश्मीर की स्थिति की जिम्मेदारी भी नौकरशाहों पर है. उन्होंने हमेशा नेताओं को भरमाया है. चाहे जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, वीपी सिंह, चंद्रशेखर, देवेगौड़ा, अटलबिहारी वाजपेयी या फिर मनमोहन सिंह रहे हों और अब नरेन्द्र मोदी, ये सभी लोग कश्मीर को लेकर वही भाषा बोलते रहे, जो भाषा नौकरशाहों ने उन्हें सिखाई. कश्मीर को देखने वाला एक सेल है, जिसमें विशेषज्ञ के रूप में बड़े नौकरशाह रहते हैं. यही लोग कश्मीर के मसले को उलझाते चले जा रहे हैं. इन दिनों कश्मीर का मसला उलझते-उलझते ऐसी जगह पहुंच गया है, जहां से भयानक विनाश की ओर एक रास्ता जा रहा है.**

प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेन्द्र भाई मोदी ने जितनी भी घोषणाएं कीं, उनमें से एक भी अपने सिरे नहीं चढ़ सकीं, क्योंकि नौकरशाह उन्हें सिरे चढ़ाना ही नहीं चाहते. एक साल पहले संसद के ऐनेक्सी में वरिष्ठ नौकरशाहों का सम्मेलन हुआ. वो एक साल में सिर्फ एक बार होता है. संयोग से मैं वहां था. जब सम्मेलन खत्म होने के बाद भोजनावकाश हुआ, तो मुझे सारे आईएएस अफसर, चाहे वो गुजरात, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश या कर्नाटक के हों, लगभग सभी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की आलोचना करते दिखाई दिए कि इनके सामने कोई साफ नक्शा नहीं है. हमें कैसे काम करना चाहिए इसके बारे में ये सीख दे रहे हैं. यह देखकर मैं हैरान था, पर ऐसा हुआ.

प्रधानमंत्री ने अपने राजनीतिक साथियों के हाथ से, मेरा मतलब केंद्रीय मंत्रिमंडल के मंत्रियों से कमान छीनकर नौकरशाहों के हाथों में पकड़ा दिया. हर मंत्री डरा हुआ है. वो अपने सचिव से कुछ भी कहने में हिचकता है, क्योंकि प्रधानमंत्री दो-दो बार यह कह चुके हैं कि जो भी नौकरशाह चाहे, वो उनसे सीधे बात कर सकता है. अब प्रधानमंत्री का ये आदेश नौकरशाहों को काम करने में तो मोटीवेट नहीं कर सका, लेकिन उसने अपने मंत्री को डराने में इस आदेश का भरपूर सहारा लिया. केंद्रीय मंत्रिमंडल में सिर्फ नितिन गडकरी, पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जैसे एक ही दो मंत्री हैं, जो अपने सचिवों से बिना डरे अपनी योजना पर काम कर रहे हैं. बाकी ज्यादातर मंत्री सचिव की तरफ ऐसे देखते हैं, जैसे चूहा बिल्ली की तरफ देखता है.

मंत्रियों की कोई जिम्मेदारी नहीं है. वो अपना रिपोर्ट कार्ड भी अपने सचिवों की दया से बना रहे हैं. मैं सवाल इसलिए खड़ा कर रहा हूं कि प्रधानमंत्री को आज नहीं तो कल ये सोचना पड़ेगा कि राजनीतिक व्यक्ति, जो केन्द्रीय मंत्रिमंडल का सदस्य है, उसका जनता के साथ सम्बंध रहता है. कार्यकर्ता उसके पास आते हैं. उसके क्षेत्र की जनता आती है. वे अपनी तकलीफें बताते हैं. परेशानियों को दूर करने के रास्ते भी सुझाते हैं, लेकिन नौकरशाहों के पास तो कोई नहीं जाता. उन्हें पता ही नहीं चलता कि वो जो फैसले ले रहे हैं, उसका जनता पर क्या असर पड़ रहा है. आज देश की यही स्थिति है. नौकरशाह एक तरह से सोच रहा है, मंत्रिमंडल के सदस्य एक तरह से सोच रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी एक तरह से सोच रहे हैं. दरअसल, प्रधानमंत्री के पास भी लोगों की तकलीफों या उनकी जानकारियों के पहुंचने का रास्ता सिर्फ और सिर्फ अखबार और टेलीविजन हैं. उनके कार्यकर्ता, जनता उनसे नहीं मिल सकते. उन्होंने वो सारे रास्ते बंद कर दिए हैं, जो गुजरात में खुले थे. इस समय उनके पास इतना वक्त ही नहीं है कि वो जनता के बीच जाएं. वो जनता के बीच जाते हैं, लेकिन अपनी बात कहते हैं. जनता की बात नहीं सुनते हैं. उनकी पार्टी जनता के बीच मोदी-मोदी का नारा लगवाकर प्रधानमंत्री को दिग्भ्रमित कर रही है. दरअसल, पार्टी नहीं दिग्भ्रमित कर रही है, पार्टी में कुछ ऐसे लोग दिग्भ्रमित करवा रहे हैं, जिनका इसी स्थिति में स्वार्थ है.

ये बातें मैं इसलिए लिख रहा हूं कि नौकरशाही इस देश में एक नए विद्रोह की जमीन तैयार कर रही है. वो विद्रोह है किसान विद्रोह. हर एक प्रदेश का किसान नाखुश है. किसान प्रधानमंत्री मोदी की बात पर भरोसा कर वोट देने निकला था. उसने उत्तर प्रदेश में भी वोट दिया. उसे आशा थी कि प्रधानमंत्री मोदी उसकी जिंदगी सुधारने के लिए कुछ अवश्य करेंगे, अपने वादों पर अमल करेंगे. पर, नौकरशाहों ने उन सारी आशाओं को मटियामेट कर दिया. अब पहली बार उन जगहों पर भी किसान आत्महत्या कर रहे हैं, जहां कभी आत्महत्या हुई ही नहीं थी, जैसे झारखंड, छत्तीसगढ़. मध्यप्रदेश में तो आत्महत्याओं का एक सिलसिला शुरू हो गया है. पिछले एक महीने के भीतर पच्चीस से ज्यादा आत्महत्याएं मध्यप्रदेश में हो चुकी हैं. महाराष्ट्र आत्महत्याओं की फसल पैदा करने वाले खेत बनते जा रहे हैं. ये आत्महत्याएं किसानों में गुस्सा पैदा कर रही हैं. किसान सरकार के खिलाफ खड़ा है तो यह स्थिति पैदा करने के लिए अगर कोई एक वर्ग जिम्मेदार है, तो वो नौकरशाह हैं. वो नौकरशाह आईएएस अफसर हो सकते हैं, आईपीएस अफसर हो सकते हैं, रॉ हो सकती है. और शायद यहीं से एक रास्ता निकला है कि इन्कम टैक्स, इंफोर्समेंट डायरेक्टोरेट, सीबीआई इन सबका डर दिखाकर मंत्रियों को भी काबू में रखें और विरोधियों को भी काबू में रखें.

किसान विद्रोह न हो, किसान कानून अपने हाथ में न लें, देश में हिंसक आंदोलन न शुरू हों, इसकी जिम्मेदारी निभाने का काम स्वयं प्रधानमंत्री को करना होगा, राजनीतिज्ञों को करना होगा. प्रधानमंत्री को, हो सकता है कि नौकरशाह ये समझाएं की आप इसमें मत ध्यान दीजिए. जैसे नक्सलवाद कानून व्यवस्था की समस्या है, वैसे किसानों की समस्या भी कानून व्यवस्था की समस्या है. हो सकता है प्रधानमंत्री समझ भी जाएं. पर मेरा मन नहीं मानता कि प्रधानमंत्री इतने भोले होंगे कि वो इस बात के भीतर छिपे हुए षड्यंत्र को न समझ पाएं. हर बार निवेदन प्रधानमंत्री से इसलिए करना होता है, क्योंकि बाकी मंत्रिमंडल के सदस्य तो शून्य हैं. किस नौकरशाह से निवेदन करें, इसलिए प्रधानमंत्री से ही निवेदन करते हैं कि इन अंतर्विरोधों को समझ कर सिस्टम यानी नौकरशाहों की काहिली को समझ राजनीतिक फैसला लें और नई पैदा होने वाली समस्या, किसान समस्या को सुलझाने में अपनी पूरी शक्ति लगाएं.■

editor@chauthiduniya.com

आर या पार

# धरती माता को मौत की सज़ा

परंजय गुहा ठाकुरता

**ऐसा प्रतीत होता है कि इन तीनों क्षेत्रों के सत्ताधारी वर्ग और उनके राजनीतिक नुमाइंदों को यह लगता था कि पूंजीवाद का पर्यावरण के लिहाज से आधुनिकीकरण काफी समय से लंबित है. लेकिन पेरिस समझौते के तहत लक्ष्यों को जान-बूझकर स्वैच्छिक और गैर बाध्यकारी रखा गया. इन्हें लागू कराने के लिए न तो कोई तंत्र बनाया गया और न ही पालन नहीं करने के लिए किसी तरह के दंड का प्रावधान किया गया. ओबामा प्रशासन ने पेरिस समझौते के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी ईपीए को दी थी और इसे क्लीन एयर एक्ट के तहत बिजली बनाने वाली कंपनियों के कार्बन उत्सर्जन को नियमित करने का काम दिया था. लेकिन इसे रोकने के लिए यह मामला अदालत में ले जाया गया. अब तो ट्रंप प्रशासन ने पेरिस समझौते से ही हटने की घोषणा कर दी है.**

यह सजा सुनाने वाले डोनाल्ड ट्रंप हैं और उन्हें जीवाश्म ईंधन के पूंजी पर खड़े लोगों और पर्यावरण विरोधियों का समर्थन मिला हुआ है. डोनाल्ड ट्रंप जलवायु परिवर्तन को हमेशा से धोखा बताते रहे हैं. 2 जनवरी, 2014 को उन्होंने अपने पहले ट्वीट में एक प्रमुख जलवायु वैज्ञानिक पर हमला करते हुए लिखा कि ग्लोबल वार्मिंग की यह खर्चीली बकवास बंद होनी चाहिए. ऐसे में जब उन्होंने 1 जून 2017 को 2015 के पेरिस समझौते से अमेरिका के हटने की घोषणा की, तो यह अनापेक्षित नहीं था. पूरी दुनिया में होने वाले हरित गैस उत्सर्जन में अमेरिका की हिस्सेदारी 15 फीसदी है. दिसंबर, 2016 में एक दस्तावेज सामने आया था. यह ट्रंप प्रशासन की पर्यावरण नीतियों के बारे में था. इसे तैयार किया था थॉमस पाइली ने. वे कोच बंधु समर्थित अमेरिकी ऊर्जा अलायंस के प्रमुख हैं और ट्रंप की टीम में ऊर्जा से जुड़े मामलों को देखते रहे हैं. इस दस्तावेज से पर्यावरण पर ट्रंप की नीतियों का खुलासा होता है. इसमें अमेरिका को पेरिस जलवायु समझौते से बाहर निकालने, ओबामा के स्वच्छ ऊर्जा की योजना को बंद करने और कीस्टोन समेत सभी पाइपलाइन परियोजनाओं को पूरा कराने से सम्बंधित बातें हैं.

इसमें कोई संदेह नहीं है कि ट्रंप और उनके सलाहकार अमेरिका के एक खास वर्ग की नुमाइंदगी करते हैं. यह खास वर्ग जीवाश्म ईंधन के कारोबार से जुड़ा हुआ है. लेकिन ट्रंप का यह निर्णय अमेरिका के सत्ताधारी वर्ग में सभी को अच्छा नहीं लगा है और न ही उनके इस निर्णय को पश्चिमी यूरोप और जापान में सराहा गया है. उनकी 'अमेरिका फर्स्ट' की नीति ने इस क्षेत्र में अमेरिका के नेतृत्व को पहले ही कमजोर कर दिया है.

जीवाश्म ईंधन के कारोबार में कोच इंडस्ट्रीज बड़ा नाम है. इसके कोच बंधुओं के अलावा ट्रंप के चुनाव अभियान में पैसा लगाने वाले कई कारोबारियों ने जलवायु परिवर्तन पर चिंता भी जताई है. गोल्डमैन सैक्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारी लॉयड ब्लैंकफैन ने ट्रंप के इस निर्णय पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि यह पर्यावरण के लिए बुरा है और दुनिया में अमेरिका के नेतृत्व के लिए भी यह बुरी खबर है. ऊर्जा क्षेत्र की बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनी एक्सनमोबिल ने पेरिस समझौते का समर्थन किया था. इसके पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी और अभी अमेरिका के विदेश मंत्री रेक्स टिलरसन ने जलवायु परिवर्तन के मसले पर अलग राय रखी थी. उन्होंने पर्यावरण संरक्षण एजेंसी यानी ईपीए के स्कॉट प्रूइट और ट्रंप के प्रमुख रणनीतिकार और ब्रेटबार्ट न्यूज के प्रमुख स्टीफन बैनन की राय को नहीं माना था. ट्रंप प्रशासन में ये दोनों लोग जलवायु परिवर्तन समझौतों के सबसे मुखर विरोधी हैं.

ऐसा प्रतीत होता है कि इन तीनों क्षेत्रों के सत्ताधारी वर्ग और उनके राजनीतिक नुमाइंदों को यह लगता था कि पूंजीवाद का पर्यावरण के लिहाज से आधुनिकीकरण काफी समय से लंबित है. लेकिन पेरिस समझौते के तहत लक्ष्यों को जानबूझकर स्वैच्छिक और गैर बाध्यकारी रखा गया. इन्हें लागू कराने के लिए न तो कोई तंत्र बनाया गया और न ही पालन नहीं करने के लिए किसी तरह के दंड का प्रावधान किया गया. ओबामा प्रशासन ने पेरिस समझौते के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी ईपीए को दी थी और इसे क्लीन एयर एक्ट के तहत बिजली बनाने वाली कंपनियों के कार्बन उत्सर्जन को नियमित करने का काम दिया था. लेकिन इसे रोकने के लिए यह मामला अदालत में ले जाया गया. अब तो ट्रंप प्रशासन ने पेरिस समझौते से ही हटने की घोषणा कर दी है.

जिन तीनों क्षेत्रों का पहले जिक्र किया गया है, वहां का सत्ताधारी वर्ग इस समझौते का इसलिए समर्थन करता है क्योंकि यह स्वैच्छिक और गैर बाध्यकारी है. क्योटो प्रोटोकॉल के तहत अमेरिका समेत दूसरे विकसित राष्ट्रों पर हरित गृह प्रभाव गैसों के उत्सर्जन को कम करने की बाध्यकारी जिम्मेदारी थी. लेकिन अमेरिका ने इसे मानने से इंकार कर दिया और ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए कुछ खास किया भी नहीं. यह स्पष्ट है कि स्वैच्छिक और गैरबाध्यकारी लक्ष्यों को हासिल करने की संभावना कम रहती है. ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में जलवायु परिवर्तन प्रक्रिया पर नजर रखने वाले वैज्ञानिकों का मानना है कि अभी जिस तरह से हरित गृह प्रभाव गैसों का उत्सर्जन हो रहा है, अगर यही बरकरार रहा तो अगले 20 सालों में ही तापमान में 2 डिग्री की बढ़ोतरी हो जाएगी. यह बढ़ोतरी एक ऐसा बिंदु है, जो बताता है कि अब तापमान बढ़ जाने के बाद जो चीजें शुरू होंगी या जो बदलाव आएगा उन्हें रोका नहीं जा सकता. इस आशंका के बावजूद अधिक उत्सर्जन करने वाले और ऐतिहासिक तौर पर अभी हरित गृह गैसों के उच्च स्तर के लिए जिम्मेदार देशों के नेता, स्वैच्छिक और गैर बाध्यकारी समझौते पर तैयार होने के बावजूद पीछे हट रहे हैं.

दरअसल, दुनिया के पूंजीपतियों ने पूंजी एकत्रित करने की होड़ में जिस तरह से मजदूरों और प्रकृति का शोषण किया है, वह अब ऐसे स्तर पर पहुंच गया है कि जिसे और झेल पाना प्रकृति के वश में नहीं है. अब प्रकृति जीवाश्म ईंधन के इस्तेमाल को झेलने को तैयार नहीं है. इसके बावजूद पूंजीवादी व्यवस्था का सबसे अधिक लाभ लेने वाले लोग जीवाश्म ईंधन से नवीकरणीय ऊर्जा की ओर जाने की प्रक्रिया को बाधित कर रहे हैं. सच्चाई तो यह है कि ऐसे लोगों के नुमाइंदे, डोनाल्ड ट्रंप ने पेरिस समझौते से पीछे हटकर धरती माता को मौत की सजा सुना दी है. अगर उनका साथ दे रहे पूंजीपतियों ने उनके इस फरमान का क्रियान्वयन शुरू किया, तो मानव सभ्यता एक लंबे और दुखदायी अंत की ओर बढ़ जाएगी.■

*(लेखक इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली के संपादक हैं.)*

feedback@chauthiduniya.com

## भुखमरी, बदहाली, पाखंड और सियासत का मारा

# 'बी' फॉर बुंदेलखंड

प्रभात रंजन दीन

बुंदेलखंड पर सियासत तो खूब हुई, लेकिन बुंदेलखंड की हालत जस की तस है. बुंदेलखंड छोड़ कर लोग बाहर जा रहे हैं. पलायन कर रहे लोग कहते हैं कि बुंदेलखंड को पॉलिटिक्स और पाखंड का रोग लग गया है. उनका मानना है कि पाखंड और पॉलिटिक्स अलग-अलग नहीं हैं. बुंदेलखंड के पढ़े लिखे लोग इस पर हैरत जताते हैं कि त्रासदी के मारे इस क्षेत्र पर बनी फिल्म 'बी फॉर बुंदेलखंड' को देश-दुनिया में प्रशंसा और कामयाबी मिलती है, लेकिन यहां की 'बी फॉर भुखमरी' हटाने पर किसी का ध्यान नहीं जाता.

नरेंद्र मोदी से लेकर राहुल गांधी, मायावती से लेकर अखिलेश यादव और अब योगी आदित्यनाथ तक की अलमबरदारी में बुंदेलखंड राजनीति का स्टेज बना हुआ है. इसी राजनीति में केंद्र से लेकर राज्य तक की सत्ता बदलती रही है, पाखंड यथावत है. तब से लेकर अब तक तमाम नेताओं के भाग्य बदल गए, लेकिन बुंदेलखंड के किसानों और आम लोगों की दशा नहीं बदली. छोटे किसानों का कर्जा माफ करने की योगी सरकार ने घोषणा भी कर दी, लेकिन जमीनी असलियत यही है कि अधिकांश किसानों पर बैंकों का नहीं, साहूकारों का कर्जा है. साहूकारों का आपराधिक दबाव किसानों को मार रहा है. पूर्व आईएएस अधिकारी सूर्य प्रताप सिंह कहते हैं कि साहूकारी अधिनियम 1934 में अंग्रेजों ने साहूकारी प्रथा को प्रतिबंधित कर दिया था, लेकिन अंग्रेज तो चले गए, पर देश से साहूकारी प्रथा नहीं गई. यह सरकार भी जानती है कि साहूकारों द्वारा गरीब किसानों और मजदूरों का शोषण जारी है. बुंदेलखंड और पूर्वांचल में लाखों छोटे किसानों की हालत बंधुआ मजदूरों जैसी हो गई है. अब तो बुंदेलखंड की त्रासदी में एक और आयाम जुड़ गया है, वह है वहां की गायें. किसान खुद भुखमरी का शिकार है तो गायों को कैसे खिलाए! बुंदेलखंड के लाखों किसानों ने अपनी गायें लावारिस छोड़ दी हैं. बुंदेलखंड में अब आपको लावारिस गायों की भरमार सड़कों और कूड़े के ढेरों पर दिखेंगी. केंद्र की भाजपा सरकार हो या प्रदेश की भाजपा सरकार, गायों को लेकर उनकी रुदालियां तो आपको खूब सुनाई पड़ेंगी, लेकिन गायों की प्राणरक्षा के लिए कोई सटीक व्यवस्था नहीं बनाई जा रही है. अब राजनीति की दुकान चलाने में गाय एक और बिकने वाला जुमला बन गई है. बुंदेलखंड क्षेत्र में भूखों को रोटी खिलाने के लिए 'रोटी बैंक' का नायाब फार्मूला लागू करने वाले पूर्व पत्रकार संन्यासी तारा पाटकर ने अब भूखी गायों को बचाने का भी बीड़ा उठाया है. इस तपती गरमी में तारा पाटकर ने बुंदेलखंड से राजधानी लखनऊ तक की पदयात्रा की और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिल कर गायों को बचाने की गुहार लगाई. पाटकर ने एक हफ्ते तक राजधानी लखनऊ में गांधी प्रतिमा पर अनशन भी किया.

तारा पाटकर ने 'रोटी बैंक' के लिए घरों से एक रोटी निकालने के आह्वान में गाय के लिए एक और रोटी निकाल कर देने का आह्वान जोड़ दिया है. पाटकर घर की रसोई से पहली रोटी गाय के नाम पर निकालने की लोगों को शपथ दिला रहे हैं. पदयात्रा के दरम्यान भी 250 किलोमीटर के रास्ते में उन्होंने विभिन्न गांवों और कस्बों में तकरीबन पांच हजार लोगों को गौ सेवा की शपथ दिलाई. उन्होंने बुंदेलखंड की 10 लाख गायों के भोजन के लिए एक करोड़ लोगों को शपथ दिलाने का लक्ष्य रखा है. तारा पाटकर ने 'चौथी दुनिया' से कहा, 'बदहाल बुंदेलखंड में जितना बुरा हाल गायों का है, उतना पहले कभी नहीं रहा. भूख से तड़पती करीब 10 लाख गायें भोजन की तलाश में कूड़े के ढेर पर जा खड़ी हुई हैं और भूसा, चारा न मिल पाने के कारण कागज, पन्नी और गंदगी खा रही हैं. पहले हिन्दुओं के घरों में यह परंपरा थी कि गायों को खिलाने के लिए रोटी-चावल निकाला जाता था. लेकिन अब नई पीढ़ी इसे भूल गई है. हमारा 'रोटी बैंक' गरीब, लाचार और भूखों को खिलाने के लिए दो रोटी और थोड़ी सब्जी देने का आग्रह ढाई साल से करता आ रहा है. करीब एक हजार लोग रोटी बैंक को लगातार भोजन मुहैया करा रहे हैं. अब लोगों से हम घर की रसोई की पहली रोटी गाय के नाम पर निकालने की अपील भी कर रहे हैं. साथ ही जन्मदिन, शादी-ब्याह व सालगिरह जैसे कार्यक्रमों में लोगों के साथ-साथ कम से कम 25-50 गायों को भोजन कराने का आग्रह भी कर रहे हैं. यह संदेश ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए हमने विश्व पर्यावरण दिवस से एक पदयात्रा शुरू की, जो गुरु गोरखनाथ की तपोभूमि महोबा से प्रारंभ हुई और 10 दिन में 250 किलोमीटर की दूरी तय कर लखनऊ पहुंची. पदयात्रा के दौरान विभिन्न गांवों व कस्बों में हम अब तक पांच हजार से अधिक लोगों को गौ सेवा की शपथ दिला चुके हैं. कई स्थानों पर हमको निस्वार्थ रूप से गाय की सेवा में लगे तमाम लोग भी मिले. उनसे बहुत सारी रोचक जानकारियां मिलीं. हम लोगों से प्यासी गायों के लिए चिरही, टब व बाल्टी की व्यवस्था करने को कह रहे हैं. महोबा से 10 किलोमीटर दूर काली पहाड़ी गांव में सड़क किनारे ढाबा चलाने वाले दयाराम राठौर ने प्यासी गायों के लिए लंबी हौद बनवा रखी है, जिसमें रोज करीब दो सौ गायें, बैल और बछड़े पानी पीने आते हैं. इसी गांव के सीताराम पटेल ने डेढ़ साल पहले एक लावारिस गाय को पकड़ कर बांध लिया था और उसकी सेवा शुरू कर दी. अब वह गाय पांच किलो दूध दे रही है. उसने एक बच्चे को भी जन्म दिया है. अब ये गाय उनके घर का महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुकी है.' भूखों और बेसहारा लोगों के लिए 'रोटी बैंक' खोलकर देश-विदेश में चर्चा में आए तारा पाटकर और उनके बुंदेली समाज ने अब बुंदेलखंड में भूख प्यास से तड़प रही गायों को बचाने की मुहिम भी अपने साथ जोड़ ली है.

बुंदेली समाज के संयोजक तारा पाटकर ने कहा कि मौदहा व भरूआ सुमेरपुर में शिव करन गुप्ता व राकेश शुक्ला व दिनेश शिवहरे जैसे गौ सेवक मिले, जो हादसे की शिकार चोटिल गायों को उठाकर अस्थाई रूप से बनाई गई गौशाला में ले जाते हैं और उनकी सेवा करते हैं. मौदहा के शिव करन तो अपने साथियों के साथ मरी हुई गायों के लिए गड्ढा खोदवाते हैं और उनको सम्मानपूर्वक दफना देते हैं. विना किसी सरकारी मदद के ऐसा वे पिछले कई साल से कर रहे हैं. कानपुर महानगर से लगे ग्रामीण क्षेत्रों से तो अब देसी गायें पूरी तरह गायब ही हो चुकी हैं. पतारा ब्लॉक के हिरनी गांव में उन्हें मात्र एक देसी गाय मिली, जबकि दो हजार जरसी गायें और करीब छह हजार भैंसें घरों के बाहर बंधी मिलीं. जब गांव के लोगों से इस बारे में पूछा तो पता चला कि भले ही देसी गाय का औषधीय महत्व सबसे ज्यादा हो, लेकिन उसका व्यावसायिक मूल्य अब बहुत कम बचा है. इसलिए देसी गायों की ऐसी दुर्गति हो गई है. पाटकर ने कहा कि बुंदेलखंड की इस गंभीर समस्या के प्रति मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ध्यान आकृष्ट करने के लिए उन्होंने 23 जून से लखनऊ के जीपीओ पार्क में गांधी प्रतिमा के समक्ष एक सप्ताह का सामूहिक उपवास रखा. पाटकर ने कहा, 'हम चाहते हैं कि सरकार गायों की हालत सुधारने के लिए तत्काल प्रभावी कार्य योजना बनाए क्योंकि यह समस्या अब विकराल रूप धारण कर चुकी है.' तारा पाटकर के साथ बुंदेली समाज के जसवंत सिंह सेंगर, मनोज सिंह चौहान, दीपक पचौरीय कई अन्य लोग भी उपवास पर बैठे. इन लोगों ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गौ-प्रेम किसी से छुपा नहीं है. उन्होंने मुख्यमंत्री आवास में भी गायें पाल रखी हैं. लिहाजा, वे बुंदेलखंड में मारी-मारी फिर रही भूखी-प्यासी लाखों गायों की उपेक्षा कैसे कर सकते हैं! भीषण गर्मी में बुंदेलखंड में पानी की कमी के बाद गाय सबसे बड़ी समस्या बन गई है. गायों के नाम पर सरकार काफी पैसा खर्च कर रही है, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि पैसा सिर्फ कागजों पर खर्च होता है और जमीन पर गायें भूख प्यास से मर रही हैं. गायों के लिए सरकार की तमाम योजनाएं फेल हैं. समाजसेवी भी गाय के लिए काम करने का दिखावा अधिक कर रहे हैं. गौशालाएं भी सिर्फ दिखावा हैं. सरकार गायों के लिए काम करना चाहती है, लेकिन कोई ठोस कदम नहीं उठाने से गायों की स्थिति दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है.

### बुंदेलखंड की भुखमरी बन रही है कामयाब फिल्मों की पटकथा

सुनने में तो मामला विवादास्पद दिखता है, लेकिन यह सच भी है कि देश की गरीबी बदहाली और फटेहाली दिखा-दिखा कर कई लोग बड़े-बड़े फिल्मकार बन गए. उन्होंने भारत की गरीबी और बदहाली दूर करने का जतन नहीं किया, बल्कि उसे विकसित दुनिया को बेचा और बड़े बन गए. खूब पुरस्कार और सम्मान बटोरे. ऐसे ही खौखले बड़प्पन पर लोग खुश होते हैं. त्रासदी के मारे बुंदेलखंड के साथ भी ऐसा ही हो रहा है. बुंदेलखंड की भुखमरी भी फिल्मों का प्लॉट बन रही है और हिट हो रही है. हाल ही में बुंदेलखंड के अभागे किसानों पर बनी फिल्म 'बी फॉर बुंदेलखंड' कोलकाता फिल्म फेस्टिवल में पुरस्कृत हुई है. लोगों ने इस फिल्म की जमकर तारीफ की. फिल्म के निदेशक विशाल मौर्य और देवी प्रसाद लेंका को 'बेस्ट डेब्यू फिल्म मेकर' के अवॉर्ड से भी नवाजा गया. इस फिल्म को इतनी सराहना मिली कि अब इसके 'गोल्डन फॉक्स अवॉर्ड्स' के लिए चुने जाने की भी पूरी संभावना जताई जा रही है. सूखे से प्रभावित बुंदेलखंड के किसानों की बदहाली ही इस फिल्म के मूल में है. 'बी फॉर बुंदेलखंड' फिल्म की कहानी किसान राम सिंह और उसके बेटे लल्ला पर आधारित है. राम सिंह पर कर्जे का बोझ है और इस कर्ज को चुकाने के लिए उनका बेटा जमीन बेचने की बात करता है. राम सिंह इंकार करते हैं, तो बेटा गांव छोड़ कर जाने लगता है. विवश राम सिंह फांसी लगाकर आत्महत्या कर लेते हैं. फिल्म की यह कथा बुंदेलखंड की क्रूर असलियत है. ■

### राजनीतिक दावों से भूख और प्यास नहीं मिटती

सूखाग्रस्त बुंदेलखंड में भीषण गर्मी के इस मौसम में तापमान 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जा रहा है. आसमान से आग बरस रही है और पथरीली जमीन आग उगल रही है. बुंदेलखंड के लोगों की नियति बन चुकी है साल दर साल सूखा, अकाल और भुखमरी की त्रासदी झेलना. सियासत भी इन्हीं बदहाल लोगों के बूते फल-फूल रही है. बुंदेलखंड की सबसे बड़ी पीड़ा यहां पेयजल की समस्या है. झांसी शहर के लोगों को माताटीला और पहुंच डैम से पीने का पानी मिल जाता है. लेकिन शहर से दूर होते जाएं तो पानी की समस्या विकराल होती जाती है. गांवों में हैंडपंपों से पानी निकलना बंद हो गया है. कुएं सूखे हैं. भूगर्भ जल का स्तर पाताल में चला गया है. चुनिंदा लोगों के पास गहरे खर्चीले हैंडपंप हैं. लेकिन यह पानी कुछ खास लोगों की ही प्यास बुझाती है. बुंदेलखंड के 80 प्रतिशत किसान कर्ज में डूबे हैं. रोजी-रोटी की तलाश में शहरों में मजदूरी के लिए भाग चुके हैं. गांव के गांव खाली पड़े हैं, बियाबान. केंद्र सरकार की संसदीय समिति की रिपोर्ट तक यह बता चुकी है कि बुंदेलखंड से लोगों का अंधाधुंध पलायन हो रहा है. लेकिन राजनीतिक दलों को

शेष पेज 11 पर

# बुंदेलखंड... कुछ भी तो नहीं बदला

# 'पी' फॉर पॉलिटिक्स

पेज 10 का शेष

कैराना का पलायन दिखता है, उन्हें बुंदेलखंड का पलायन नहीं दिखता. केंद्र की रिपोर्ट कहती है कि बांदा से सात लाख 37 हजार 920, चित्रकूट से तीन लाख, 44 हजार 920, महोबा से दो लाख 97 हजार 547, हमीरपुर से चार लाख 17 हजार 489, उरई से पांच लाख 38 हजार 147, झांसी से पांच लाख 58 हजार 377 और ललित पुर से तीन लाख 81 हजार 316 लोग पलायन कर चुके हैं. केंद्र सरकार की यह रिपोर्ट दो साल पहले की है. अब तो यह आंकड़ा और बढ़ चुका होगा, लेकिन सरकार वायदे चलाए जा रही है, कार्रवाई को काठ मारा हुआ है. विडंबना यह है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुंदेलखंड आकर यह कह चुके हैं कि पांच-पांच नदियों के होने के बाद भी बुंदेलखंड का प्यासा होना दुर्भाग्यपूर्ण है. मोदी ने कहा भी कि असली समस्या पानी के प्रबंधन की अराजकता है. लेकिन समस्या की शीर्ष स्तर तक पहचान होने के बावजूद उसे सुधारा नहीं गया. यह नेताओं के मुंह पर कालिख और तमाचा ही तो है कि जहां यमुना, चंबल, धसान, बेतवा और केन जैसी नदियां बहती हों वहां से लाखों लोग पलायन कर जाएं! जहां दस वर्षों में चार हजार से अधिक किसान खुदकुशी कर चुके हों! जहां पत्थर खोद कर नेता और माफिया करोड़पति और अरबपति हो रहे हों! बुंदेलखंड में उत्तर प्रदेश के सात जिले झांसी, हमीरपुर, बांदा, महोबा, जालौन और चित्रकूट आते हैं. इन सात जिलों में 19 विधानसभा सीटें हैं. इन सभी सीटों पर भाजपा जीती है. लेकिन इस क्षेत्र असलियत क्या दिखती है, टूटी-फूटी सड़कें, मीलों दर मीलों सूखे खेतों का रेगिस्तान, छोटे-छोटे बियाबान पड़े गांव, फूस और खपरैल की छतों के नीचे बैठे सूखे मरियल लोग और मातमी सन्नाटा. यह फिल्मी पटकथा नहीं, बुंदेलखंड की वास्तविक तस्वीर है.

प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और ग्राम्य विकास राज्य मंत्री महेंद्र सिंह ने बुंदेलखंड को लेकर वादे तो बहुत सारे किए, लेकिन उन्हें जमीन पर यथार्थ होता देखने का कोई जतन नहीं किया. योगी ने अभी हाल ही में कहा था कि एक कॉल पर 30 मिनट में पानी का टैंकर पहुंच जाएगा. लेकिन असलियत में ऐसा नहीं है. योगी ने कहा था कि पूरे बुंदेलखंड में एक हजार टैंकरों की व्यवस्था की जा रही है, जो पंचायत, ब्लॉक, तहसील और जिला मुख्यालयों पर रहेंगे और जहां भी पानी की जरूरत होगी 30 से 40 मिनट में वहां पहुंचा दिया जाएगा. इसके साथ ही सभी थानों, सरकारी दफ्तरों में प्याऊ का इंतजाम होगा और हजारों नए हैंडपंप भी लगाए जाएंगे. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुंदेलखंड जाकर कहा कि बुंदेलखंड में पानी की समस्या दो वर्ष में खत्म कर दी जाएगी. बुंदेलखंड को नई दिल्ली से सिक्स-लेन हाईवे से जोड़ा जाएगा. आने वाले पांच वर्षों में कई नए उद्योग लगेंगे और यहां के नौजवान को रोजगार मिलेगा, क्षेत्र से पलायन रुकेगा. बुंदेलखंड के लोगों ने इन योजनाओं के कारगर होने के लिए अगले चुनाव का इंतजार शुरू कर दिया है. सरकार ने पेयजल के लिए यूपी जल निगम का एक टोल-फ्री नंबर भी दिया था. उस नंबर पर डायल कीजिए तो फोट उठता नहीं और उठता है तो बोलने वाला पुलिसिया अंदाज में बात करता है. बुंदेलखंड की तपती जमीन पर नेता बिना लाव-लश्कर लिए घूमें, तब उन्हें असलियत का पता चले. ललितपुर के तालबेहट ब्लॉक में ग्योरा गांव के लगभग आठ सौ परिवारों के लिए महज नौ हैंडपंप हैं. लेकिन इस गर्मी में केवल चार हैंडपंपों में ही थोड़ा-थोड़ा पानी आ रहा है. लोगों को ऐसे कुओं का पानी पीने के लिए विवश होना पड़ रहा, जिसमें कचरा रहता है. हैंडपंप के पानी में भी हानिकारक तत्व की अधिकता है. पानी से होने वाली तमाम बीमारियां यहां के लोगों और बच्चों को ग्रसित किए हुई हैं. झांसी के बबीना ब्लॉक में रसीना गांव के लोगों का हाल बहुत बुरा है. इस गांव में डेढ़ सौ फीट खोदने पर भी पानी नहीं मिलता. लोग कई-कई किलोमीटर दूर के गांवों से पानी ढोकर लाते हैं. सिमरिया गांव में कहने के लिए 25 हैंडपंप हैं, लेकिन इनमें मात्र छह ही चालू हालत में हैं.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुंदेलखंड आकर पांच-पांच नदियों के होने की बात तो करते हैं, लेकिन नदियों की खराब हालत के बारे में कुछ नहीं कहते. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी बुंदेलखंड आकर पेयजल समस्या का जिक्र किया, लेकिन नदियों को पुनर्जीवित करने के लिए किसी भी सरकारी योजना का कोई जिक्र नहीं किया. सरकार के पास यह रिपोर्ट है कि बेतवा नदी जानलेवा तौर पर प्रदूषित हो चुकी है. बेतवा का पानी किसी जहर से कम नहीं रह गया है. यह वैज्ञानिक शोध में प्रमाणित हो चुका है और इसकी रिपोर्ट सरकार तक भेजी जा चुकी है. बेतवा नदी के पानी में घुला रसायन शरीर को नुकसान पहुंचा रहा है. एक समय बेतवा नदी का पानी शुद्ध था, लेकिन अब यह जहरीला हो चुका है. बेतवा नदी में काफी सिल्ट जम चुकी है और नदी का एक हिस्सा सिल्ट के कारण टापू में तब्दील हो चुका है. नदी के पानी में आर्सेनिक भी काफी मात्रा में है. पानी में जो तैलीय पदार्थ बह कर आता है, उस वजह से जानवरों की खाल उधड़ने लगती है. इलाके के लोग अगर नदी में नहा लेते हैं, तो शरीर पर फफोले हो जाते हैं. बांदा जिले के लगभग 300 से ज्यादा गांवों के लिए जीवनदायिनी मानी जाने वाली केन नदी का वजूद भी खतरे में है. लगभग दो दशक से चल रहा रेत-बालू के खनन का खेल इसे नष्ट कर रहा है. रेत माफिया के आगे सरकारें नतमस्तक रही हैं, जिस वजह से बुंदेलखंड की नदियों का भीषण नुकसान हुआ है. योगी सरकार की सख्ती के कारण खनन का धंधा थोड़ा थमा है, लेकिन रुका नहीं है. हथियारों के बल पर केन नदी का सीना अब भी खोदा जा रहा है. केन नदी छिछली होकर रह गई है. केन और बेतवा को जोड़े जाने की योजना और विनाशकारी साबित होने वाली है. जल विशेषज्ञ राजेंद्र सिंह कहते हैं कि केन-बेतवा नदी जोड़ने की परियोजना ही गलत है. इससे सिर्फ ठेकेदारों की जेब भरेगी. इससे गरीबों को कोई फायदा नहीं पहुंचेगा. अभी जो सिंचाई हो रही है, उतनी भी नहीं हो पाएगी. केन-बेतवा को जोड़ने की जरूरत ही नहीं है. बहरहाल, बुंदेलखंड के नदी नालों और पहाड़ों को बुरी तरह खोद डाला गया है और यह क्रम जारी है. बांदा में केन नदी का पुल पार करने के बाद महोबा को जोड़ने वाले 60 किलोमीटर के हाईवे-76 के दोनों किनारों पर सैकड़ों जगह हो रहे अवैध खनन को कोई भी देख सकता है. यह अलग बात है कि सरकार को यह नहीं दिखता. विस्फोट से खोखले किए जा रहे पहाड़ों और दिन-रात चल रहे क्रशर देखकर सरकार और माफिया के गठजोड़ का खुला खेल खुली तरह समझ में आता है. महोबा और चित्रकूट में ग्रेनाइट की खुदाई भी दिन-रात चल रही है. इस पर कोई अंकुश नहीं.

## आंकड़ों में बुंदेलखंड की बदहाली

भारतीय स्टेट बैंक के वर्ष 2016 के आंकड़े बताते हैं कि उत्तर प्रदेश के किसानों पर कुल कृषि ऋण 86,241.20 करोड़ है. भारतीय रिजर्व बैंक कहता है कि ढाई एकड़ से कम जोत वाले 31 प्रतिशत सीमांत और लघु किसानों को ऋण दिया गया है. यानि, प्रदेश सरकार ने लघु और सीमांत किसानों के कुल 27,419.70 करोड़ का कर्ज माफ किया. कर्जे का औसत प्रति किसान लगभग 1.34 लाख रुपए का है. सरकारी दस्तावेज कहता है कि कर्जा लेने वाले लघु और सीमांत कृषकों की संख्या लगभग डेढ़ करोड़ है. जबकि 10 करोड़ किसानों में से 2.33 करोड़ लघु और दो करोड़ सीमांत कृषक हैं. स्पष्ट है कि इन सभी पर किसी न किसी प्रकार का कर्ज जरूर है. फिर सवाल उठता है कि सरकार ने किस आधार पर महज डेढ़ करोड़ कर्जदार किसानों की सूची बनाई? खैर, उत्तर प्रदेश का इस वर्ष (2016-17) का सालाना बजट 3.46 लाख करोड़ रुपए का है. सरकार को इस वर्ष के कुल बजट का 33 प्रतिशत हिस्सा कर्ज माफी के लिए बैंकों को देना होगा. इससे वित्तीय वर्ष 2016-17 में उत्तर प्रदेश को 49,960.88 करोड़ रुपए का राजकोषीय घाटा होगा. यह घाटा सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 4.04 प्रतिशत है. कर्ज माफी के बाद यह घाटा 55 प्रतिशत बढ़ जाएगा. उत्तर प्रदेश की वित्तीय हालत पहले से ही खराब चल रही है. इस प्रदेश में किसानों की हालत यह रही है कि वर्ष 2013 में यहां 750 किसानों ने आत्महत्याएं की थीं. वर्ष 2016 में 1800 किसानों ने आत्महत्या की. आधे से अधिक आत्महत्याएं सूखाग्रस्त बुंदेलखंड और गरीब पूर्वांचल में हुईं. इन आत्महत्याओं का मुख्य कारण किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) का ऋण और उससे भी अधिक साहूकारों का ऋण है. साहूकारों से किसानों ने 20 से 24 प्रतिशत ब्याज पर कर्जा ले रखा है. इसमें किसान की खेती-बाड़ी सब गिरवी पड़ी हुई है और किसान साहूकारों का बंधुआ मजदूर बन गया है. साहूकारों से किसानों को मुक्ति दिलाने की सरकार की तरफ से कोई कानूनी कोशिश नहीं हो रही है. ■

### सीएम को दिखाने के लिए एक रात में तालाब भर देते हैं नौकरशाह

किसी क्षेत्र में प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री को आना हो तो नौकरशाहों की सक्रियता देखिए, रातभर में सड़कें तैयार हो जाएंगी, रास्ते धुल जाएंगे, इलाके में हरियाली और खुशहाली नजर आने लगेगी. किसी शहीद के परिजन से मिलने मुख्यमंत्री उनके घर जा रहे हों तो उस घर में बिजली का कनेक्शन लग जाएगा, फटाफट एसी और पंखे लग जाएंगे, यहां तक कि चादर तकिए तक बदल जाएंगे. मुख्यमंत्री के वहां से जाते ही अधिकारी अपनी मौलिक नंगई पर उतर आते हैं और सारे साजो-सामान उखाड़ लिए जाते हैं. तब लोगों को पता चलता है कि सुविधाएं तो मुख्यमंत्री जी को तकलीफ न हो इसके लिए लगाई गई थीं. पूरी व्यवस्था को सड़ाने के असली दोषी नौकरशाह हैं, जो नेताओं को आगे करके सबको बेवकूफ बनाते हैं और संसाधनों को लूटते हैं. बुंदेलखंड में भी ऐसा ही हुआ. मुख्यमंत्री को वहां जाना था तो नौकरशाहों ने रातों रात तालाब में पानी भर दिया. सूखे का मारा गांव अचानक पानी से लबालब हो गया. नौकरशाहों ने यह जादू दिखाया झांसी के सूखा पीड़ित गांव टांकोरी में. अधिकारियों की यह कारस्तानी देख कर गांव के लोग हैरत में आ गए, जब उन्होंने देखा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आगमन के पहले गांव का विशाल तालाब रातो रात पानी से भर दिया गया. गांव वाले तैयारी में थे कि अर्से से सूखे पड़े तालाब के बारे में वे मुख्यमंत्री से शिकायत करेंगे कि पूरे क्षेत्र को कभी पानी मुहैया करने वाला तालाब वर्षों से सूखा पड़ा है, लेकिन प्रशासन लगातार जनता की शिकायतों की अवहेलना कर रहा है. लेकिन क्षेत्र के लोगों ने सुबह देखा कि तालाब तो पानी से लबालब है. गांव वाले मुख्यमंत्री के सामने पोल न खोल दें, इसके लिए गांव के मानिंदों को पुलिस ने बुरी तरह धमकाया और मुंह न खोलने की हिदायत दी. गांव वालों ने डर के मारे मुख्यमंत्री के सामने कुछ नहीं बोला. कुछ मुखर ग्रामीणों को उनके घर में बंद कर पुलिस ने बाहर से कुंडी लगा दी थी. ग्रामीणों का कहना है कि गांव में आपातकाल लगा था. मुख्यमंत्री को विकास का 'दृश्य' दिखाने के लिए गांव के तालाब को टैंकरों से भर दिया गया. एक दिन पहले गांव का तालाब सूखा था, दूसरे दिन उसमें पानी लबालब भरा था. और मुख्यमंत्री कैसा कि उसे जमीनी हकीकत के बारे में कोई सूचना नहीं, कोई जानकारी नहीं.

बुंदेलखंड दौरे पर निकले मुख्यमंत्री ने तालाब के निरीक्षण का कार्यक्रम भी रखा था. इसके लिए मुख्यमंत्री ने झांसी-मवई गिर्द रोड पर उपेक्षित और सूखा प्रभावित गांव टांकोरी चुना था. मुख्यमंत्री को प्रसन्न करने के लिए प्रशासन ने मुस्तरा तालाब से आए नाले में पानी छोड़कर टांकोरी तालाब भर दिया गया. पानी भरने के लिए भारी तादाद में टैंकर लगाए गए थे. मुख्यमंत्री के वहां पहुंचने के पहले स्टेज सेट हो चुका था. ग्राम प्रधान रामलाल अहिरवार और दूसरे प्रमुख लोगों को पुलिस ने दूर ही रोक लिया था. स्थानीय पत्रकारों को भी मुख्यमंत्री के पास फटकने नहीं दिया गया. मुख्यमंत्री को टांकोरी गांव के प्राथमिक और पूर्व माध्यमिक विद्यालय का निरीक्षण करने भी जाना था. पुलिस ने स्कूल के पास बने घरों में बाहर से कुंडी लगा दी थी, ताकि लोग मुख्यमंत्री तक पहुंच नहीं पाएं. बाद में स्थानीय प्रशासन ने यह कहते हुए पल्ला झाड़ लिया कि मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर दूसरे जिलों से पुलिस मंगाई गई थी. ■

feedback@chauthiduniya.com

# बिहार के भूदानी किसानों पर आफ़त

**बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग से जारी इस परिपत्र से बिहार भूदान यज्ञ कमेटी हैरान है. भूदान कार्यकर्ता इस चिंता में डूबे हैं कि आख़िर सरकार ने इस परिपत्र को साठ साल के बाद क्यों जारी किया? अगर करना ही था तो जमींदारी उन्मूलन के तत्काल बाद क्यों नहीं किया? उस समय परिपत्र पर अमल करना आसान भी होता, अब तो इससे अराजकता ही फैलेगी. भूदान कार्यकर्ता भूदान किसानों की जमीन उनके हक में सुनिश्चित करने के लिए किसी ऐसे अकाट्य तर्क की तलाश में जुट गए हैं, ताकि अदालत में सरकारी परिपत्र रद्द करवा सकें. अगर इस प्रयास में भूदान कार्यकर्ता नाकाम होते हैं तो भूदान किसानों के पास करो या मरो आंदोलन के सिवाय कोई चारा नहीं होगा.**

कुमार कृष्णन

बिहार सरकार के एक फरमान से गांधी जी के सच्चे उत्तराधिकारी विनोबा भावे के भूदानी किसान संकट में घिर गए हैं. ऐसा कर सरकार ने यह साबित करने की कोशिश की है कि गांधी जी के आम आदमी से उसका कोई मतलब नहीं है, खासकर उन भूदानी किसानों से तो एकदम नहीं जिनके लिए विनोबा भावे बिहार में वर्षों रहकर दान में जमीन मांगते रहे. सरकार के राजस्व विभाग द्वारा जारी एक परिपत्र के मुताबिक, नीतीश सरकार ने उन जमीनों को अपनी बता कर विनोबा के समय से बसे भूदान किसानों को बेदखल करने की तैयारी शुरू कर दी है. भूदान किसान बिहार भूदान यज्ञ कमेटी के पर्चे के आधार पर प्रदत्त जमीन पर बसे थे. अब जबकि उनकी अगली पीढ़ियां भी आ गई हैं, ऐसे में साठ साल बाद उन्हें भूदान की जमीन से उजाड़कर गांधी, विनोबा और जयप्रकाश का माला जपनेवाली सरकार क्या मकसद हासिल करना चाहती है?

बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग से जारी इस परिपत्र से बिहार भूदान यज्ञ कमेटी हैरान है. भूदान कार्यकर्ता इस चिंता में डूबे हैं कि आखिर सरकार ने इस परिपत्र को साठ साल के बाद क्यों जारी किया? अगर करना ही था तो जमींदारी उन्मूलन के तत्काल बाद क्यों नहीं किया? उस समय परिपत्र पर अमल करना आसान भी होता, अब तो इससे अराजकता ही फैलेगी. भूदान कार्यकर्ता भूदान किसानों की जमीन उनके हक में सुनिश्चित करने के लिए किसी ऐसे अकाट्य तर्क की तलाश में जुट गए हैं, ताकि अदालत में सरकारी परिपत्र रद्द करवा सकें. अगर इस प्रयास में भूदान कार्यकर्ता नाकाम होते हैं तो भूदान किसानों के पास करो या मरो आंदोलन के सिवाय कोई चारा नहीं होगा. भूदान किसान इस परिपत्र को विनोबा जैसे संत की आत्मा पर कुठाराघात बता रहे हैं. वे इससे इतने कुपित हैं कि वे मौजूदा सरकार और उनके अमले को बात-बात में जमकर कोसते हैं. वे उदाहरण देते हैं कि अतीत में जिस नेता ने भूदान किसानों के विरुद्ध कदम उठाने की कोशिश की, वह दुर्दिनों में ऐसा घिरा कि चाहकर भी चुनाव नहीं लड़ सका. कुछ ऐसा ही हाल इस परिपत्र को जारी करनेवाले सरकार से जुड़े नेताओं का भी होगा. भूदान किसान भूदान प्राप्ति और वितरण की प्रक्रिया को एक यज्ञ की तरह देखते हैं और इसके विरुद्ध कदम उठानेवाले अफसरों के खिलाफ आवाज उठाते हैं.

परिपत्र की बात भूदान किसानों के बीच आग की तरह फैल चुकी है. भूदान किसान असमंजस में हैं, आखिर वे करें तो क्या करें. उनकी तो कहीं सुनवाई नहीं होती. अफसर और उनके कारिन्दे भी नहीं सुनते. वे तो उन्हीं दबंग भ्रष्टाचारियों के पक्ष में खड़े रहते हैं जो उन्हें बेदखल करने का षड्यंत्र करते रहते हैं. हम भले विनोबा को मानें या न मानें, पर भूदान किसान उनको अपना उद्धारक मानते हैं. इन भूदान किसानों के हित में विनोबा ने जीते जी भूदान यज्ञ अधिनियम को खूब सोच विचारकर इतना सशक्त बनाया कि उसे देश का कोई कानून चुनौती नहीं दे सके.

अब अगर इतना सशक्त अधिनियम सरकार के एक परिपत्र के आगे हार जाता है, तो इससे न सिर्फ भूदान किसान उजड़ेंगे, बल्कि गांधी, विनोबा और जयप्रकाश की विरासत और उनके योगदानों पर भी आंच आएगी. दुनिया भर में प्रसिद्ध मानवीय आधार पर अवतरित एक स्वयंस्फूर्त अहिंसक क्रांति की स्मृतियों, प्रतिमानों और उसके कारण बने-संवरे भूदान किसानों के छोटे-छोटे संसार भी तबाह हो जाएंगे. भूदान किसानों को एक उम्मीद उनके लिए जीवनदान देनेवाले लोकनायक जयप्रकाश नारायण आंदोलन के योद्धाओं से थी, लेकिन न जाने किस कारण वे भी चुप्पी साधे हुए हैं.

परिपत्र बिहार भूदान यज्ञ अधिनियम 1954 की धारा 12 के प्रावधानों के अनुकूल नहीं है. अधिनियम की धारा 12 में स्पष्ट है कि यदि किसी सत्वधारी में जिसका स्टेट या भूमिसुधार अधिनियम 1950 के अधीन राज्य में निहित हो चुकी हो. इस अधिनियम के प्रारंभ से पहले लिखित रूप से घोषणा की हो ऐसे स्टेट या भूधृति में समाविष्ट किसी भूमि को उसने आचार्य विनोबा भावे को दान कर दिया है और राज्य सरकार से यह लिखित प्रतिज्ञा की हो कि इस अधिनियम के अधीन ऐसी भूमि के संबध में भुगतानी मुआवजा छोड़ देगा तो राज्य सरकार ऐसी भूमि को भूदान यज्ञ के प्रयोजनार्थ भूदान यज्ञ समिति को हस्तांतरित कर देगी. वह भूमि भूदान यज्ञ समिति में निहित हो जाएगी. इसके बावजूद परिपत्र के मुताबिक, जमींदारी उन्मूलन के बाद यदि भूतपूर्व जमींदारों द्वारा गैरमजरूआ खास जमीन बिहार भूदान यज्ञ समिति अथवा विनोबा भावे को दान स्वरूप दिया गया है, तो ऐसे दानपत्रों की वैधानिक मान्यता नहीं होगी, क्योंकि जमींदारी उन्मूलन के बाद गैरमजरूआ खास जमीन सरकार में निहित हो चुकी है. परिपत्र को प्रभावी किया जाएगा तो करीब चार लाख भूदान किसानों को भूदान यज्ञ समिति द्वारा प्रदत्त जमीन से बेदखल होना होगा. भूदान से प्राप्त कुल भूमि 6,48,593.14 एकड़ में से 3,46,494.95 एकड़ भूमि संपुष्ट की गई है. अभी तक 2,56,392.39 एकड़ भूमि वितरित की जा चुकी है. वितरण के योग्य बची हुई 5990.03 एकड़ भूमि के वितरण का काम भूदान यज्ञ कमेटी द्वारा किया ही जा रहा था कि अब उसके रास्ते यह परिपत्र अड़चन बन गया है. सरकार वितरण के काम को सुनिश्चित करने के बजाय अब परिपत्र को बाकायदा क्रियान्वित करने में जुट गई है. इससे काफी संख्या में भूदान किसान प्रभावित हो रहे हैं. इन किसानों को भूदान यज्ञ कमेटी में वैध तरीके से निहित गैर मजरूआ खास जमीन दी गई थी. अगर सरकार जमींदारी उन्मूलन के तुरंत बाद गैर मजरूआ खास जमीन को भूदान में निहित नहीं करती तो आज यह नौबत नहीं आती. अधिकारी परिपत्र के आधार पर अलग-अलग जिलों में भूदान किसानों को नोटिस भी भेज रहे हैं. हालांकि भूमि वितरण का काम बिहार और झारखंड में एक साथ हुआ. वहां भी सरकार द्वारा संपुष्ट गैरमजरूआ खास जमीन भूमिहीनों को दी गई, लेकिन वहां की सरकार भूदान किसानों पर इस तरह के परिपत्र लाकर परेशान नहीं कर रही है.

**परिपत्र बिहार भूदान यज्ञ अधिनियम 1954 की धारा 12 के प्रावधानों के अनुकूल नहीं है. अधिनियम की धारा 12 में स्पष्ट है कि यदि किसी सत्वधारी में जिसका स्टेट या भूमिसुधार अधिनियम 1950 के अधीन राज्य में निहित हो चुकी हो. इस अधिनियम के प्रारंभ से पहले लिखित रूप से घोषणा की हो ऐसे स्टेट या भूधृति में समाविष्ट किसी भूमि को उसने आचार्य विनोबा भावे को दान कर दिया है और राज्य सरकार से यह लिखित प्रतिज्ञा की हो कि इस अधिनियम के अधीन ऐसी भूमि के संबध में भुगतानी मुआवजा छोड़ देगा तो राज्य सरकार ऐसी भूमि को भूदान यज्ञ के प्रयोजनार्थ भूदान यज्ञ समिति को हस्तांतरित कर देगी.**

परिपत्र को लेकर बिहार भूदान यज्ञ कमेटी के अध्यक्ष कुमार शुभमूर्ति का कहना है कि परिपत्र सरकार की भूमिसुधार नीति के अनुकूल नहीं है और न ही विधिसम्मत है. सरकार ने एक परिपत्र जारी कर कहा है कि जमींदारों ने जो गैरमजरूआ खास जमीन दान में दिया था, वह दान अवैद्य है. राजस्व और भूमि सुधार विभाग का कहना है कि दान अवैध इसलिए है कि गैरमजरूआ खास जमीन जमींदारों की नहीं थी. राज्य की सभी गैरमजरूआ खास जमीन जमींदारी उन्मूलन होते ही सरकार की हो गई थी. शुभमूर्ति सवाल करते हैं कि 1950 में जमींदारी उन्मूलन के बाद जब ये जमीन सरकार की हो गई तो 1954, 1955, 1956 के वर्षों में जमींदारों ने ये जमीन कैसे दान में दे दी. अगर यह सर्कुलर 1960 तक निकल जाता तब भी यह बात मानने लायक होती. लेकिन सरकार को खुद उस समय ध्यान नहीं था. सरकार ने अपनी ही जमीन को संपुष्ट करके भूदान के खाते में निहित कर दी. ऐसे में अब यह सर्कुलर जारी करना सरासर गलत है.

उन्होंने कहा कि अब तक तीन लाख से अधिक भूमिहीनों को भूदान की ओर से जमीन दी गई है. इसमें करीब डेढ़ लाख भूमिहीनों को जो जमीन दी गई, वह गैर मजरूआ खास जमीन ही है. इन डेढ़ लाख भूमिहीनों को बाकायदा कानूनी तरीके से प्रमाण पत्र देकर बसाया गया, उसे अब सरकार कैसे बेदखल कर सकती है? फिर उनका कैसे बंदोबस्त करेंगे? इस सर्कुलर के जारी होने से ऐसे भूदानी किसान चिंता में डूब गए हैं और इस आशंका से त्रस्त हैं कि अब अधिकारी आएंगे और उन्हें तरह-तरह की नोटिस देंगे. फिर उन्हें भूदान की जमीन से खदेड़ देंगे. सर्कुलर से भारी अराकजकता फैल रही है, सरकार इसे वापस ले. अगर भूदानी जमीन के वितरण के शुरुआती दौर में ही सरकार ऐसे परिपत्र जारी करती तो उस समय उनकी मंशा आसानी से पूरी हो जाती, लेकिन आज इस सर्कुलर के प्रभावी होने से मामला बिगड़ सकता है. यह परिपत्र राज्य के सभी प्रमंडलीय आयुक्तों और जिला पदाधिकारियों को प्रेषित किया गया है. इस बारे में राजस्व और भूमि सुधार विभाग के प्रधान सचिव को लिखे एक पत्र में शुभमूर्ति ने कहा है कि उक्त परिपत्र के निर्गत होने की वजह से लाखों भूदान किसान प्रभावित हो रहे हैं. जो भूदान किसान वर्षों से भूदान की जमीन पर बसे हैं या जोत आबाद कर जीविकोपार्जन कर रहे हैं और रसीद कटाते आ रहे हैं, उनका रसीद अब राजस्व कर्मचारियों द्वारा नहीं काटा जा रहा है. नए भूदान किसानों का भी रसीद उक्त परिपत्र के आधार पर काटा जाना बंद कर दिया गया है, जिससे काफी संख्या में दलित गरीब भूमिहीन भूदान किसान अपनी भूमि के दाखिल-खारिज के लिए भटक रहे हैं और बड़ी संख्या में भूदान किसान बेदखल हो रहे हैं. इस परिपत्र की वजह से भूमि सुधार उपसमाहर्ता न्यायालय में सैकड़ों एकड़ भूमि से संबंधित दाखिल दानपत्रों की संपुष्टि नहीं की जा रही है या फिर उन दानपत्रों को खारिज किया जा रहा है, जिसकी वजह से भूमि वितरण कार्य प्रभावित हो रहा है और राज्य में माहौल बुरी तरह से बिगड़ रहा है. ■

feedback@chauthiduniya.com

मगध विश्वविद्यालय

## कॉलेजकर्मियों का आंदोलन शुरू पढ़ाई चौपट

**बिहार के बड़े विश्वविद्यालयों में शुमार मविवि इन दिनों गैर शैक्षणिक कार्यों, वित्तीय अनियमितता और फर्जी डिग्री घोटालों के कारण देश भर में चर्चा में है. इस विश्वविद्यालय में पठन-पाठन से ज्यादा जमा राशि को ठिकाने लगाने के उपाय में पदाधिकारी लगे रहते हैं.**

चौथी दुनिया ब्यूरो

मगध विश्वविद्यालय के सभी 44 कॉलेजों के ढाई हजार कर्मचारी इन दिनों आन्दोलन की राह पर हैं. अपनी विभिन्न मांगों को लेकर कॉलेजकर्मियों ने चरणबद्ध आन्दोलन की शुरुआत कर दी है, जिसके कारण पठन-पाठन से लेकर सत्र भी अनियमित होने लगे हैं. मगध प्रमण्डल के पांच जिले गया, जहानाबाद, औरंगाबाद, नवादा, अरवल और पटना प्रमण्डल के दो जिले पटना और नालंदा कुल सात जिलों में विवि के अंगीभूत कॉलेज हैं. इन कॉलेज में विभिन्न पाठयक्रमों में लाखों छात्र-छात्राएं नामांकित हैं. इन कॉलेज में शिक्षकेत्तर कर्मियों के बराबर आन्दोलनरत रहने से छात्र-छात्राओं को परीक्षा फॉर्म भरने व अन्य शैक्षणिक व गैर शैक्षणिक कार्यों में परेशानी होती है. वहीं, कॉलेजकर्मियों का कहना है कि मविवि के पदाधिकारी तथा मुख्यालय में कार्यरत शिक्षकेत्तर कर्मचारी खुद तो सारी सुविधाएं ले रहे हैं, लेकिन राज्य के अन्य विवि में मिल रही सुविधाओं से यहां के कॉलेज कर्मियों को वंचित रखा है. इन्हीं वंचित सुविधाओं की मांग को लेकर कर्मचारी आंदोलनरत हैं. मविवि के कॉलेजकर्मियों के अनुसार, राज्य के सभी विश्वविद्यालयों के कर्मचारियों के साथ-साथ मविवि मुख्यालय के कर्मचारियों को एसीपी का लाभ जून 2015 से मिल रहा है, जबकि मविवि के कॉलेज कर्मियों को आज तक उक्त सुविधाएं नहीं मिली हैं. सेवाकाल में मृत कर्मियों के आश्रितों को अनुकम्पा के आधार पर विगत चार वर्षों से नियुक्ति नहीं हो रही है. स्वीकृत पद रिक्त हैं, फिर भी प्रोन्नति नहीं हो रही है. सेवाकाल में मृत तथा सेवानिवृत्त कर्मियों को पेंशन नहीं मिल पा रहा है. इन्हीं मांगों को लेकर मविवि के कॉलेज कर्मियों ने आन्दोलन का रुख अख्तियार कर लिया है. बिहार राज्य विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय कर्मचारी महासंघ मगध विश्वविद्यालय प्रक्षेत्र के पदाधिकारियों ने बताया कि आन्दोलन के तहत मविवि मुख्यालय में अपनी मांगों को लेकर धरना-प्रदर्शन, कलमबंद हड़ताल, कॉलेज में तालाबंदी व अंत में अनिश्चितकालीन हड़ताल करने का निर्णय लिया गया है.

बिहार के बड़े विश्वविद्यालयों में शुमार मविवि इन दिनों गैर शैक्षणिक कार्यों, वित्तीय अनियमितता और फर्जी डिग्री घोटालों के कारण देश भर में चर्चा में है. इस विश्वविद्यालय में पठन-पाठन से ज्यादा जमा राशि को ठिकाने लगाने के उपाय में पदाधिकारी लगे रहते हैं. शैक्षणिक गुणवत्ता तथा समय से विभिन्न पाठयक्रमों की परीक्षा लेना तो दूर की बात, परीक्षा फॉर्म भरने, पंजीयन, अंकपत्र निकालने, डिग्री लेने या अन्य छोटे-मोटे कार्यों के लिए छात्र-छात्राओं को कई-कई दिनों तक दौड़ना पड़ता है. इसके कारण विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में शामिल होने से इस विश्वविद्यालय के हजारों छात्रों को वंचित होना पड़ता है. इस विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले छात्र-छात्राएं विवि की व्यवस्था से असंतुष्ट तो हैं ही, मविवि के अंगीभूत 44 कॉलेजों के ढाई हजार कॉलेजकर्मी भी अपनी मांगों को लेकर आन्दोलन की राह पर हैं.

feedback@chauthiduniya.com

# अब नक्सलियों से आर या पार

सुनील सौरभ



बिहार-झारखंड में अब नक्सलियों के खिलाफ निर्णायक लड़ाई होगी. इसके लिए पूरी तैयारी कर ली गई है. नक्सल प्रभावी क्षेत्रों के संबंध में सभी तरह की जानकारी सरकारी खुफिया तंत्र के सहारे इकट्ठा की गई है. नक्सलियों के खिलाफ अभियान में लगे सुरक्षा बलों को स्थानीय पुलिस एवं अन्य सरकारी तंत्रों के बीच समन्वय बनाकर ठोस एवं कारगर कार्रवाई करने की रणनीति तैयार की गई है. गत 12 जून 2017 को केन्द्रीय सुरक्षा सलाहकार के विजय कुमार ने बिहार के गया जिला के बाराचट्टी स्थित कोबरा बटालियन के मुख्यालय में सुरक्षा बलों के अधिकारियों के साथ हुई बैठक में आवश्यक निर्देश दिए. इस बैठक में बिहार- झारखंड के सीमावर्ती क्षेत्रों समेत दोनों राज्यों से नक्सलियों के पूर्ण सफाए की रणनीति बनाई गई.

**12 जून 2017 की बैठक में नक्सलियों के खिलाफ कारगर अभियान चलाने का फैसला किया गया है, ताकि झारखंड से भागे नक्सलियों को बिहार के जंगलों में पनाह नहीं मिल सके. बैठक में नक्सलियों को उन्हीं की भाषा में जवाब देने की रणनीति तय की गई है. बैठक में बिहार-झारखंड के संबंधित जिलों के एसपी समेत अन्य सुरक्षा एजेंसियों के कमांडेंट ने भाग लिया. लेकिन सवाल है कि नक्सलियों के खिलाफ अबतक निर्णायक कार्रवाई क्यों नहीं की गई? सुरक्षा बलों पर अबतक प्रति महीने खर्च हुए करोड़ों की राशि बेकार क्यों गई?**



12 जून 2017 को गया जिले के बाराचट्टी के बरवाडीह स्थित कोबरा कैंप में केन्द्रीय सुरक्षा सलाहकार के विजय कुमार तमाम सुरक्षा बलों के पदाधिकारियों के साथ नक्सलियों के खिलाफ निर्णायक लड़ाई की तैयारी कर रहे थे, उसी दौरान गया जिले के कोठी थाना क्षेत्र के वसुरा गांव के पास सड़क निर्माण कर रहे कंपनी के दो जेसीवी को नक्सलियों ने फूंक दिया. यह हाल तब है, जब झारखंड की सीमा से सटे गया जिले के शेरघाटी अनुमंडल में कोबरा, सीआरपीएफ, एसएसबी के कैंप तथा बिहार पुलिस के दर्जन भर से अधिक थाने हैं. स्थानीय स्तर पर हर थाने में पंचायतों में चौकीदार की भी नियुक्ति है. ये चौकीदार अपने क्षेत्र में आपराधिक गतिविधियों की जानकारी पुलिस को देते हैं. नक्सलियों की गतिविधियों की जानकारी भी इन चौकीदारों को होती है, लेकिन इनकी पुलिस से ज्यादा मिलीभगत नक्सलियों से होती है. यहां तक कि थाने के पुलिसकर्मियों की भी संलिप्तता नक्सलियों के साथ होती है. यही कारण है कि केन्द्रीय सुरक्षा बलों के तमाम प्रयासों के बाद भी नक्सलियों के खिलाफ कारगर कार्रवाई नहीं हो पाती है. नक्सलियों का सूचना तंत्र इतना मजबूत है कि सर्च ऑपरेशन की जानकारी नक्सलियों को पहले ही मिल जाती है. इसका प्रमुख कारण है कि स्थानीय लोगों, कुछ पुलिसकर्मियों के साथ-साथ बिहार-झारखंड के कई राजनेता आज भी नक्सलियों के संरक्षक बने हुए हैं.

प्रतिबंधित नक्सली संगठन भाकपा माओवादी की मध्य एरिया कमेटी का सचिव संदीप यादव उर्फ विजय यादव पिछले दो दशकों से बिहार-झारखंड के सीमावर्ती जिलों में सुरक्षा बलों के लिए चुनौती बना है. 42 साल के संदीप ने दो दशक पूर्व गया जिले के बांके बाजार में तत्कालीन थानेदार बिनोद सिंह पर बम फेंककर अपराध की दुनिया में कदम रखा था. बाद में बिहार-झारखंड की सीमा से लगे गया और औरंगाबाद जिलों में कई नक्सली घटनाओं को अंजाम देने के बाद उसका कद भी बढ़ता गया. आज की तारीख में संदीप स्थानीय पुलिस के अलावा केन्द्रीय सुरक्षा बलों के भी टॉप लिस्ट में है. इस कुख्यात नक्सली कमांडर के कई राजनेताओं से भी संबंध हैं.

12 जून 2017 की बैठक में नक्सलियों के खिलाफ कारगार अभियान चलाने का फैसला किया गया है, ताकि झारखंड से भागे नक्सलियों को बिहार के जंगलों में पनाह नहीं मिल सके. बैठक में नक्सलियों को उन्हीं की भाषा में जवाब देने की रणनीति तय की गई है. बैठक में बिहार-झारखंड के संबंधित जिलों के एसपी समेत अन्य सुरक्षा एजेंसियों के कमांडेंट ने भाग लिया. लेकिन सवाल है कि नक्सलियों के खिलाफ अबतक निर्णायक कार्रवाई क्यों नहीं की गई? सुरक्षा बलों पर अबतक प्रति महीने खर्च हुए करोड़ों की राशि बेकार क्यों गई? नक्सली प्रभाव वाले क्षेत्रों में सरकारी खुफिया तंत्र लाचार क्यों नजर आता है? स्पष्ट है कि नक्सलियों को किसी न किसी रूप में सत्ता और राजनीति का संरक्षण प्राप्त है, तभी तो नक्सलियों के खिलाफ कोई अभियान सफल नहीं हो पाता है.

ज्ञात हो कि बिहार-झारखंड के पन्द्रह जिलों के पचास नक्सली वर्षों से पन्द्रह हजार सुरक्षा बलों पर भारी पड़ रहे हैं. इन नक्सलियों पर सरकार ने 25 हजार से पांच लाख तक के इनाम घोषित कर रखे हैं. इन नक्सलियों पर 12 से लेकर 20-20 मामले दर्ज हैं. खुफिया विभाग के साथ-साथ सुरक्षा बलों तथा स्थानीय पुलिस के खुफिया विभाग भी इन क्षेत्रों में सक्रिय हैं. इसके बावजूद इन कुख्यात नक्सलियों का कोई सुराग नहीं मिल पा रहा है.■

feedback@chauthiduniya.com

# उपेक्षित है भगवान बुद्ध का ऐतिहासिक टीला

**पुरातत्व विभाग ने इस क्षेत्र की खुदाई कर वहां से प्राप्त ऐतिहासिक अवशेषों को कोलकाता संग्रहालय में सुरक्षित रखे जाने की बातें कही थीं. जिला प्रशासन की ओर से प्रकाशित क्रिमिला नामक स्मारिका में भी इस पुरातात्विक टीले का उल्लेख किया गया है. विरासत बचाओ समिति के प्रखर सदस्य सह इतिहासकार अनिल कुमार सिंह ने अपने आलेख में इसे भगवान बुद्ध की स्मारक टीला बताया है.**

एसके गांधी

feedback@chauthiduniya.com

पालवंशीय एवं भगवान बुद्ध की ऐतिहासिक धरोहरों की विरासत को संभाले लखीसराय जिले के कई हिस्सों में पुरातात्विक अवशेष बिखरे पड़े हैं. इसके बावजूद प्रशासनिक और जनसामान्य की उपेक्षा के कारण इन धरोहरों का लगातार क्षरण हो रहा है. किउल विरदावन गांव स्थित ऐतिहासिक एवं पुरातात्विक भगवान बुद्ध का गुफानुमा टीला देखने के बाद ऐसा प्रतीत होता है कि अगर समय रहते इसका संरक्षण नहीं किया गया, तो यह खंडहर बनकर रह जाएगा. हालांकि जिला प्रशासन ने उक्त टीले के कुछ हिस्सों पर दीवार निर्माण करवाया है, लेकिन भूखंडों पर अतिक्रमण के कारण इस ऐतिहासिक टीले के भविष्य पर प्रश्नचिन्ह लग गया है. पुरातत्व विभाग ने इस क्षेत्र की खुदाई कर वहां से प्राप्त ऐतिहासिक अवशेषों को कोलकाता संग्रहालय में सुरक्षित रखे जाने की बातें कही थीं. जिला प्रशासन की ओर से प्रकाशित क्रिमिला नामक स्मारिका में भी इस पुरातात्विक टीले का उल्लेख किया गया है. विरासत बचाओ समिति के प्रखर सदस्य सह इतिहासकार अनिल कुमार सिंह ने अपने आलेख में इसे भगवान बुद्ध की स्मारक टीला बताया है.



सरकारी अधिकारियों की लापरवाही के कारण अब इस टीले के अस्तित्व पर ही खतरा मंडराने लगा है. स्थानीय ग्रामीणों के अनुसार वर्तमान टीला पालवंश के जमाने में राजा इन्द्रदमन के किले में प्रवेश करने का गुफा था. यहां से जयनगर काली पहाड़ी एवं अशोक धाम तक राजा इन्द्रदमन के किले का विस्तार था.

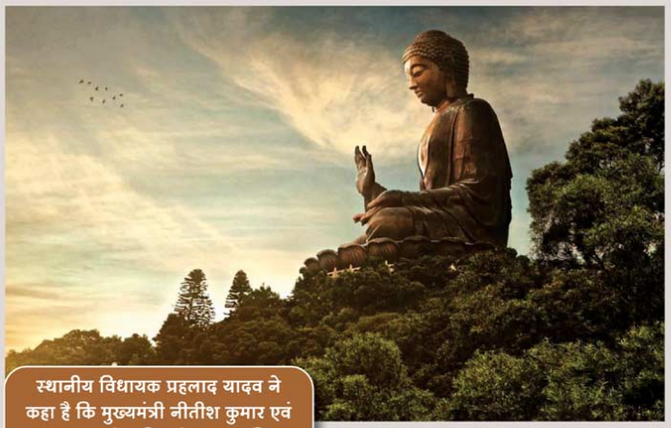





**स्थानीय विधायक प्रहलाद यादव ने कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एवं युवा, कला, संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग के प्रधान सचिव को अवगत कराकर पालवंशकालीन ऐतिहासिक गुफा को सुरक्षित कराया जाएगा. उन्होंने बताया कि जरूरत पड़ने पर पर्यटन विभाग की ओर से इसे बौद्ध सर्किट से जुड़वाने का भी प्रयास करेंगे. उन्होंने कहा कि ऐतिहासिक विरासत की हिफाजत करना सभी नागरिकों का दायित्व है.**

हालांकि इस स्थान पर भगवान बुद्ध के ठहरने का भी जिक्र मिलता है. पुरातत्व विभाग विभाग ने कई दशक पूर्व इस जगह की खुदाई की थी, जिसका जिक्र स्थानीय लोग भी करते हैं.

स्थानीय विधायक प्रहलाद यादव ने कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एवं युवा, कला, संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग के प्रधान सचिव को अवगत कराकर पालवंशकालीन ऐतिहासिक गुफा को सुरक्षित कराया जाएगा. उन्होंने बताया कि जरूरत पड़ने पर पर्यटन विभाग की ओर से इसे बौद्ध सर्किट से जुड़वाने का भी प्रयास करेंगे. उन्होंने कहा कि ऐतिहासिक विरासत की हिफाजत करना सभी नागरिकों का दायित्व है. उन्होंने चानन प्रखंड के घोषीकुंडी स्थित पहाड़ी को भौगोलिक धरोहर बताया. उन्होंने कहा कि घोषीकुंडी पहाड़ी स्थित गांव में एक पौराणिक कबीर मठ भी इतिहास का हिस्सा है. लेकिन इस पहाड़ी का बौद्ध कालीन अवशेष होने के बारे में उनके पास कोई प्रमाणिक जानकारी उपलब्ध नहीं है.

उन्होंने कहा कि लखीसराय की धरती अपनी पुरातात्विक एवं धार्मिक इतिहास के लिए राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत पहचान रखती है. वहीं श्री यादव ने कहा कि घोषीकुंडी गांव में इंजीनियरिंग कॉलेज का निर्माण नहीं किए जाने के संदर्भ में भी वे सरकार को अवगत कराएंगे. गौरतलब है कि जिलाधिकारी सुनील कुमार ने जिले में इंजीनियरिंग कॉलेज के निर्माण के लिए चानन स्थित घोषीकुंडी गांव में उक्त पहाड़ी के नजदीक सरकारी जमीन अधिगृहित करने का प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजा था. इसे पुरातत्व विभाग ने तकनीकी कारण बताकर जमीन अधिग्रहण पर रोक लगा दी थी.

इसके बाद जिला प्रशासन ने प्रस्तावित इंजीनियरिंग कॉलेज का निर्माण करवाने के लिए जिले के अन्य हिस्सों में सरकारी अथवा निजी जमीन की तलाश प्रारम्भ कर दी. इस बीच कई पंचायतों के प्रमुख और समाजसेवियों ने राज्य सरकार से घोषीकुंडी गांव में प्रस्तावित इंजीनियरिंग कॉलेज बनवाने की गुहार लगाई है.■

दांतों की सुन्दरता और आप

ariskon Pharma Pvt. Ltd.
An ISO 9001 : 2008 Certified Co.
डेन्टल केयर मील रोड, खगड़िया
डॉ. मनीष कुमार,(BDS)
FAGE, Certified Orthodontist

डॉ मनीष कुमार डेन्टल केयर, मील रोड, खगड़िया ने बातचीत के क्रम में बच्चों में होने वाले टेढ़ेमेढ़ेपन के बारे में बताया कि 12 साल तक विशेष ध्यान देने की जरूरत नहीं है लेकिन जैसे ही दूध के दांत खत्म होते हैं उसके बाद के दांतों को कैविटी से बचाना बहुत जरूरी हो जाता है इसलिए जब भी खाना खायें या टॉफी खायें, जंक फूड खायें जो कि मना है या फिर दूध पीयें अपने दांतों की बीच फंसे हुए पदार्थ को निकालना आवश्यक हो जाता है और इसके लिए दो टाईम ब्रशिंग के अलावा आपको चाहिए कि कुल्ला अंगुली मुंह में घुमाते हुए अवश्य करें। इनका मानना है कि नयें दांतों को बचाने के जरूरत होती है क्योंकि इसके बाद आपको नकली दांत ही मिलेंगे। इसलिए इनमें कैविटि न लगने दें। दांतों के टेढ़ेमेढ़े होने के बारे में उन्होंने बताया कि 12 साल बाद हम इसमें दो प्रक्रिया अपनाते हैं एक तो रिमूवल ऑर्थोडोन्टिस्ट तथा दूसरा फिक्स ऑर्थो डोन्टोस्टि प्रक्रिया अपनाते हैं। केविटी दूर रखने में निम्न भोजन सहायक होते हैं:- कैल्शियम-दूध और दूध से बनी चीजें जैसे दूध,दही और पनीर सोयाबीन, मूंगफली, सूरजमुखी के बीज और हरी सब्जियों में कैल्शियम काफी मात्रा में होता है। खाने में विटामिन सी अवश्य शामिल करें। दांतों के लिए विटामिन सी होना आवश्यक है। फाइबर- उच्च फाइबर खाद्य पदार्थ खाने से मुंह में लार पूरी मात्रा में बनती है जो दांत को केविटी से बचानें में मदद करती है। किशमिश, अंजीर, केले, सेब और संतरे जैसे ताजे फल और सूखे फल फाइबर के अच्छे स्रोत हैं। अन्य स्रोत जैसे सेम, मूंगफली, बादाम, चोकर और मटर आदि शामिल हैं। साबुत अनाज-साबुत अनाज में विटामिन बी और लौह तत्व प्रचुर मात्रा में होता हैं साबुत अनाज हड्डियों और दांतों के लिए मैग्नीशियम एक महत्वपूर्ण घटक है। चोकर, ब्राउन राइस साबुत अनाज का अच्छा स्रोत है। डॉ. मनीष ने कहा कि साल छः महिने में एक बार अवश्य आप दांतों के चिकित्सक से मिलकर जांच करवा लें।■ भारती

Carbo - XT Drops Susp.
Ferrous Ascorbate100 mg +
Folic Acid 1.5 mg +
Vitamine B5 mcg Tab.
A Colic Drops.
Simethocone Emulsion, Dil Oil Fennel Oil
Siliplex Syp.
Silymarin, vitamin B Complex
Calcuium & Lactic Acid Bacillus
Oflogyl-OZ Susp. (60 ml)
Ofloxacine 100 mg &
Omindazole 125 mg
Acoba Syp.
Methylocobalamine, Lycopene, Multivitamine
Multimineral & Antioxident
NOKSIRA Pharma Pvt.Ltd.
A Division of AriskonPharma

CRM
TMT BAR




ISO 9001 - 2000 Certified Co.
IS:1786:2008
CM/L-5746178
Fe-500
मुख्य खूबियाँ
• बचत
• मजबूती
• शानदार फिनीश
Mfg. : CITY ROLLING MILLS PVT. LTD., PATNA
HELPLINE : 0612-2216770

## अकेलेपन का अंडमान भोगते आडवाणी

# क्या आडवाणी अकेले में रोते हैं?

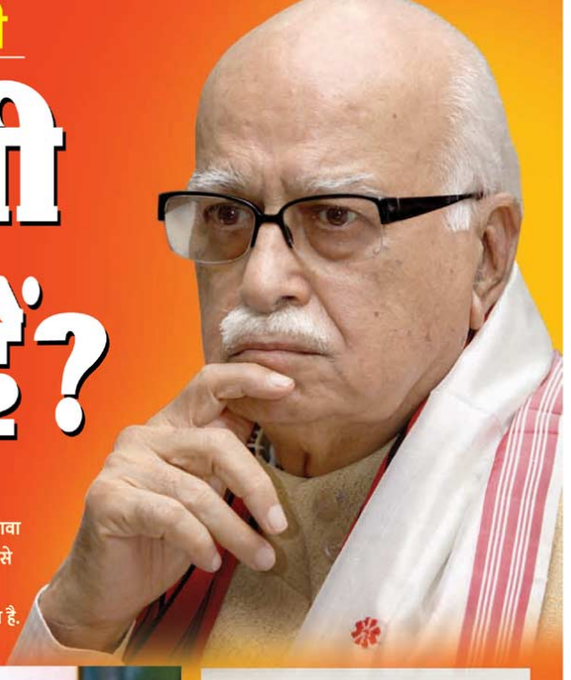

**क्या आडवाणी एकांत में रोते होंगे? सिसकते होंगे या कमरे में बैठे-बैठे कभी चीखने लगते होंगे, किसी को पुकारने लगते होंगे? बीच-बीच में उठकर अपने कमरे में चलने लगते होंगे, या किसी डर की आहट सुन कर वापस कुर्सी पर लौट आते होंगे? बेटी के अलावा दादा को कौन पुकारता होगा? क्या कोई मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री या साधारण नेता उनसे मिलने आता होगा? आज हर मंत्री नहाने से लेकर खाने तक की तस्वीर ट्वीट कर देता है. दूसरे दल के नेताओं की जयंती की तस्वीर भी ट्वीट कर देता है. उन नेताओं की टाइमलाइन पर सब होंगे मगर आडवाणी नज़र नहीं आएंगे. सबको पता है. अब आडवाणी से मिलने का मतलब आडवाणी हो जाना है.**

रवीश कुमार

लाल कृष्ण आडवाणी का एकांत भारत की राजनीति का एकांत है. हिन्दू वर्ण व्यवस्था के पितृपुरुषों का एकांत ऐसा ही होता है. जिस मकान को जीवन भर बनाता है, बन जाने के बाद ख़ुद मकान से बाहर हो जाता है. वो आंगन में नहीं रहता है. घर की देहरी पर रहता है. सारा दिन और कई साल उस इंतज़ार में काट देता है कि भीतर से कोई पुकारेगा. बेटा नहीं तो पतोह पुकारेगी, पतोह नहीं तो पोता पुकारेगा. जब कोई नहीं पुकारता है तो ख़ुद ही पुकारने लगता है. गला खखारने लगता है. घर के अंदर जाता भी है, लेकिन किसी को नहीं पाकर उसी देहरी पर लौट आता है. बीच बीच में संन्यास लेने और हरिद्वार चले जाने की धमकी भी देता है, मगर फिर वहीं डेरा जमाए रहता है.

पिछले तीन साल के दौरान जब भी आडवाणी को देखा है, एक गुनाहगार की तरह नज़र आए हैं. बोलना चाहते हैं मगर किसी अनजान डर से चुप हो जाते हैं. जब भी चैनलों के कैमरों के सामने आए, बोलने से नज़रें चुराने लगे. आप आडवाणी के तमाम वीडियो निकाल कर देखिए. ऐसा लगता है उनकी आवाज़ चली गई है. जैसे किसी ने उन्हें शीशे के बक्से में बंद कर दिया है. उसमें धीरे-धीरे पानी भर रहा है और बचाने की अपील भी नहीं कर पा रहे हैं. उनकी चीख बाहर नहीं आ पा रही है. उनके सामने से कैमरा गुज़र जाता है. आडवाणी होकर भी नहीं होते हैं.

आडवाणी का एकांत उस पुरानी कमीज़ की तरह है, जो बहुत दिनों से रस्सी पर सूख रही है, मगर कोई उतारने वाला भी नहीं है. बारिश में कभी भीगती है, तो धूप में सिकुड़ जाती है. धीरे धीरे कमीज़ मैली होने लगती है. फिर रस्सी से उतर कर नीचे कहीं गिरी मिलती है. जहां थोड़ी सी धूल जमी होती है, थोड़ा पानी होता है. कमीज़ को पता है कि धोने वाले के पास और भी कमीज़ है. नई कमीज़ है.

क्या आडवाणी एकांत में रोते होंगे? सिसकते होंगे या कमरे में बैठे-बैठे कभी चीखने लगते होंगे, किसी को पुकारने लगते होंगे? बीच-बीच में उठकर अपने कमरे में चलने लगते होंगे, या किसी डर की आहट सुन कर वापस कुर्सी पर लौट आते होंगे? बेटी के अलावा दादा को कौन पुकारता होगा? क्या कोई मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री या साधारण नेता उनसे मिलने आता होगा? आज हर मंत्री नहाने से लेकर खाने तक की तस्वीर ट्वीट कर देता है. दूसरे दल के नेताओं की जयंती की तस्वीर भी ट्वीट कर देता है. उन नेताओं की टाइमलाइन पर सब होंगे मगर आडवाणी नज़र नहीं आएंगे. सबको पता है. अब आडवाणी से मिलने का मतलब आडवाणी हो जाना है.

रोज़ सुबह उठकर वे एकांत में किसकी छवि देखते होंगे, वर्तमान की या इतिहास की. क्या वे दिन भर अख़बार पढ़ते होंगे या न्यूज़ चैनल देखते होंगे. फोन की घंटियों का इंतज़ार करते होंगे? उनसे मिलने कौन आता होगा? न तो वे मोदी-मोदी करते हैं न ही कोई आडवाणी-आडवाणी करता है. आखिर वे मोदी-मोदी क्यों नहीं करते हैं, अगर यही करना प्रासंगिक होना है तो इसे करने में क्या दिक्कत है? क्या उनका कोई निजी विरोध है, है तो वे इसे दर्ज क्यों नहीं करते हैं?

लोकसभा चुनाव से पहले आडवाणी ने एक ब्लॉग भी बनाया था. दुनिया में कितना कुछ हो रहा है. उस पर तो वे लिख ही सकते हैं. इतने लोग जहां तहां जाकर लेक्चर दे रहे हैं, वहां आडवाणी भी जा सकते हैं. नेतृत्व और संगठन पर कितना कुछ बोल सकते हैं. कुछ नहीं तो उनके सरकारी आवास में फूल होंगे, पौधे होंगे, पेड़ होंगे, उनसे ही उनका नाता बन गया होगा, उन पर ही लिख सकते थे. फिल्म की समीक्षा लिख सकते हैं. वे आडवाणी के अलावा भी आडवाणी हो सकते थे. वे होकर भी क्यों नहीं हैं!

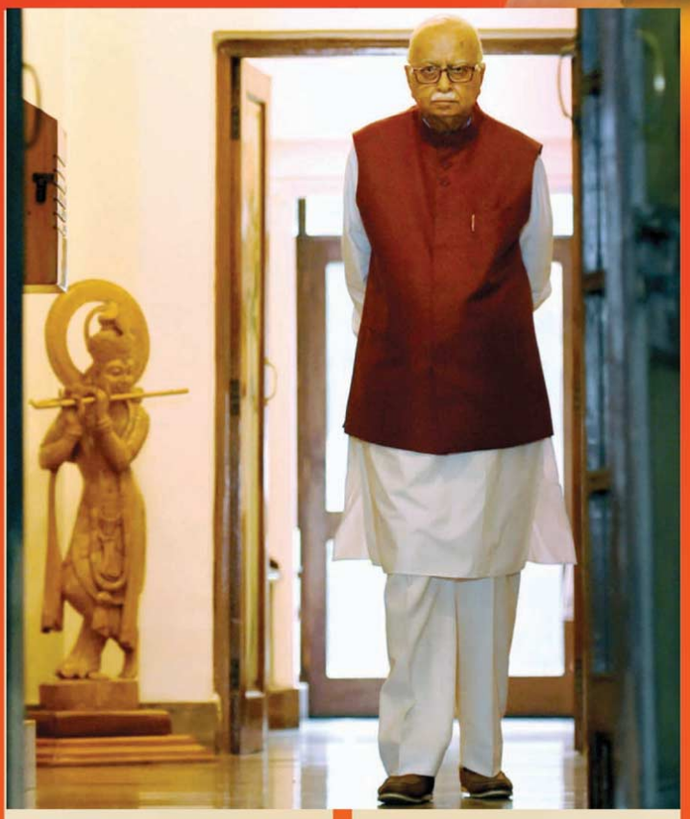

आडवाणी ने अपने निवास में प्रेस कांफ्रेंस के लिए बकायदा एक हॉल बनवाया था. तब अपनी प्रासंगिकता को लेकर कितने आश्वस्त रहे होंगे. उस हॉल में कितने कार्यक्रम हुए हैं. कहीं ऐसा तो नहीं कि वे दिन में एक बार उस हॉल में लौटते होंगे. कैमरे और सवालों के शोर सुनते होंगे. सुना है कुछ आवाज़ें दीवारों पर अपना घर बना लेती हैं. जहां वे सदियों तक गूंजती रहती हैं. क्या वो हॉल अब भी होगा वहां?

आडवाणी अपने एकांत के वर्तमान में ऐसे बैठे नज़र आते हैं जैसे उनका कोई इतिहास न हो. भाजपा आज अपने वर्तमान में शायद एक नया इतिहास देख रही है. आडवाणी उस इतिहास के वर्तमान में नहीं हैं. जैसे वो इतिहास में भी नहीं थे. वे दिल्ली में नहीं, अंडमान में लगते हैं. जहां समंदर की लहरों की निर्ममता सेलुलर की दीवारों से टकराती रहती है. दूर-दूर तक कोई किनारा नज़र नहीं आता है. कहीं वे कोई डायरी तो नहीं लिख रहे हैं? दिल्ली के अंडमान की डायरी!

सत्ता से वजूद मिटा कांग्रेस का, लेकिन नाम मिट गया आडवाणी का. सोनिया गांधी से अब भी लोग गाहे बगाहे मिलने चले जाते हैं. राष्ट्रपति के उम्मीदवार का नाम तय हो जाता है तो प्रधानमंत्री सोनिया गांधी को फोन करते हैं, जिनकी पार्टी से वो भारत को मुक्त कराना चाहते हैं. क्या उन्होंने आडवाणी जी को भी फोन किया होगा? आज की भाजपा आडवाणी मुक्त भाजपा है. उस भाजपा में आज कांग्रेस है, सपा है, बसपा है सब है. संस्थापक आडवाणी नहीं हैं. क्या किसी ने ऐसा भी कोई ट्वीट देखा है कि प्रधानमंत्री ने आडवाणी को भी राष्ट्रपति के उम्मीदवार के बारे में बताया है? क्या रामनाथ कोविंद मार्गदर्शक मंडल से भी मिलने जाएंगे? मार्गदर्शक मंडल, जिसका न कोई दर्शक है न कोई मार्ग.

भारतीय जनता पार्टी का यह संस्थापक विस्थापन की ज़िंदगी जी रहा है. वो न अब संस्कृति में है न ही राष्ट्रवाद के आख्यान में है. मुझे आडवाणी पर दया करने वाले पसंद नहीं हैं, न ही उनका मज़ाक उड़ाने वाले. आडवाणी हम सबकी नियति हैं. हम सबको एक दिन अपने जीवन में आडवाणी ही होना है. सत्ता से, संस्थान से और समाज से. मैं उनकी चुप्पी को अपने भीतर भी पढ़ना चाहता हूं. भारत की राजनीति में संन्यासी होने का दावा करने वाला प्रासंगिक हो रहे हैं और संन्यास से बचने वाले आडवाणी अप्रासंगिक हो रहे है. आडवाणी एक घटना की तरह घट रहे हैं. जिसे दुर्घटना के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए.

जिन लोगों ने यह कहा है कि विपक्ष आडवाणी को अपना उम्मीदवार बना दे, वो आडवाणी के अनुशासित जीवन का अपमान कर रहे हैं. उन्हें यह पता नहीं है कि विपक्ष की हालत भी आडवाणी जैसी है. आडवाणी के साथ क्रूरता उनके साथ सहानुभूति रखने वाले भी कर रहे हैं और जो उनके साथ हैं वो तो कर ही रहे हैं. आडवाणी का एक दोष है. उन्होंने ज़िंदा होने की एक बुनियादी शर्त का पालन नहीं किया है. वो शर्त है बोलना. अगर राजनीति में रहते हुए बोल नहीं रहे हैं तो वे भी राजनीति के साथ धोखा कर रहे हैं तब जब राजनीति उनके साथ धोखा कर रही है. उन्हें ज़ोर से चीखना चाहिए. रोना चाहिए ताकि आवाज़ बाहर तक आए. अगर बग़ावत नहीं है तो वो भी कहना चाहिए. कहना चाहिए कि मैं खुश हूं. मैं डरता नहीं हूं. वे चुप्पी मेरा चुनाव है. न कि किसी के डर के कारण है.

आडवाणी की चुप्पी हमारे समय की सबसे शानदार पटकथा है. इस पटकथा को क्लाइमेक्स का इंतज़ार है. कुहासे से घिरी दिल्ली के राजपथ पर एक सीधा तना हुआ बूढ़ा चला आ रहा है. लाठी की ठक-ठक सुनाई देने लगी है. वो क़रीब आता जा रहा है. उसके बग़ल से टैंकों का काफ़िला तेज़ी से गुज़र रहा है. सांस्कृतिक राष्ट्रवाद पर उनके दिए गए पुराने भाषण गूंज रहे हैं. टैंकों ने राष्ट्रवाद को संभाल लिया है और संस्कृति ने गाय. पितृपुरुष आडवाणी टैंकों के काफिले के बीच ठिठके से खड़े हैं. धीरे धीरे बोलने लगते हैं. ज़ोर ज़ोर से बोलने लगते हैं. रोने लगते हैं. मगर उनकी आवाज़ टैंकों के शोर में खो जा रही है. काफिला इतना लंबा है कि फिर चुप हो जाते हैं.

फिल्म का कैमरा टैंक से हटकर अब उस बूढ़े को साफ-साफ देखने लगता है. क्लोज़ अप में आडवाणी दिखते हैं. बीजेपी के संस्थापक आडवाणी. गुरुदत्त की शॉल ओढ़े हुए राजपथ पर क्या कर रहे हैं! ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, बाहें फैलाए हुए रायसीना हिल्स की तरफ देख रहे हैं. राष्ट्रपति का काफिला संसद की तरफ जा रहा है. लाल रंग की वर्दी में सिपाही घोड़ों पर बैठे हैं.

धीरे धीरे फ्रेम में एक शख़्स प्रवेश करता है. दीपक चोपड़ा. आडवाणी के रथ का सारथी. आडवाणी के एकांत का बेमिसाल साथी. दीपक चोपड़ा आडवाणी की तरफ देख रहे हैं. उनके पास डायरी है. उस डायरी में आडवाणी से मिलने के लिए समय मांगने वालों के नाम हैं. अब वही नाम इन दिनों किसी और से मिल रहे हैं. रायसीना हिल्स से एक रिपोर्टर भागता हुआ करीब आता है. दीपक जी, आप आडवाणी जी के साथ क्यों हैं? आप उन सबके साथ क्यों नहीं हैं जो इस वक्त संसद में हैं.

कैमरा दीपक चोपड़ा के चहरे पर है. उनके होंठ आधे खुले रह जाते हैं. आंखों में एक अंतहीन गहराई है. जिसकी खाई में सत्ता की एक कुर्सी टूटी पड़ी है. कुछ पुराने फ्रेम हैं जिसमें आडवाणी जी बड़े-बड़े नेताओं से मिल रहे हैं. हाथ जोड़े हुए हैं, आंखें बंद हैं और मुस्कुरा रहे हैं. हर फ्रेम में दीपक चोपड़ा हैं.

रिपोर्टर को जवाब मिल जाता है. वो अब दूसरा सवाल करता है, क्या आडवाणी जी अब भी बोलेंगे. क्या वे अकेले हैं. क्या वे रोते हैं. क्या वे दिन भर चुप रहते हैं. क्या उनसे कोई मिलने आता है. संस्थापक विस्थापन क्यों झेल रहा है. क्या ये सब कांग्रेस की साज़िश है? दीपक चोपड़ा चुप हैं.

इसी सीन पर डायरेक्टर कट कहता है मगर पैक-अप नहीं कहता. अपनी टीम से कहता है, इंतज़ार करो. देखो, यह बूढ़ा राजपथ से किस तरफ मुड़ता है, मुड़ता भी है या यहीं अनंत काल तक खड़ा रहता है. असिस्टेंट डायरेक्टर कहता है, सर, हम साइलेंस शूट करेंगे या साउंड? डायरेक्टर कहता है, साउंड शूट करना होता तो मैं संसद में होता जहां नए राष्ट्रपति का स्वागत हो रहा है, जहां नए-नए नारे लग रहे हैं. मैं साइलेंस शूट करने आया हूं. उस डर को कैप्चर करने जो इस वक्त आडवाणी जी के चेहरे पर है. वो डर ही उनकी चुप्पी है.

कैमरे के क्लोज़ अप में आडवाणी के ब्लॉग का पेज आ जाता है. उस पर लिखा है A MAN OF WORDS AND ACTION, सर फिल्म का यही टाइटल होगा क्या? नहीं. फिल्म का टाइटल होगा A MAN OF NO WORDS AND NO ACTION. ■

*लेखक जाने माने टीवी पत्रकार हैं*

feedback@chauthiduniya.com

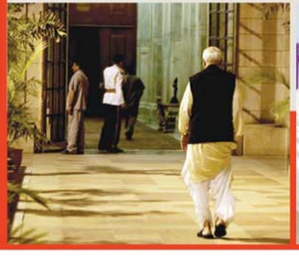

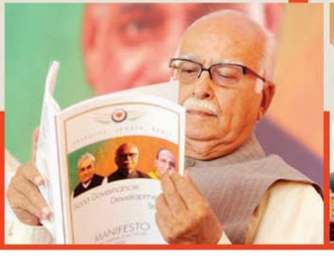

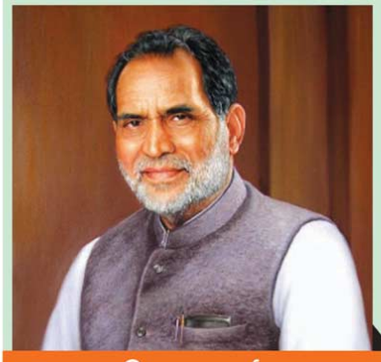

जन्मदिन- 1 जुलाई 1927
पुण्यतिथि- 8 जुलाई 2007

## पुण्यतिथि विशेष

# भारतीय राजनीति का 'युवा तुर्क'

चौथी दुनिया ब्यूरो

प्रधानमंत्री के रूप में अपने 8 महीने से भी कम समय के कार्यकाल में चंद्रशेखर ने नेतृत्व क्षमता और दूरदर्शिता की जो छाप छोड़ी, उसे हमेशा याद रखा जाएगा. चाहे बाबरी मस्जिद विवाद हो, कश्मीर मसला या पूर्वोत्तर की समस्याएं, चंद्रशेखर ने तमाम विवादित मुद्दों को स्पष्ट सियासी रणनीति के जरिए सुलझाने की कोशिश की. वे न सिर्फ एक लोकप्रिय राजनेता थे, बल्कि प्रखर वक्ता, विद्वान लेखक और बेबाक समीक्षक भी थे. उनके सियासी व्यक्तित्व को इस बात से भी समझा जा सकता है कि वे एक ऐसे नेता थे, जो सीधे प्रधानमंत्री बने. प्रधानमंत्री बनने से पहले उन्हें किसी भी मंत्रालय का कोई अनुभव नहीं था.

चन्द्रशेखर का जन्म 1 जुलाई 1927 को उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में इब्राहिम पट्टी गांव के एक किसान परिवार में हुआ था. वे अपने छात्र जीवन से ही राजनीति की ओर आकर्षित थे. 1950-51 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में मास्टर डिग्री करने के बाद वे समाजवादी आंदोलन से जुड़ गए. चंद्रशेखर बलिया में जिला प्रजा समाजवादी पार्टी के सचिव चुने गए. इसके बाद 1955-56 में वे उत्तर प्रदेश में राज्य प्रजा समाजवादी पार्टी के महासचिव बने. 1962 में वे उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के लिए चुने गए. इसके बाद जनवरी 1965 में चंद्रशेखर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हो गए. 1967 में उन्हें कांग्रेस संसदीय दल का महासचिव चुना गया. एक संसद सदस्य के रूप में उन्होंने समाज में हाशिए पर पड़े लोगों के लिए मुखरता से आवाज उठाई. इस संदर्भ में जब उन्होंने समाज में उच्च वर्गों के गलत तरीके से बढ़ रहे एकाधिकार का विरोध किया, तो सत्ता में बैठे कई नेताओं से उनके मतभेद भी हुए. लेकिन इस युवा तुर्क ने हमेशा ही दृढ़ता, साहस एवं ईमानदारी के साथ निहित स्वार्थ के खिलाफ लड़ाई लड़ी. चंद्रशेखर एक राजनेता से इतर पत्रकार भी थे. उन्होंने 1969 में यंग इंडियन नामक साप्ताहिक पत्रिका शुरू की, जो दिल्ली से प्रकाशित होती थी. इस पत्रिका के स्पष्टवादी लेखों के कारण आपातकाल के दौरान इसपर प्रतिबंध लगा दिया गया. हालांकि फरवरी 1989 से पुनः इसका नियमित प्रकाशन शुरू हुआ.

कहा जाता है, जब इंदिरा गांधी ने चंद्रशेखर से पूछा कि आपके जैसे मुखर समाजवादी आखिर कांग्रेस में आने को क्यों तैयार हुए, तो चंद्रशेखर का स्पष्ट जवाब था- मैं कांग्रेस के चाल, चरित्र और चेहरे को बदलने आया हूं. फिर जब इंदिरा गांधी ने पूछा कि अगर ऐसा सम्भव नहीं हुआ तो? इसपर चन्द्रशेखर का जवाब था, फिर मैं कांग्रेस को तोड़ दूंगा. चन्द्रशेखर ने हमेशा ही व्यक्तिगत राजनीति के खिलाफ रहकर वैचारिक एवं सामाजिक परिवर्तन की राजनीति का समर्थन किया. यही कारण भी था कि 1973-75 के दौर में जब कांग्रेस संगठन पर इंदिरा गांधी हावी हो गई थीं, तब चंद्रशेखर जयप्रकाश नारायण के विचारों के करीब आए. इस वजह से वे जल्द ही कांग्रेस पार्टी के भीतर असंतोष का कारण बन गए. ये बात स्पष्ट रूप से तब सामने आ गई, जब कांग्रेस के शीर्ष निकायों, केंद्रीय चुनाव समिति तथा कार्य समिति का सदस्य होने के बावजूद आपातकाल के दौरान चंद्रशेखर को गिरफ्तार किया गया. 25 जून 1975 की रात जब उन्हें गिरफ्तार किया गया, उस समय वे संसद भवन थाने से जयप्रकाश नारायण से मिलकर निकल रहे थे. आपातकाल के दौरान जेल में उन्होंने एक डायरी लिखी थी, जो बाद में मेरी 'जेल डायरी' के नाम से प्रकाशित हुई. 'सामाजिक परिवर्तन की गतिशीलता' उनके लेखन का एक प्रसिद्ध संकलन है.

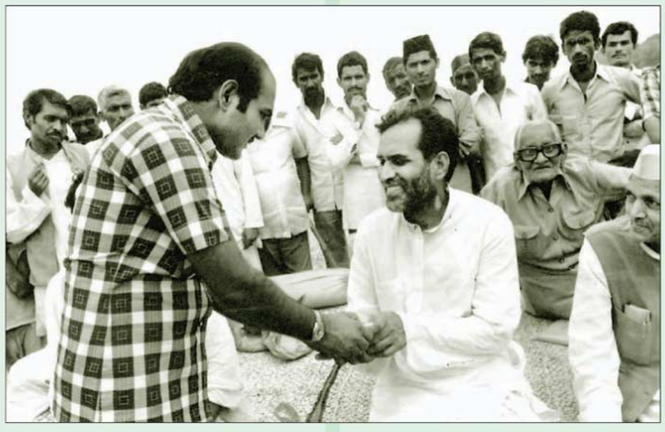

आपातकाल के दौरान ही जब चुनाव की घोषणा हुई और जनता पार्टी का विधिवत गठन हुआ, तो रामलीला मैदान में हुई जनता पार्टी नेताओं की सभा में चंद्रशेखर को पार्टी का अध्यक्ष चुना गया. चंद्रशेखर की सियासी स्वीकार्यता को इस बात से समझा जा सकता है कि उनका मोरारजी देसाई से मतभेद था, लेकिन फिर भी अध्यक्ष पद के लिए मोरारजी देसाई ने ही उनके नाम की घोषणा की. 24 मार्च, 1977 को मोरारजी देसाई के नेतृत्व में केंद्र में जनता पार्टी की सरकार बनी. उस समय तमाम बड़े नेता सरकार में मंत्री बनने के लिए मशक्कत करते दिखे. चंद्रशेखर को भी मंत्री बनने का प्रस्ताव था, जेपी ने भी उन्हें मंत्रिमंडल में शामिल होने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने स्वीकार नहीं किया. चंद्रशेखर ने प्रस्ताव इसलिए ठुकराया, क्योंकि मोरारजी देसाई से उनका मतभेद था और वे ऐसा मानते थे कि कैबिनेट प्रणाली में प्रधानमंत्री से मतभेद रह कर मंत्रिमंडल में शामिल होना उचित नहीं है. ये बात उन्होंने जेपी को भी बताई थी और मोरारजी देसाई को भी. चंद्रशेखर भले ही सरकार में शामिल नहीं हुए, लेकिन पार्टी अध्यक्ष के रूप में जनता पार्टी को लोकतांत्रिक बनाने में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. खींचतान के बावजूद वे पार्टी में समरसता और समन्वय बनाने की दिशा में काम करते रहे. हालांकि 1979 में ही जनता पार्टी टूट गई थी. चंद्रशेखर 1977 से 1988 तक जनता पार्टी के अध्यक्ष रहे. इस दौरान उन्होंने उन्होंने भारत यात्रा की. सामाजिक एवं राजनीतिक कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करने के उद्देश्य से उन्होंने केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश एवं हरियाणा सहित देश के विभिन्न भागों में लगभग पंद्रह भारत यात्रा केंद्रों की स्थापना की. इसके पीछे उनका उद्देश्य ये था कि देश के पिछड़े इलाकों में लोगों को शिक्षित व जागरूक किया जा सके, ताकि वे जमीनी स्तर पर कार्य कर सकें. इससे पहले 6 जनवरी 1983 से 25 जून 1983 तक चंद्रशेखर ने दक्षिण के कन्याकुमारी से नई दिल्ली में महात्मा गांधी की समाधि राजघाट तक लगभग 4,260 किलोमीटर की पदयात्रा की. इस पदयात्रा के दौरान वे लोगों से मिले एवं उनकी महत्वपूर्ण समस्याओं को समझा.

1984 से 1989 तक की संक्षिप्त अवधि को छोड़ कर 1962 से वे संसद के सदस्य रहे. 1989 में उन्होंने अपने गृह क्षेत्र बलिया और बिहार के महाराजगंज संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ा एवं दोनों ही चुनाव जीते. बाद में उन्होंने महाराजगंज की सीट छोड़ दी. विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार के गिरने और जनता दल में फूट के बाद कांग्रेस के समर्थन से चंद्रशेखर 10 नवंबर 1990 को भारत के ग्यारहवें प्रधानमंत्री बने. वे जब प्रधानमंत्री बने उस समय देश मंदिर और मंडल की आग में जल रहा था. चंद्रशेखर की पहली प्राथमिकता थी, स्थिति सामान्य करना. राम मंदिर विवाद को लेकर जब विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने उनके पास संदेश भेजा कि वे मिलना चाहते हैं, तो प्रधानमंत्री चंद्रशेखर का जवाब था कि तुरंत आ जाइए. लेकिन जब विश्व हिंदू परिषद वाले मिलने नहीं आ सके, तो चंद्रशेखर खुद ही उनकी बैठक में पहुंच गए. वे इस विवाद को सुलझाने के करीब पहुंच गए थे, लेकिन उन्हें प्रधानमंत्री के रूप में पर्याप्त समय नहीं मिल पाया. कांग्रेस द्वारा समर्थन वापस लेने के बाद चंद्रशेखर ने 5 मार्च 1991 को अपने पद से इस्तीफा दे दिया. राम मंदिर विवाद के अलावा कश्मीर, पंजाब में पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद और उत्तर-पूर्व के उग्रवाद को लेकर भी चंद्रशेखर सरकार ने कई निर्णायक कदम उठाए थे. ऐसा कहा जाता है कि अगर चंद्रशेखर की सरकार पूरे एक साल भी चली होती तो इन तमाम विवादित मुद्दों की स्थिति आज कुछ और होती. दिल्ली में 8 जुलाई 2007 को ये ओजस्वी आवाज और दुरदर्शी आंखें हमेशा के लिए बंद हो गईं, लेकिन भारतीय राजनीति में इस युवा तुर्क का योगदान हमेशा याद रखा जाएगा.■

feedback@chauthiduniya.com

# सभ्यता के संरक्षण के लिए ज़रूरी है नदी का संवर्धन

चौथी दुनिया ब्यूरो

प्राचीन काल में सभ्यता के विकास से लेकर वर्तमान में देश और समाज के संवर्धन तक, नदियां हमारे विकास का एक प्रमुख आधार रही हैं. लेकिन आज ज्यादातर नदियां अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रही हैं. हाल ही में आई संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट बताती है कि दुनिया भर की 227 बड़ी नदियों में से 136 नदियों में पानी का बहाव थम रहा है. संयुक्त राष्ट्र की इस सूची में भारत की लगभग सभी प्रमुख नदियां हैं. हमारी मौसमी छोटी नदियां तो कब की खत्म हो चुकी हैं, बड़ी नदियां भी अब अपनी पहचान से जूझ रही हैं. इनमें पानी नहीं है. 2006 में नर्मदा का जल-स्तर 323 मीटर था, जो लगातार नीचे गिर रहा है. बेतवा, केन, चंबल के भी यही हालात हैं. इनमें भी पानी का बहाव दिन-ब-दिन खत्म होता जा रहा है.

पानी के लिए पहचानी जाने वाली नदियों से पानी विहिन होते जाने का मुख्य कारण है, इन पर बनने वाले बड़े-बड़े बांध और इनके किनारे के निर्माण. बांधों के कारण डाउन स्ट्रीम में पानी की कमी होती जा रही है. ऐसे बांधों के आस-पास के 10-15 किमी नदी क्षेत्र में जलीय जीवन समाप्त हो रहा है. इनके कारण नदियों का स्वयं शुद्धीकरण तंत्र भी नष्ट होता जा रहा है. इसके साथ-साथ नदियों में बहाए जाने वाले कंपनियों-कारखानों के अवशिष्ट भी इनके बहाव में बाधक बन रहे हैं. नदियों के बहाव मार्ग में भारी मात्रा में गाद का पटाव पानी की गुणवत्ता खत्म करने के साथ-साथ नदियों के इकोसिस्टम को भी चौपट कर रहा है.

जलभराव और बहाव के बिना नदियां मर रही हैं. जल के सतत प्रवाह के कारण ही नदियों में ऑक्सीजन बना रहता है. बहाव नहीं होने के कारण पानी में ऑक्सीजन की कमी नदियों के जलीय पारिस्थितिकी को नष्ट कर रही है.

हमें इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि नदियां जीवित रहीं, तभी वो जनजीवन को भी आबाद कर सकेंगी. एशिया और अमेरिका के घनी आबादी वाले क्षेत्रों से होकर बहने वाली नदियों पर दुनिया की एक तिहाई आबादी निर्भर है. ये नदियां ही उनकी आजीविका और पेयजल का माध्यम हैं. 1999 तक 31 देशों के 45 करोड़ लोग पानी के लिए तरसते थे. लेकिन जल व्यवस्थाओं के प्रति लापरवाह रवैया 2035 तक 43 देशों की एक अरब आबादी के लिए नई मुसीबत बनकर आएगा. एक अनुमान के मुताबिक 2025 तक भारत सहित 48 देशों में पीने योग्य पानी नहीं होगा. पानी की प्रति व्यक्ति उपलब्धता जो 1950 में 6008 घनमीटर प्रति व्यक्ति प्रतिवर्ष थी, वो अब घटकर 1200-1400 घनमीटर नीचे जा चुकी है. ये एक भयावह स्थिति का संकेत है.

ये चिंताजनक बात है कि हमारे देश में नदियों का संरक्षण और संवर्धन कभी भी ज्वलंत मुद्दा नहीं बन सका, जबकि नदियों के अस्तित्व पर खतरा सबसे विकराल स्थिति है. अकाल और सूखे के समय जब पानी को लेकर हाहाकार मचता है, तो सरकारें एक्शन मोड में दिखती हैं, लेकिन फिर कुछ दिनों बाद स्थिति जस की तस हो जाती है. सूखने के कगार पर पहुंच चुकी नदियों को पुनर्जिवित करने के उद्देश्य से 1977 में मोरारजी देसाई की सरकार ने नदियों को आपस में जोड़ने का काम शुरू किया था. लेकिन सरकार बदलने के बाद 1982 में इस योजना को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया. इसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने 1999 में इस योजना को पुनर्जीवित करना चाहा और इसके लिए प्रयास किया. लेकिन वे इसके लिए कोई काम शुरू कर पाते उससे पहले ही 2004 में उनकी सरकार चली गई. तब से अब तक नदियों को जोड़ा जाना बस चुनावी मुद्दा बनकर रह गया है. हाल ही में दिल्ली में आंदोलनरत तमिलनाडु के किसानों का एक प्रमुख मांग नदियों को जोड़ा जाना भी था.

भारत में अब तक की सरकारें नदियों के संरक्षण व संवर्धन को लेकर कितनी जागरूक रही हैं, इसे गंगा और यमुना के हाल से जाना जा सकता है. गंगा की सफाई को लेकर अब तक हजारो करोड़ रुपए बहाए जा चुके हैं, लेकिन तब भी गंगा के बहाव को सुचारू नहीं किया जा सका है. देश की राजधानी दिल्ली में यमुना नाले में तब्दील हो चुकी है, लेकिन इसकी स्थिति बेहतर करने की बात फाइलों से निकलकर जमीनी रूप अख्तियार नहीं कर पा रही. नदियों के तरफ गौर न करने के कारण ही आज सरस्वती बस नाम की नदी बनकर रह गई है. गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, कावेरी, सिंधु, महानदी, तुंगभद्रा जैसी कई नदियां देश के अलग-अलग क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था और विकास का मेरुदंड हैं, लेकिन अब ये खुद को बचाए रखने की जंग लड़ रही हैं. हालांकि नदियों को पुनर्जिवित करना मुश्किल काम भी नहीं है. लंदन की टेम्स और वाडले इसका सबसे बेहतर उदाहरण है कि अगर इच्छा शक्ति हो, तो खत्म होने के कगार पर खड़ी नदी को भी पुनर्जिवित किया जा सकता है.■

feedback@chauthiduniya.com

## सलमान ने मुझे कभी नुकसान नहीं पहुंचाया: सोहेल खान

लंबे समय बाद सोहेल और सलमान खान एक बार फिर ट्यूबलाइट फिल्म में भाई के किरदार में नज़र आएंगे. उनकी बॉन्डिंग-केमिस्ट्री की तारीफें अभी से हो रही हैं. सोहेल खान से एक सवाल पूछा गया था कि सलमान की वजह से उनके करियर में कितनी दिक्कतें हुई? इसके जवाब में सोहेल ने कहा कि सलमान खान ने उन्हें कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचाया है. वो जैसे हैं, खुद की वजह से हैं. अक्सर कहा जाता है कि सोहेल और अरबाज़ का करियर केवल इसलिए नहीं चला क्योंकि उन पर सलमान खान के भाई होने का प्रेशर था. सलमान का स्टारडम उनका करियर खा गया. लेकिन इन बातों को नकारते हुए सोहेल ने कहा कि उन्हें नहीं लगता कि सलमान का स्टारडम कभी उन पर हावी हुआ है. ये बात, उन्होंने काफी विद करण में भी खुलकर बोली थी.■



# शाहरूख खान ने क्यों कहा ख़ुद को छिछोरा!

इस साल जनवरी में उनकी फिल्म रईस ने जब बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ सौ करोड़ से ज्यादा का कारोबार किया और फिल्म सुपरहिट रही, तो उनके विरोधियों का मुंह बंद हो गया. इसके बाद किंग खान ने सभी को ये बता दिया कि उनको बॉलीवुड का किंग खान कोई ऐसे ही नहीं कहा जाता. शाहरूख खान अपने करियर में लगभग हर तरह के किरदार निभा चुके हैं. फिर वह चाहे रोमांटिक किरदार हो या फिर विलेन, वे सभी किरदारों को बखूबी निभा लेने में माहिर हैं.

टीज़र में अनुष्का और शाहरूख एक होटल के कमरे में बंद हैं. शाहरूख अनुष्का को बता रहे हैं कि वो चीप हैं, यानि औरतों को गंदी नज़र से देखने वाले इंसान हैं. अनुष्का मानने को तैयार नहीं है. इस सीन को देखकर आपको जब वी मेट का डीसेंट होटल वाला सीन ज़रूर याद आएगा. जब शाहिद और करीना रेप पर डिस्कस करते हैं और शाहिद का मानना होता है कि करीना उन्हें रेप के लिए चाभी लगा रही हैं.

प्रवीण कुमार

बॉलीवुड के किंग खान और रोमांस करने में माहिर शाहरूख खान का जलवा एक बार फिर देखने को मिल रहा है. किंग खान एक समय तीनों खानों में बॉलीवुड पर सबसे टॉप पर थे, लेकिन बीच में उनकी दो फिल्में फैन और दिलवाले ने उनकी स्टारडम पर ग्रहण लगा दिया. इन दोनों फिल्मों की वजह से शाहरूख, सलमान और आमिर खान से पीछे हो गए. फिल्म समीक्षकों ने भी यह कयास लगाना शुरू कर दिया कि शाहरूख का जलवा अब पहले की तरह नहीं रहा है. इस साल जनवरी में उनकी फिल्म रईस ने जब बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ सौ करोड़ से ज्यादा का कारोबार किया और फिल्म सुपरहिट रही, तब उनके विरोधियों का मुंह बंद हो गया. इसके बाद किंग खान ने सभी को ये बता दिया कि उनको बॉलीवुड का किंग खान कोई ऐसे ही नहीं कहा जाता है.

शाहरूख खान अपने करियर में लगभग हर तरह के किरदार निभा चुके हैं. फिर वह चाहे रोमांटिक किरदार हो या फिर विलेन का रोल, वे सभी किरदार को निभाने में माहिर हैं. शाहरूख इस समय थोड़ा हटकर किरदार निभाना चाहते हैं. उनका यह सपना इम्तियाज़ अली की फिल्म *जब हैरी मेट सेजल* में पूरा होने वाला है. जी हां, फिल्म का टाइटल शाहिद-करीना की *जब वी मेट* से लिया गया. लेकिन इम्तियाज़ अली की यह फिल्म उस फिल्म से एक दम अलग होगी. फिल्म में किंग खान का साथ अनुष्का शर्मा देंगी.

फिल्म *जब हैरी मेट सेजल* का टीज़र देखने के बाद किंग खान के फैंस बेसब्री से उनकी इस फिल्म का इंतजार कर रहे हैं. शाहरूख इस फिल्म में एक छिछोरे की भूमिका करते नज़र आ रहे हैं, जिसे लोगों ने काफी पसंद किया. उम्मीद लगाई जा रही है कि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफलता के झंडे गाड़ने में कामयाब रहेगी और नए कीर्तिमान स्थापित करेगी. टीज़र में अनुष्का और शाहरूख एक होटल के कमरे में बंद हैं. शाहरूख अनुष्का को बता रहे हैं कि वो चीप हैं, यानि औरतों को गंदी नज़र से देखने वाले इंसान हैं. लेकिन अनुष्का मानने को तैयार नहीं है. इस सीन को देखकर आपको *जब वी मेट* का डीसेंट होटल वाला सीन ज़रूर याद आएगा. जब शाहिद और करीना रेप पर डिस्कस करते हैं और शाहिद का मानना होता है कि करीना उन्हें रेप के लिए चाभी लगा रही हैं. बहरहाल यह तो तय है कि *जब हैरी मेट सेजल* में शाहरूख खान का ये अंदाज लोगों को काफी पसंद आने वाला हैं. क्योंकि शाहरूख जब छिछोरापन करते है तो उनके फैंस उन्हें पसंद करते हैं.

इम्तियाज़ अली की रोमांटिक फिल्मों में अगर प्यार में कन्फ्यूजन ना हो, तो कहा जाता है कि उनकी फिल्म पूरी ही नहीं होती है. यही उनकी हर फिल्म का कॉमन पॉइंट होता है-प्यार और कन्फ्यूज़न! तो इस फिल्म में भी शाहरूख और अनुष्का में प्यार का कन्फ्यूजन आपको जरूर देखने को मिलेगा. हालांकि इससे पहले उनकी रणबीर-दीपिका की फिल्म *तमाशा* ने बॉक्स ऑफिस पर कुछ ख़ास कमाल नहीं दिखाया. लेकिन उनको फिल्म *जब हैरी मेट सेजल* से काफी उम्मीदें हैं. उन्हें पूरी उम्मीद है कि यह सुपरहिट फिल्मों में जरूर शामिल होगी. इम्तियाज़ अली की कहानियों में हीरोइन अक्सर केंद्र में होती है. इस बार भी ऐसा होना तय है. अब देखना है कि शाहरूख के साथ अनुष्का को कितनी तरजीह मिलती है. फिल्म 4 अगस्त को रिलीज़ हो रही है. पहले ये अक्षय कुमार की टॉयलेट एक प्रेम कथा के साथ क्लैश हो रही थी. बाद में दोनों पक्षों ने बातचीत करके इसका हल निकाला और इस क्लैश को टाल दिया, ताकि दोनों फिल्मों की कमाई पर इसका कोई असर ना पड़े.■

## शाहरूख ने की करियर में सात ग़लतियां

शाहरूख खान ने अपने करियर की शुरुआत फिल्म दीवाना में ऋषि कपूर और दिव्या भारती के साथ सहअभिनेता के तौर पर की थी. उनकी यह पहली फिल्म हिट साबित हुई. इसके बाद उन्होंने फिल्म बाज़ीगर, डर और अंजाम जैसी सुपरहिट फिल्मों में अपने निगेटिव रोल से तहलका मचा दिया था. किंग खान ने अपने करियर में एक से बढ़कर एक हिट फिल्में दी हैं. करीब 70 से ज्यादा फिल्मों में काम कर चुके शाहरूख खान के अवॉर्ड की बात की जाए, तो एक लंबी लिस्ट तैयार करनी पड़ेगी. हो भी क्यों ना, आख़िर वे बॉलीवुड के बादशाह जो ठहरे.

लेकिन आपको सुनकर अजीब लगेगा कि किंग खान ने भी करियर में कई बड़ी गलतियां की हैं, जो उन्हें शायद नहीं करनी चाहिए थी. जी हां, किंग खान ने अपने करियर में कई ऐसी बड़ी फिल्मों को रिजेक्ट किया है, जो बाद में ज्यादातर ब्लॉकबस्टर साबित हुई हैं. अब सोचने वाली बात यह है कि अगर ये फिल्में भी बादशाह के नाम दर्ज हो जातीं, तो बॉलीवुड में उनका मुकाबला शायद ही कोई कर पाता. आइए जानते हैं किंग खान की वे सात सबसे बड़ी गलतियां, जो उनको नहीं करनी चाहिए थी.

1 **3 इडियट्स :** विधु विनोद चोपड़ा मुन्ना भाई एमबीबीएस और मुन्ना भाई 2 के बाद चेतन भगत की किताब फाइव प्वाइंट समवन पर फिल्म बना रहे थे और इस बार वे किंग खान को लेना चाहते थे. लेकिन किसी वजह से दोनों में बात नहीं बन पाई और शाहरूख खान की जगह आमिर खान ने ले ली. 3 इडियट्स ने उस साल कई अवॉर्ड अपनी झोली में डाल लिए थे.

2 **जोधा अकबर :** शायद ज्यादा लोग इस बात को नहीं जानते होंगे, लेकिन स्वदेश फिल्म के बॉक्स ऑफिस पर ज्यादा न चल पाने के बावजूद आशुतोष गोवारिकर जोधा अकबर में भी लीडिंग रोल में किंग खान को लेना चाहते थे. लेकिन किंग खान फिल्म की लोकेशन को लेकर खुश नहीं थे. उन्होंने कहा कि इस फिल्म की वजह से वे अपने बच्चों के साथ ज्यादा वक्त नहीं बिता पाएंगे. नतीजा यह हुआ कि फिल्म ऋतिक की झोली में आ गिरी. इस फिल्म के लिए ऋतिक को बाद में फिल्मफेयर, आइफा, गिल्ड, स्टारडस्ट की ओर से बेस्ट एक्टर का अवॉर्ड दिया गया.

3 **लगान :** आशुतोष गोवारिकर ने शुरुआत में आमिर खान से फिल्म प्रोड्यूस करने की इच्छा जताई, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया. बाद में वे इस फिल्म को शाहरुख के पास लेकर गए तो उन्होंने भी मना कर दिया. आशुतोष दोबारा आमिर के पास गए और इस बार वे मान गए. लगान ने ऑस्कर तक का सफर तय किया. इसके साथ ही उस साल कई अवॉर्ड अपनी झोली में डालने का भी एक रिकॉर्ड बना डाला.

4 **कहो ना प्यार है :** किंग खान शुरू से ही राकेश रोशन के फेवरेट रहे हैं. फिल्म कोयला जब बॉक्स ऑफिस पर नहीं चल पाई तो उन्होंने फिल्म *कहो ना प्यार* है के लिए सबसे पहले शाहरुख खान को ही लिया था. लेकिन बात कुछ बनी नहीं, तब जाकर राकेश रोशन ने इस फिल्म में अपने बेटे को हीरो की भूमिका में उतारा. इसके बाद इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर जो हंगामा मचाया, वह बॉलीवुड के इतिहास में आज भी यादगार है. इस फिल्म ने उस साल अवॉर्ड के मामले में गिनीज़ बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाया हुआ है. उस दौरान फिल्म ने लगभग 95 अवॉर्ड अपने नाम किए थे.

5 **मुन्ना भाई एमबीबीएस :** इस फिल्म के डायरेक्टर व प्रोड्यूसर की पहली पसंद शाहरुख थे. असल में संजय दत्त को ज़हीर का रोल मिलने वाला था, जो आख़िर में जिम्मी शेरगिल ने किया. पर शाहरुख की डेट्स की सेटिंग नहीं बैठ पाने के कारण लीडिंग रोल के लिए संजय ने हामी भर दी. फिल्म सुपरहिट रही, जिसके बाद पार्ट-2 भी बनाया गया और यह फिल्म भी सुपरहिट रही.

6 **रंग दे बसंती :** राकेश ओमप्रकाश मेहरा की क्लास फिल्म रंग दे बसंती में काम करने के लिए पहले शाहरुख खान को ऑफर दिया गया था, लेकिन किंग खान ने अपने करियर में फिर से वही गलती कर दी और उन्होंने इस फिल्म को करने से मना कर दिया. आखिरकार आमिर खान ने यह फिल्म की, जो सुपरहिट रही.

7 **रोबोट :** तमिल डायरेक्टर शंकर रोबोट फिल्म के लिए शाहरुख को लेना चाहते थे, लेकिन बाद में यह फिल्म रजनीकांत की झोली में जाकर गिरी. क्यों, कैसे अब ये पूछना बेवकूफी होगी. इस फिल्म को एक बड़ी हिट में शामिल किया गया है.